

**DUE DATE SLIP**

## GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# राजस्थान में राजनैतिक जन-जागरण

लेखक

डा० के० प्र० सक्सेना

राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय महाविद्यालय,

जयपुर



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

जयपुर—४

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय, भारत सरकार की  
विश्वविद्यालय ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत राजस्थान  
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित :

प्रथम संस्करण—१९७२

मूल्य ७ ००

© राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर-४

मुद्रक—

ग्रणिमा प्रिन्टर्स

पुलिस मेमोरियल

जयपुर—४

## विषय-सूची

१ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चेतना का आधुनिक	१—१७
२ १८१७ का विप्लव और राजस्थान	१८—३५
३ सुधारों का युग और राजनैतिक चेतना का विकास	३६—४८
४ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राजस्थान में काठिकारी आंदोलन (१८८५—१९२४)	४९—७०
५ भीम-आंदोलन	७१—७८
६ राजस्थान में राजनैतिक आंदोलन और राजनैतिक संस्थाओं की स्थापना (१९२५—१९३९)	७९—१०१
७ जामखण्ड और एकीकरण (१९३९—४७)	१०२—१२१
८ अन्तर्द्वार	१२२—१२५

## प्रस्तावना

भारतीय भाषाओं की उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की राष्ट्रीय नीति की शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए सन् १९६५ में भारत सरकार ने एक बृहत् योजना का कूटपात किया था जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों में ग्रन्थ भण्डारणियों की स्थापना कर उनके माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षा-स्तर पर विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पुस्तकों के मौलिक लेखन और ग्रन्थ भाषाओं से अनुवाद करने का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ था। भारत सरकार के विद्या एवं बुद्धि सेवा मन्त्रालय ने बहुतों पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसके लिए गत प्रविष्टि अनुदान भीकाट किया। राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी की स्थापना भी इसी उद्देश्य की पूर्ति एवं योजना को क्रियान्वित करने के लिए की गई है। अस्तुतः ग्रन्थ 'राजस्थान में 'राजनैतिक जन-जागरण' का प्रकाशन भी इसी योजना के अन्तर्गत हुआ है।

राजस्थान की भूमि दो सदियों से वीर प्रभुता भूमि बनने का सीमावर्ष मिलता रहा है। महा के वीरों ने अपने आदर्शों एवं स्वाधीनता प्राप्ति के लिए हथेली-हथेली अपने प्राण नीडावर किए हैं। यज्ञों से पूर्व धरम, सुकं एवं मुगल बादशाहों से लोहा लेन वाले उदयपुर एवं ओझपुर के राजपरानों का नाम इति-हाम ने पृष्ठों पर स्वर्णश्रियों से अंकित है। जब अंग्रेज भारत के अधिपति बन गए तब उन्हें भी हमारे देश से निष्कामित करते थे भारत के ग्रन्थ प्राप्ति के समान ही राजस्थान के स्वतन्त्रता-सेनानियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। लेकिन राजस्थान के सेनानियों के लिए एक साथ दो कठिनों से मुकाबला करना होता था जिनमें प्रथम रियासतों के शासक एवं दूसरे अंग्रेज। इतना होते हुए भी राजस्थान में पूर्ण रूप से 'राजनैतिक चेतना जागृत हुई, परिणाम-

## प्रस्तावना

स्वरूप १५ अगस्त, १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्ति के अवसर पर राजस्थान की देशी रियासतों भी भारतीय सघ में विलीन होकर भारत का एक अभिन्न घग बन गई ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक डॉ० कृष्णस्वरूप सकमेना ने इस ग्रन्थ को राष्ट्रीय सघहालय, नई दिल्ली एवं राजकीय सघहालय बीकानेर तथा ग्रन्थ प्रामाणिक सामग्री के साधार पर तैयार किया है । हमें विश्वास है कि यह ग्रन्थ ग्रन्थापको एवं विद्याविगो के अनिरिक्क जन-साधारण के लिए भी सपयोगी होगा ।

नारायणसिंह मसुदा

मध्यघ, हिन्दो ग्रन्थ सकादमी

एव

शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।

---

## प्रावकथन

स्वतन्त्रता उपहार के रूप में प्राप्त नहीं होनी, वह त्याग और बलिदान माहती है। पारिवाक से ही राजस्थान का इतिहास त्याग, बलिदान और वीरता की कहानी रहा है जहाँ मानृधूमि के लिए माना सर्वस्व मोछावर कर देना एक परम्परा रही है। विशेषतः (उदयपुर) और मारवाड (मेरपुर) द्वारा अरर, रूर्ह मृग्य और बाद में मरेषों के विरुद्ध जो लोहा लिया गया वह निरुध ही राजस्थान की अन्ध रियासतों व जलता के निर्ण युगों तक वैरणा प्रदान करता रहा।

भारत के अन्य प्रान्तों के समान ही राजस्थान की जनता ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप से योगदान दिया था, जब ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की बेगनी धारा बही तो राजस्थान की जनता को बलुता न रहा सका। परन्तु राजस्थान की जनता को अपने अधिकारों की रक्षा और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए लोहा खर्च करना पडा। प्रथमतः ऐसी शिवायतों के निरुध राजाशा और जमीनारों के विरुद्ध उनके अत्याचारों से मुक्ति प्राप्ति करना कोई सामान काम नहीं था और दूसरे ब्रिटेन के विरुद्ध विरुद्ध इन कामों पर बरदहस्य था। समन त्याग, बलिदान और जन-आवरण के जन-स्वल्प अन्य प्रान्तों के समान ही राजस्थान की देशी रियासतों में भी 'लोकनिव एव उतरदायी सरकारें' पदाब्द हुई और जब १२ अगस्त, १९४७ को अया की प्रथम किरण ने भारत के मान पर स्वतन्त्रता का निलक दिया तो राजस्थान की देशी रियासतों को भारतीय मन में विलीन होकर भारत का एक समिन्न अंग बन गई।

प्रस्तुत पुस्तक में १८५७ की क्रांति से १९४७ तक राजस्थान में हुए

## प्राक्कथन

राजनैतिक मान्दोत्तन एवं राजनैतिक जन जागरण की विवेचना की गई है । यह प्रथम अवसर है जब कि १८५७ से १९४७ तक के राजस्थान में राजनैतिक जन-जागरण के इतिहास की प्रस्तुत किया गया है । ग्रन्थ है राष्ट्रीय जन-जागरण एवं मान्दोत्तन के इतिहास में रुचि रखने वाले विद्वानों, युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी ।

मैं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ समिती का आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक को प्रकाशनार्थ स्वीकार किया । मैं श्री यशदेव शर्मा, कार्यवाहक निदेशक का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके प्रयत्नों से ही पुस्तक का प्रकाशन शीघ्र हो पाया है ।

शत्रुघ्न

६ अप्रैल, १९७०

कुप्पास्वरूप सक्सेना





## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चेतना का प्रादुर्भाव

जिसे भी देश में राजनैतिक चेतना काकटिक घटना का परिणाम नहीं है, इसके लिए युगो-युगो तक साधना और प्रयत्न करने पड़ते हैं। उदाहरणतः ब्रिटेन, सोवियत संघ और जॉन के इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि 'त्याग के परिणामस्वरूप ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है'। भारत का स्वतंत्रता-इतिहास और राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास भी कनका इसी प्रकार धीरे धीरे हुआ है। आरम्भिक अवस्था में राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक चेतना मुक्त अवस्था में थी, परन्तु राजस्थान का अपना एक इतिहास है "राजस्थान" त्याग और वीरता का पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है। हिन्दू शासन की समाप्ति के पश्चात् राजस्थान में मुसलमानों का शासन आरम्भ हुआ। १२०६ से लेकर १७०७ तक मुस्लिम शासन के पालिष्य में रहने के बावजूद राजस्थान की जनता और राजाजी ने साम्राज्यवादी शक्तियों से सम्पर्क किया। इसीलिए राजस्थान एक ऐसी पवित्र भूमि बना रहा मृत्यु से मउने वाले नागरिकों और राजाओं की बनी नहीं थी, सम्भवतः यही कारण था कि राजपूत एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते रहे 'जिसे मृत्यु ने कोई हार नहीं था।' इस सर्व में राजपूत नागरिकों ने विशेष योगदान दिया, जोने की अपने आप ही अग्नि के समान बन देना एक ऐसा दृष्टान्त बना जो युगो-युगो तक न केवल राजपूतों के लिए अकिनु आने वाली शक्तियों के लिए भी एक प्रेरणादायक श्रोत बना रहा।

राजस्थान का इतिहास और उनका स्वतंत्रता-संग्राम इसी पृष्ठभूमि में फला फूला। मजेश मे, उज्जैनपुर, जोधपुर इत्यादि ऐसे राज्य थे जिन्होंने

स्वतन्त्रता संधि को गई दिखाए दी। महाराणा प्रताप और घोर राठौड़ दुर्गादास ने राजस्थान में नव चेतना जागृत करने में अमूल्य योगदान दिया। अपने आपकी कष्ट देकर जनता की सेवा का वक्त लिया, व्यक्तिगत स्वार्थ को देश-सेवा की बलिदेवी पर थोड़ाबर किया और "स्वतन्त्रता उपहार के रूप में प्राप्त नहीं होती, यह त्याग और बलिदान चाहती है।" इस उक्ति को परिचित कर दिखाया, अन्य प्रांतों के समान ही राजस्थान में भी मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् ब्रिटेन के साम्राज्यवाद का प्रभुत्व स्थापित हुआ। आरम्भिक अवस्था में इस प्रभुत्व को चुनौती भी दी गई परन्तु धीरे-धीरे राजस्थान के राजा इस साम्राज्यवाद के तिकार बन गये।

राजस्थान में राजनैतिक नेतृत्व का अभाव :

उदयपुर के महाराणा राजसिंह और जोधपुर के महाराजा जयचन्तसिंह की मृत्यु के पश्चात् १८वीं सताब्दी के मध्य में राजपूत-राजनीति भ्रष्ट विहीन हो गई। इस समय राजपूत राजाओं में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस जाति की और परम्पराओं की रक्षा कर सके। ऐसी अवस्था में मराठा और विहारियों ने जो भर कर राजपूताने को लूटा। महाराजा बुद्धसिंह की मराठों के हाथों पराजय ने इस तथ्य को उद्घाटित कर दिया कि यदि राजस्थान के राजाओं ने आपसी स्वार्थ और ईमानदारी को समाप्त नहीं किया तो उनका पतन सन्निकट है। इसीलिए सन् १७१४ में जयपुर महाराजा जयसिंह ने राजस्थान के सभी राजाओं का मेवाड़ स्थित दुरडा ग्राम में एक सम्मेलन आयोजित किया जिससे कि विहारियों और मराठों के आक्रमण का सामना करने के लिए एक समान नीति का निर्माण किया जा सके, परन्तु राजाओं के आपसी ईमानदारी और कन्ह ने इस सम्मेलन को विफल बना दिया। इन परिस्थितियों में राजस्थान के राजा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का संरक्षण प्राप्त करने के लिए आकर्षित हुए। ब्रिटेन यही चाहता था क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा उस समय तक नहीं हो सकती थी जबतक कि भारत के देशी राजे और रजवाड़े ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन न करें।

राजपूताना के राज्यों के प्रति ब्रिटिश-नीति (१८०३-१८०५) "ब्रिटिश संरक्षण" की नीति :

दिसम्बर १८०२ में जयपुर की संधि के पश्चात् लॉर्ड इलहीजी की

नीति जयपुरा पार ब्रिटिश साम्राज्यवाद व प्रभाव-क्षेत्र को विवर्जित करने की थी। राजस्थान की राजनीतिव स्थिति उत्तरोत्तर बदने बदतर होती जा रही थी। तेसी अवस्था में ब्रिटेन के 'दोरी रियासतों में हस्तक्षेप की नीति' को अपनाया। ब्रिटिश सरकार का मन था कि मराठों के प्रायत्न को समाप्त करने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए देशी राजाघों की सहायता आवश्यक ही नहीं घबिनु घबिहाय है। तेसी अवस्था में जब भारत के सांस्कृतिक गवर्नर जनरल लार्ड डलहौसी ने देशी रियासतों के राजाघों के सम्मुख ब्रिटिश सहायता का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि १८०३ से लेकर १८०५ तक भारत के अनेक देशीय राजाघों और राजस्थान की रियासतों के साथ अनेक प्रकार की संधियाँ की गई जिन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में १८०३ की संधि पर हस्ताक्षर हुए। १२ दिसम्बर १८०३ को जयपुर महाराजा और ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से जनरल लेन के साथ एक समझौता हुआ जिसे १५ जनवरी १८०४ को भारत व सांस्कृतिक गवर्नर जनरल लार्ड डलहौसी ने अनुमोदित किया। इस संधि के अनुसार जयपुर महाराजा ने यह वचन दिया कि ब्रिटेन के विरुद्ध और कजु जयपुर के विरुद्ध और कजु समझे जावेंगे और बिना ब्रिटिश सत्ता की अनुमति के किसी भी विदेशी व्यक्ति को राज्य में सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जयपुर महाराजा ने ब्रिटेन की प्रभुसत्ता की भी स्वीकार किया। यद्यपि ब्रिटेन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि वह जयपुर महाराजा के सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी प्रकार १८०३ में जोधपुर महाराजा भीमसिंह के साथ भी लार्ड लेन ने संधि चर्चा प्रारम्भ की। परंतु महाराजा भीमसिंह की आत्मसिद्धि मृत्यु के कारण संधि पर तत्काल हस्ताक्षर नहीं हो सके। अतः महाराजा के उत्तराधिकारी महाराजा मानसिंह ने २२ दिसम्बर १८०३ को ब्रिटेन के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के मुख्य अवयव भी जयपुर संधि के समान ही थे। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के द्वारा जोधपुर महाराजा को यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि किसी विदेशी व्यक्ति या सत्ता ने जोधपुर पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन जोधपुर की सहायता करेगा। इसी प्रकार अगले महाराजा के साथ भी संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि की मुख्य बात यह थी कि महाराजा अगले ने यह आश्वासन दिया कि यदि अगले की

अन्य राज्यों के मध्य अधिकार में कोई बाध बिबाध उत्पन्न हुआ तो वह ब्रिटेन के पक्ष निर्णय के लिए सुपुट किया जाएगा। सवि का यह उपबन्ध सम्भवतः ब्रिटेन के लिए सबसे अधिक लाभप्रद था क्योंकि इस उपबन्ध के अन्तर्गत ब्रिटेन अलवर के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता था। १८०५ में भरतपुर के साथ भी सवि सम्पन्न हुई। इस सवि के उपबन्ध भी जयपुर, जोधपुर और अजमेर राजाओं के साथ हुई सवियों के समान ही थे। ब्रिटिश सरकार की ओर से लार्ड सेक ने स्पष्ट आश्वासन भी दिया था कि ब्रिटेन की सरकार भरतपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही किसी प्रकार का मुद्राबन्ध भरतपुर राजा से प्राप्त करेगी।

उपरोक्त सवियाँ इस बात का प्रमाण थीं कि राजस्थान के राजा अपने राज्यों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम निष्ठ नहीं हुए थे और वे धीरे धीरे बाह्य सहायता पर निर्भर होते जा रहे थे परन्तु उनके हृदय में यह भय भी घर करता जा रहा था कि ब्रिटेन का हस्तक्षेप एक दिन उनकी स्वतन्त्रता को समाप्त कर देगा अतः उन्हें अधिक समय तक ब्रिटेन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। १८०५ में लार्ड कार्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए और उनके आगमन के साथ ही साथ राजस्थान के राजाओं में प्रचलित एक नई नीति का आरम्भ हुआ जिसे “अहस्तक्षेप” की नीति कहा जाता है।

### ब्रिटेन की अहस्तक्षेप नीति (१८०५-१८११)

ब्रिटिश सरकार अब इस निष्कर्ष पर पहुँच चुकी थी कि देशी राजाओं के विवादों में हस्तक्षेप करना उनके लिए उचित नहीं है क्योंकि इससे ब्रिटेन के विपक्ष जन भावना को बल मिलता था। ऐसी अवस्था में लार्ड कार्नवालिस ने अपने पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल लार्ड वेवेक्ली की नीति का अनुसरण करना ठीक नहीं समझा। लार्ड कार्नवालिस का मन था कि यदि ब्रिटेन देशी राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उसका साम्राज्य अधिक आसानी से सुदृढ़ बन सकेगा अथवा राजपूत राजाओं की तरफ से सम्भव है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी जाय परन्तु लार्ड कार्नवालिस बहुत ही कम समय तक भारत में रहे। उनके उत्तराधिकारी जार्ज वार्ले और लार्ड मिन्टो ने भी इसी अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया परन्तु १८१५ में लार्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के आगमन के बाद ब्रिटेन की नीति पुनः बदल

गई। साहें हेस्टिग्स ने साहें बेलेजली की नीति को पुनर्जीवन किया और इस प्रकार "हस्तक्षेप" की नीति का पुनर्जन्य हुआ।

**साहें हेस्टिग्स और हस्तक्षेप की नीति (१८१५-१८१८)**

१८११ में सर चार्ल्स मैटथाफ ने यह सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिषद बना दिया जाना चाहिए जो ब्रिटिश सरकार में कार्य करे, जिससे कि राजस्थान के राज्यों में बिगडारी और मराठाओं की स्यूटमार को रोकना जा सके तथा शांति और व्यवस्था स्थापित हो जा सके। साहें हेस्टिग्स ने मैटथाफ की नीति का अनुमोदन किया और देशी राजाओं को ब्रिटिश सरकार प्रदान करने के लिए उनमें बहुत नजदीक के संबंध बनाने की चेष्टा की। साहें हेस्टिग्स को विश्वास था कि राजपूताना के तीन प्रमुख राज्य जयपुर, जोधपुर और उदयपुर सब बनाने की नीति को प्रथम स्वीकार कर देंगे क्योंकि इन राज्यों में घातरिक प्रतिरोध बढ़ना जा रहा था तथा शांति और व्यवस्था सतरे में पड़ती जा रही थी। तबनुसार १८१८ में साहें हेस्टिग्स ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और उदयपुर, के साथ संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किए। संक्षेप में, १८१८ की संधि का परिणाम यह था कि राजस्थान के राजाओं ने ब्रिटेन के प्रभुत्व को पूरे रूप में स्वीकार कर लिया था और अपने आपको ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन की तरफ से इन राज्यों के घातरिक मामलों में भी हस्तक्षेप आरम्भ हुआ और विशेषतः जयपुर तथा जोधपुर में इस हस्तक्षेप का घोर विरोध भी हुआ। घातरिक स्थिति में हस्तक्षेप का मुख्य कारण राजा और उसके जागीरदारी के मध्य मत विभिन्नता थी। विशेषतः उत्तराधिकार के प्रश्न पर जयपुर, कोटा और जोधपुर में अनेक घातरिक मतभेद उठ खड़े हुए। ब्रिटेन के हस्तक्षेप ने ध्यान में भी का काम किया। इन देशी रियासतों के सामलों में एक नई भावना ने जन्म लिया और यह यह था कि ब्रिटेन अपने हस्तक्षेप के द्वारा उनकी स्वायत्तता को समाप्त कर देना चाहता है। इस प्रकार ब्रिटिश विरोधी भावना ने उदित होने का यह प्रथम चरण था।

**उदयपुर में ब्रिटिश हस्तक्षेप**

राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से इस समय उदयपुर की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। उदयपुर ने महाराणा का प्रभुत्व नाममात्र का रद्द किया था। उसने प्रभुत्व को पावतौर से नौबटों के हाथों और राहपुरा के

राजा ने चुनौती दी थी। इनके अतिरिक्त उदयपुर के जागीरदार महाराणा के आदेश को मानने के लिए तयार नहीं थे ऐसी अवस्था में ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट कनल टाड ने महाराणा उदयपुर की सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए जागीरदारों और महाराणा के मध्य एक समझौता कराना चाहा जिसे टॉड कोलनाभा कहा जाता है। इसके अन्तर्गत यह प्रावधान रखा गया कि यदि उदयपुर महाराणा के आदेश का पालन नहीं किया गया तो ब्रिटेन उदयपुर महाराणा की सशस्त्र सहायता करेगा और उनके आदेश का पालन करवाएगा। मार्च १८२१ में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई शाह शिवलाल महाराणा के द्वारा प्रमाण निरुक्त किए गए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शिवलाल को ब्रिटिश समयन प्राप्त था। परन्तु १८२१ में अष्टाचार और अनुशासन हीनता के आरोप में उदयपुर महाराणा ने शिवलाल को बर्खास्त कर दिया। उदयपुर में ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट ने महाराणा के इस आदेश का अनुमोदन करने से इंकार कर दिया परन्तु महाराणा इस सन्दर्भ में ब्रिटेन से हस्तक्षेप की स्वीकार करने के लिए तयार नहीं थे उनका कहना था कि यह उदयपुर का अपना आंतरिक मामला है और ब्रिटेन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः ब्रिटिश सरकार ने महाराणा के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार ब्रिटेन और उदयपुर के विमर्श हुए सबको में एक नया मोड़ आ गया।

### जयपुर में हस्तक्षेप

२१ दिसम्बर १८१८ को जयपुर महाराजा जगतसिंह की मृत्यु हो गई। निराशान होने के कारण उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न गम्भीर बन उठा। मोहनराम नाजिर ने नरवर क भूतपूर्व राजा के पुत्र मोहनसिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। यह भी कहा गया कि महाराजा जगतसिंह ने मृत्यु से पूर्व मोहनसिंह को गोद ले लिया था और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस समय ब्रिटिश सरकार को थार से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया परन्तु मोहनराम नाजिर के विरोधी ठाकुरों ने मोहनसिंह को राजा मानने से इंकार कर दिया। इन विरोधियों का कहना था कि ठाकुर बहादुरसिंह उत्तराधिकारी का दावा अधिक प्राथमिक है और उसे ही उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप प्रारम्भ किया। तत्कालिक ब्रिटिश एजेंट ओट्टर नोनी ने जयपुर के जागीरदारों की एक सभा आयोजित की जिसमें उत्तराधिकार के प्रश्न पर जागीरदारों

से अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । परन्तु इसी बीच इस समाचार ने कि महारानी जयपुर गर्भवती है स्थिति को परिवर्तित कर दिया । २५ अप्रैल १८१६ को महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे तयारि जयसिंह के नाम पर जयपुर का महाराजा घोषित किया गया । साथ ही साथ महारानी ने मोहनराम नाजिर को बरसान्ध कर दिया और उसके स्थान पर जोहराम को राज्य का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया । महारानी के इस कार्य ने ब्रिटिश हस्तक्षेप की धामनित किया । मोस्टर लोनी मोहनराम नाजिर का समर्थक था । अपनी बात मनवाने के लिए मोस्टर लोनी ने ब्रिटिश सशस्त्र सेना को भी जयपुर भेजने के आदेश जारी कर दिए परन्तु महारानी ने साहस के साथ ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते हुए कहा 'जयपुर की सधि जयपुर महाराजा और ब्रिटेन के बीच से हुई है महाराजा के नौकरी ने साथ यह सधि नहीं हुई है' इसी बीच मोरार लोनी ने जयपुर सरकार की सहायता के लिए एक बोरोरीय अधिकारी को नियुक्ति का प्रस्ताव भी किया और कैप्टेन स्टीवर्ट को राज्य का राजस्व अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, साथ ही साथ जोहराम को पदमुक्त करके उसके स्थान पर रायल बेरीसाल को नियुक्त किया गया । इस घटना ने जयपुर रानी और ब्रिटिश सत्ता के मध्य संघर्ष को जन्म दिया । हिंदी और जयपुर के भासपास के क्षेत्र से सैनिकों ने महारानी के समर्थन में जयपुर की ओर प्रस्थान किया, उधर ब्रिटिश सरकार ने मसोरावाद से ब्रिटिश सेना को जयपुर में बुलवा लिया परन्तु इन सबके बावजूद जयपुर राजमाता न रावल बेरीसाल को मान्यता देने से इन्कार कर दिया । प्रत्यक्ष ब्रिटेन की सरकार की भुनना पर मोस्टर लोनी ने स्थिति को और न बिगड़ने देने के लिए हस्तक्षेप किया और बेरीसाल को पदमुक्त करके उसके स्थान पर बिग्री के ठाकुर मेघसिंह और मलेश नारायण और गोविन्द नारायण को मुख्य राजस्व अधिकारी पद पर नियुक्त किया । इस प्रकार जयपुर राजमाता और ब्रिटिश अधिकारियों के मध्य सम्बन्धिता सम्पन्न हुआ । परन्तु यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि १८०३ और १८१८ की सधि के बावजूद राजा और जागीरदार अपने आंतरिक मामला में ब्रिटेन के हस्तक्षेप की स्वीकार करने में तैयार नहीं थे ।

कोटा में हस्तक्षेप

२१ जनवरी १८१६ को कोटा महाराज जयसिंह की मृत्यु हो गई । उनके उत्तराधिकारी महाराज विजयसिंह और तत्कालीन कोटा राज्य अधि

कारी जालिमसिंह के पुत्र माधोसिंह के मध्य घच्छे सबंध नहीं थे। इस अवस्था में माधोसिंह महाराज किशोरसिंह को अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ६ और ७ अप्रैल १८१६ को महाराजा किशोरसिंह के समर्थकों ने सेना को बुला लिया, उधर राजराणा माधोसिंह ने भी अपने समर्थक सैनिकों को आमंत्रित कर लिया। इस प्रकार एक संधर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसने ब्रिटेन के हस्तक्षेप को आमंत्रित किया। कर्नल टॉड ने एक १२ घुड़सवार समझौता तैयार किया जिसे राजराजा और राजराणा दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार राजराणा को २०० सैनिक निवृत्त करने का अधिकार दिया गया परंतु राजराजा ने कुछ और अधिक सैनिक बुलाकर स्थिति को और अधिक गम्भीर बना दिया। कर्नल टॉड के द्वारा राजराजा को अंतिम चेतावनी (मस्टीमेरम) दे दी गई कि वह पांच दिन भेद भेद उनके समझौते को स्वीकार करें अन्यथा उसके भयंकर परिणाम होंगे। महाराज समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, अंततः २८ दिसम्बर को महाराजा ने कोटा से बूंदी की ओर प्रस्थान किया। कर्नल टॉड ने महाराणा को चेतावनी दी कि उनका सशस्त्र सामना किया जाएगा। अंततः नगरीय के पास महाराज की सेना और राजराणा व ब्रिटिश समर्थित सेना के मध्य संधर्ष हुआ। महाराज ने छोटे भाई किशोरसिंह बुरी तरह घायल हुए और महाराज को जयपुर सीमा व शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। ब्रिटेन के इस आघात ने भयंकर राजपूत राजाओं को सशक्त बना दिया। वे सोचने लगे कि आज जो कुछ कोटा महाराज के साथ हुआ है वही बल उनके साथ भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में ब्रिटेन के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आरम्भ हुआ। इसी बीच १२ नवम्बर को कोटा महाराज नाथद्वारा पहुंचे। कर्नल टॉड के वकील ने एक समझौता-प्रस्ताव रखा जिस पर १६ नवम्बर १८२१ को महाराज ने हस्ताक्षर कर दिए। एक प्रकार से यह ब्रिटेन की सत्ता के समक्ष कोटा महाराज का पूर्ण समर्पण था। कोटा के आठ-दिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप ने एक बार पुनः यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटेन का एकमात्र उद्देश्य है राजस्थान व अपने साम्राज्यवाद को पूरी तरह मजबूत बना देना। साथ ही साथ यह देशीय राजाओं की आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त था। संक्षेप में, देशीय राज्यों की जनता का ब्रिटेन की न्यायप्रियता में ते विश्वास हिल उठा और उनमें भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जन्म लेने लगीं।



प्रसन्न में हस्तक्षेप

इसी बीच प्रसन्न में भी राजनीतिक दृष्टि से हस्तक्षेप किया गया। १८१५ में रावराजा बलवन्तसिंहजी की मृत्यु हो गई और इसने साथ ही उनके उत्तराधिकार का प्रश्न विचट रूप धारण कर लिया। यही के लिए मुख्यतः दो दावेदार थे जिनमें से एक उनका अनोरस पुत्र बलवन्तसिंह, जो कि एक मुस्लिम वैश्य से उत्पन्न हुआ था और जिसने बाद में हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया था—दावेदार था, और दूसरा महाराजा का भतीजा बलवन्तसिंह था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाराजा की इच्छा अपने अनोरस पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में यही पर बैठाने की थी और इसीलिए जब उनकी मृत्यु के बाद किरोजपुर के महमद बख्त खां ने अपने मरतवा में बलवन्तसिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की परन्तु महाराजा के जमींदार इस व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं थे। प्रसन्न दोनों दलों के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार बलवन्तसिंह को प्रसन्न राज्य का नामधारी महाराजा और बलवन्तसिंह को वास्तविक शासक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस सन्दर्भ में ब्रिटिश सरकार का रुखा बड़ा विचित्र रहा। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 'यदि भावस्थिता हुई तो यह अवश्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार सुरक्षित रहती है' जब १८२५ में बख्त महमद बख्त खां ने दिल्ली की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उनकी हत्या करने वाला बलवन्तसिंह के दल का एक सदस्य था, ब्रिटिश एजेंट मोस्टर सोनी ने आवायक जाच परदास के आदेश दिए चालु इस घटना न बलवन्तसिंह और बलवन्तसिंह के आपसी दलों के मध्य वैमनस्य और बढ़ता उत्पन्न कर दी। ऐसी व्यवस्था में पुनः दोनों दलों में एकता स्थापित करने के लिए मोस्टर सोनी के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यह तथ्य हुआ कि—

- (१) बलवन्तसिंह और बलवन्तसिंह के मध्य राजक्षेत्र का सदाव्यवहार विवरण किया जाएगा।
- (२) वे परमन जिनकी निम्नलिखित चार जाल स्थल स ज्वादा है और जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रियासत को प्रदान किए गए हैं उन्हें बलवन्तसिंह और उनके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।
- (३) उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में न बख्त महमद बख्त खां को

(४) यह भी घोषित किया गया कि यदि भद्रमद बरहल सा की हत्या में बनेसिंह का मदहात्मक रुम भी रहा है तो भी इसकी स्पष्ट घोषणा करना वांछित नहीं होगा ।

उपयुक्त गन्दी पर १८२५ में समझौता सम्पन्न हुआ जिसे २१ फरवरी १८२६ को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया । यह इस बात का प्रमाण था कि ब्रिटिश सरकार राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है और यह ऐसा कोई अवसर नहीं मिला चाहती जिसके द्वारा वह अपनी सत्ता को मजबूत बना सके ।

भरतपुर में हस्तक्षेप .

भरतपुर में भी उत्तराधिकार का प्रश्न ब्रिटिश हस्तक्षेप का कारण बना । २६ फरवरी १८२५ को महाराजा बलदेवसिंह स्वर्गवास हो गए और इसके साथ ही उत्तराधिकार के दो दावेदार बने हुए इनमें से एक बलदेवसिंह के पुत्र बलवतसिंह और दूसरे, दुर्जनसाल थे । ब्रिटिश सरकार द्वारा बलवतसिंह को ६ फरवरी १८२५ को राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया परन्तु इसके साथ ही दुर्जनसाल और उसके जाट समर्थकों ने विद्रोह पड़ा कर दिया । ११ मार्च १८२५ को दुर्जनसाल और उसके साथियों ने भरतपुर के किले पर आक्रमण किया और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया । मोस्टर लोनी ने दुर्जनसाल और उसके साथियों की इस कार्यवाही को "दिन दहाड़े डाका" डालने की सजा दी और बलवतसिंह के समर्थन की घोषणा की । दूसरी ओर, दुर्जनसाल ने जाट जाति के नाम पर भरतपुर के प्रत्येक व्यक्ति से यह अनुरोध किया कि वह उसका समर्थन करे परन्तु इसी बीच गवर्नर जनरल ने यह निर्णय दिया कि यदि उत्तराधिकार के प्रश्न पर राज्य में यदि कोई विवाद है तो राज्य का यह अपना मामला है और ब्रिटिश सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए साथ ही मोस्टर लोनी को यह आदेश दिया कि वह सज्जन हस्तक्षेप न करे और बलवतसिंह का समर्थन करना बंद कर दे । इसी बीच दुर्जनसाल के छोटे भाई माधोसाल न सत्ता हाथिलाने का प्रयत्न किया और हीम ने किले पर आधिपत्य जमा लिया । माधोसिंह ने दुर्जनसाल के विरुद्ध ब्रिटन का समर्थन भी प्राप्त करना चाहा क्योंकि कि बलवतसिंह उसे गुप्तियांगी देने के लिए तैयार हो जाए । एक बार स्थिति पुन बदली, मैटबोय ब्रिटिश रेजीडेंट और राजपूताना में एजेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए ।

उनका दृष्टिकोण यह था कि राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने की पहिल जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की है और इसलिए वह विपत्ती हुई स्थिति को प्रायः मृदुतर नहीं देख सकते। तदनुसार मैटकोफ ने महाराजा बलबलसिंह के समर्थन में ब्रिटिश सेना को भरतपुर भेजने का आदेश दे दिया। अतः १० अक्टूबर १८२५ को ब्रिटिश सेना ने भरतपुर ब्रिगेड पर आक्रमण किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जनवर जोधपुर, जयपुर और करोली की सेनाओं ने दुर्जनसाल की सहायता की। यद्यपि मैटकोफ की इस समाचार में विश्वास नहीं था। दुर्जनसाल ने प्रस्ताव किया कि वह बलबलसिंह का समर्थन करने के लिए तैयार है, यदि ब्रिटिश सेनाएं भरतपुर से वापिस हट जाएं, परंतु मैटकोफ ने बिना शर्त दुर्जनसाल के समर्थन की मांग की। अतः ब्रिगेड की दीवार को शायनामाष्ट से उखाड़ा गया और इस प्रकार ब्रिटिश सेना ने भरतपुर शहर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दुर्जनसाल की गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अहमदाबाद भेज दिया गया।

### जोधपुर में हस्तक्षेप

१८१८ की सन्धि पर हस्ताक्षर हुए अभी अधिक समय भी नहीं हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया। जैसे ही १८१८ की सन्धि पर हस्ताक्षर सम्पन्न हुए ऐसा विश्वास किया जाने लगा था कि जोधपुर महाराजा मानसिंह अपना आन्तरिक समुत्थान छोड़ चुके हैं। अक्टूबर १८१८ में महाराजा मानसिंह ने रिटेल से सशस्त्र सहायता मागने की इच्छा प्रकट की और इन सैनिक दलों का खर्चा बरदास्त करने की इच्छा भी प्रकट की। परंतु उनका कहना यह था कि यह सेनाएं उनके स्वयं के आदेशों के अनुरूप कार्य करेगी और प्रमुखता जागीरदारी एवं ठाणुरी की दकानों में जोधपुर महाराजा की सहायता करेगी। ब्रिटिश एजेंट प्रोक्टर लोनी ब्रिटिश हस्तक्षेप का समर्थन था परंतु इसके पहले कि सशस्त्र सेनाएं भेजी जाएं वह राज्य की वास्तविक स्थिति का जायजा ले लेना चाहता था। इसलिए प्रोक्टर लोनी ने अपने प्रधान पुरोही बलराम दास को जोधपुर की स्थिति का वास्तविक पता लगाने के लिए भेजा। इसी बीच जोधपुर के आंतरिक स्थिति दिनोदिन बिगड़ने लगी और महाराजा के विरोधी और प्रतिस्पर्धी पंतहाराज ने जोधपुर सेनाओं के समर्थन में सपूचे शहर पर अपना प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया। व्यवहार में महाराजा और उनके सन्धियों का सम्बन्ध केवल ब्रिगेड तक सीमित रह गया। इस स्थिति में बलराम

अली जोधपुर पहुँचा, बरकत अली इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वास्तव में महाराजा मानसिक दृष्टि ■ बिस्कुन ठीक हैं। बरकत अली ने महाराजा की पुनः सत्ता स्थापित करने के लिए अपनी रेजीडेंट की ओर से सहायता का आग्रहवाक्य दिया। परन्तु बरकत अली की बातचीत से महाराजा मानसिंह को यह संदेह हुआ कि सम्भव मित्रता और सहायता के नाम पर ब्रिटेन उनकी स्वतन्त्रता और राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है। अतः महाराजा ने ब्रिटिश सहायता के प्रस्ताव को नम्रतापूर्वक ठुकरा दिया परन्तु अपने जागीरदारों एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों पर इस प्रकार का प्रभाव अवश्य डाला कि ब्रिटिश सरकार उन्हें ही राज्य का वास्तविक शासक समझती है। महाराजा मानसिंह के इस प्रयत्न ने जोधपुर के अन्य ठाकुर और जागीरदारों की स्वामीभक्ति भी प्राप्त कर ली।

बरकत अली की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर ने सुपरिटेण्डेण्ट एग्रेन्ट कैंपेन को जोधपुर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा। जोधपुर में कैंपेन के ठहरने के दौरान महाराजा ने पुनः इस प्रकार का आचरण किया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें ही जोधपुर का सर्वे सर्वा मानती है और इस प्रकार अपने असंतुष्ट जागीरदारों पर अपना प्रभाव जमाने की चेष्टा की। एग्रेन्ट कैंपेन ने महाराजा को ब्रिटेन की ओर से सशस्त्र सहायता देने का पुनः प्रस्ताव किया परन्तु महाराजा ने पुनः नम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

१८२१ में जोधपुर के असंतुष्ट ठाकुरों एवं जागीरदारों ने ब्रिटिश एग्रेन्ट कैंपेन टाई को महाराजा के विरुद्ध शिकायतों का एक मेमोरेण्डम प्रस्तुत किया। इसी बीच महाराजा ने जोधपुर के अनेक असंतुष्ट ठाकुरों एवं जागीरदारों को राज्य से निष्काशित कर दिया गया था। अतः ब्रिटिश एग्रेन्ट मोस्टर लोनी ने महाराजा को परामर्श दिया कि वह इन निष्काशित ठाकुरों एवं जागीरदारों को क्षमा वाचना प्रदान करें। महाराजा ने ब्रिटिश सरकार को विश्वास दिलाया कि वे इन ठाकुरों और जागीरदारों की शिकायतों पर अवश्य विचार करेंगे यदि वे उनसे प्रत्यक्ष बातचीत करें। तदनुसार ब्रिटिश रेजीडेंट ने इन असंतुष्ट ठाकुरों को यह परामर्श दिया कि वे जोधपुर वापिस लौट जाएँ और महाराजा से सीधी बातचीत करें। साथ ही साथ उन्हें यह भी आशवासन दिया गया कि इस यात्रा के दौरान उनके जीवन और सम्पत्ति की रक्षा

की जाएगी। परन्तु इन असमुष्ट जागीरदार घोर ठाकुरों को महाराजा के आदेश से रास्ते से ही बिरफूदा कर दिया गया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें रिहा भी कर दिया गया था। इस घटना ने घोस्टर लोदी को महाराजा के खिलाफ बहुत अधिक असमुष्ट कर दिया। उन्होंने महाराजा को ब्रिटेन की 'महाराजगी' भी प्रशंसा की। साथ ही साथ एक० विल्डर को जोधपुर की स्थिति का आग्रह देने के लिए पुनः भेजा गया। महाराजा जोधपुर घोर विल्डर के मध्य बातचीत करते ही तनावपूर्ण बातचीत में हुई। महाराजा का कहना था कि १८१८ की संधि के अनुसार ब्रिटेन उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अतः महाराजा ने माया, आनंद, निवेश और रात के ठाकुरों को पुनः जागीरें दे दीं और ब्रिटेन में पुनः इस आग्रह की मांग की कि ब्रिटिश सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक० विल्डर ने ब्रिटिश सरकार की ओर से महाराजा की आग्रहसूचि दी कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यद्यपि घोस्टर लोदी एक० विल्डर के इस आग्रह से असमुष्ट नहीं था परन्तु क्योंकि विल्डर वचन दे चुका था अतः उन्होंने अंततः ने उसकी वचन की रक्षा करने का निश्चय किया। १८२४ में महाराजा घोर उनके जागीरदारों के मध्य पुनः विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश सरकार जोधपुर के ठाकुरों का वचन से रही थी परन्तु ब्रिटिश रेजिडेंट यह नहीं चाहता था कि वह असमुष्ट जागीरदारों घोर ठाकुरों की तरफ से पुनः हस्तक्षेप करे। इसी बीच स्थिति पुनः बदली और जोधपुर के असमुष्ट ठाकुर पोकनसिंह ने जोधपुर क्षेत्र में प्रवेश किया और बीकानेर पर आधिपत्य जमा लिया। महाराजा पोकनसिंह ने ब्रिटिश सहायता की मांग की। परन्तु ब्रिटिश सरकार उस समय तक सहायता के लिए कोई भी वचन देने के लिए तैयार नहीं थी जबतक कि महाराजा अपने संपूर्ण विवाद ब्रिटिश सरकार के सम्मुख सब निर्णय के लिए रखने को तैयार न हो जाए। पोकनसिंह ने ऐसा तक आ पहुँचा और यह स्थिति ने काफी अप्रकर रूप धारण कर लिया, परिणामतः महाराजा पोकनसिंह इस बात के लिए तैयार हो गए कि उनके वह जागीरदारों के मध्य विवाद को ब्रिटिश सरकार ने सब निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने पोकनसिंह पर दबाव डाला कि वह अपनी सेनाएँ जोधपुर में हटा दें, पोकनसिंह ने जोधपुर प्रदेश से अपनी सेनाएँ हटा लीं और इस प्रकार बड़े समय के लिए जोधपुर में शांति स्थापित हो गयी।

## बीकानेर में हस्तक्षेप

जोधपुर के समान ही बीकानेर में भी राजा और जागीरदारों के मध्य कटुता और वैमनस्यता का बालावरण था। जागीरदार राजा के आदेश को चुनौती देते थे और इस प्रकार जालि और व्यवस्था को चाहे जब खतरा उत्पन्न हो जाता था। तदनुसार १८१८ की संधि के पश्चात् बीकानेर महाराजा ने अपने विद्रोही जागीरदारों को दवाने के लिए ब्रिटेन से सहाय्य सहायता का अनुरोध किया। ब्रिटेन भी बीकानेर में रुचि रखता था क्योंकि भागनपुर तक व्यापार करने का यह सीधा मार्ग था। अतः ब्रिटिश रेजीडेंट ने एक घुड़सवार सना बीकानेर भेज दी जिसने कुरुक्षेत्र नीमा नाहान सानुन और बीरोड इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया लेकिन इसी बीच फतेहाबाद और सिरसा में भाटियों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने घरेलू हस्तक्षेप का यह स्वरूप अवसर समझा। ब्रिटिश सना को आदेश दिया गए कि वह फतेहाबाद और सिरसा पर पुनः आधिपत्य स्थापित कर ले और फिर बीकानेर-क्षेत्र में प्रवेश करे। जेम्स डीयर बरनोल्ड के अनुसार म ब्रिटिश सेवा ने बीकानेर के प्रमुख इलाकों पर जैसे ददरेशा सिरमौर, सिरसीना, बुध, सरिया मुडुकरा और गदेली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। महाराजा की सनामी ने भी इस कार्यवाही में ब्रिटिश सना की सहायता की परन्तु प्रसन्नोद्द जागीरदारों ने सना ठाकुर पृथ्वीसिंह के द्वारा इस कार्यवाही का पोर विरोध किया गया। अतः ठाकुर पृथ्वीसिंह को बिना छोड़ना पड़ा और बीकानेर महाराजा ने उसने क्षमा-याचना की। इसी प्रकार ददरेशा के ठाकुर मूरधन ने भी क्षमा समर्पण कर दिया और गलावटी की ओर भाग गया। गदेली भरिया सिरसीना और बुध के ठाकुरों ने भी समर्पण कर दिया और इस प्रकार ब्रिटिश सैनिक सहायता के परिणामस्वरूप बीकानेर में शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई।

## १८२५ के बाद ब्रिटेन की नीति

कोटा, जयपुर, उज्जैन, अजमेर और भरतपुर तथा जोधपुर की राजाओं ने ब्रिटिश सरकार पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियाँ डाल दी थी। जैसाकि हम देख चुके हैं इन राज्यों के आन्तरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप ने ब्रिटेन के प्रति विरोध को जन्म दिया था। वास्तव में १८१८ में जब राजस्थान के अनेक राज्यों के साथ विभिन्न संधियाँ की गई थीं तो ब्रिटिश

सरकार ने यह कभी नहीं विचार था कि उस दिन प्रजा की कठिनाइयों का सामना करना होगा। जमी अधिकांश में १८२५ के बाद ब्रिटेन की नीति में पुन परिवर्तन के तत्क्षण दिखाई दिए। मेन्काफ ने पुन लम्बे आदेश जारी किए कि जहाँ तक संभव हो पायों व पालनिक सामानों में हस्तक्षेप न किया जाए। यही कारण है कि १८२९ में जब जयपुर की महाराज्ञी ने मोटराम को अपना मुख्यकार नियुक्त किया तब ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी हस्तक्षेप के मोटराम को नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया। इसी प्रकार उदयपुर में भी महाराज्ञी के आदेशों कापों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। बीकानेर और जोधपुर के प्रति भी यही नीति अपनाई गई। अंत में १८२५ के बाद ब्रिटेन ने एक बार पुन अहमशेष की नीति का अनुसरण किया और इस प्रकार अन्तःप्रदेशों के राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया। इसी बीच १८३२ में भारत के नये गवर्नर जनरल लार्ड डलहौसी ब्रिटिश सरकार को बोधे।

### ब्रिटिश की नीति

ब्रिटिश ने अंत में मेन्काफ की अहमशेष की नीति का समर्थन किया परंतु उन्होंने इसका कड़ाई से पालन करने में इन्कार कर दिया। अंत में, ब्रिटिश की नीति को 'अनुविना' की नीति कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ आवश्यक हो वहाँ हस्तक्षेप करने के लिए गवर्नर जनरल तैयार थे। १८३२ में गवर्नर जनरल डलहौसी ने अंत में एक देशी राजाओं का दरबार आयोजित किया जिसमें टीपू के नवाब अमीरखा, उदयपुर के महाराजा अमरसिंह, जयपुर के महाराजा जयसिंह, कोटा के महाराज रामसिंह, विजयनगर के महाराजा बलरामसिंह और बूंदी के महाराज रामसिंह ने भाग लिया। बीकानेर और अजमेर के महाराजा बहुत अधिक दूरी के कारण उपस्थित नहीं हो सके और जोधपुर के महाराजा मानसिंह अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के कारण भाग्यवश नहीं हो पाए। इस अवसर पर राजाओं ने ब्रिटिश सरकार से यह अनुरोध किया कि वे उनके राज्यों में पड़ने वाली कठिनाइयों और लोगों के आक्रमण से उनकी रक्षा करें साथ ही साथ यह भी अनुरोध किया गया कि विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने में भी ब्रिटिश सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करे। परंतु गवर्नर जनरल लार्ड डलहौसी ने इन अनुरोधों को मानने से इन्कार कर दिया। उनका कहना था यह राज्यों का

घटना प्रान्तरिक मायता है और उन्हें ही घपनी स्थिति को समझना चाहिए। परंतु इन सबके बावजूद जोधपुर की स्थिति बहुत अधिक गंभीर बनती जा रही थी ऐसा विश्वास किया जाता है कि जोधपुर के महाराजा नाथो के प्रभाव में थे। साथ ही साथ वे अन्य राजाओं के साथ मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध एक मोर्चा भी बनाना चाहते थे। यह भी संभव है कि जोधपुर महाराजा स्वयं और फारम के साथ मिलकर ब्रिटेन का विरोध करना चाह रहे हैं ऐसी धारणा में ब्रिटिश सरकार जोधपुर में हस्तक्षेप करने का बहाना ढूँढ रही थी।

### जोधपुर में हस्तक्षेप

सन् २ अगस्त १८३६ को ब्रिगेडियर रीज़ के नेतृत्व में ब्रिटेन की सशस्त्र सेना ने जोधपुर सीमा का उल्लंघन कर राज्य में प्रवेश किया। जोधपुर महाराजा ने ब्रिटेन की सभी मांगों को स्वीकार करने हुए २७ सितम्बर १८३६ को किला खाली कर दिया और इस प्रकार ब्रिटिश विरोधी महाराजा को सत्ता ब्रिटेन की सत्ता के समक्ष झुकना पड़ा। इसी प्रकार जयपुर और शेखावाड़ी इलाकों में भी शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर मेजर फ्रांसिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने प्रवेश किया और शेखावाड़ी-भोज के कुश्वाहा लुटेरे दूधरमिह उर्फ दूधरी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार देशी राज्यों में शांति और व्यवस्था के नाम पर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता गया।

### लार्ड डलहौजी की नीति और राजस्थान के राजा

जब भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी बन। उन्होंने एक नई नीति का सूत्रपात किया जिसे 'राज्यों का विलय' की नीति के नाम से पुकारा जाता है। इस नीति का मुख्य आधार यह था कि यदि देशी रियासत के राजा की नियन्त्रण मृत्यु हो जाय तो उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के अनुमोदन पर ही हो सकेगी और यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस परिस्थिति में उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जायगा। लार्ड डलहौजी की इस नीति ने राजस्थान के राजाओं को चिंतित कर दिया। उदाहरण १० जुलाई १८५२ को करौली के महाराजा नरसिंह पाल की मृत्यु हुई। लार्ड डलहौजी ने प्रस्ताव किया कि करौली रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाय परंतु कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स ने गवर्नर



जनरल के इस प्रस्ताव को मानने ■ इन्कार कर दिया। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता की करौनी महाराज के रूप में मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया। मगध में, ब्रिटिश सरकार को इन गतिविधियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे देशी रियासतों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। ब्रिटेन की इस नीति ने राजाओं को भी उनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करा दिया। अब वे समझ गये कि, मगध जंगलों में वे ब्रिटेन के हाथों में बंछतुननी बन चुके हैं।

इस प्रकार राजस्थान में ब्रिटेन का प्रभाव-क्षेत्र स्थापित होना गया। विभिन्न देशी रियासतों के राजे और महाराजे नाथमात्र के शासक रह गये। साम्प्रतिक सत्ता ब्रिटेन के हाथों में आ चुकी थी लेकिन इस सबके बावजूद जयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में ब्रिटेन के हस्तक्षेप की नीति का जो मुना बिरोध किया गया वह इस बात का प्रतीक था कि जनता, जागीरदार और राजे ब्रिटेन की सत्ता को सहर्ष रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। साम्प्रतिक में वे साम्प्रतिक कारणों से ब्रिटेन का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं यही कारण है कि १८५७ में जब आगमन पड़नी बार ब्रिटेन की सत्ता को चुनौती दी गई तो देशी राजे और जागीरदारों ने भी ब्रिटीशों का साथ दिया। यह राजनैतिक चेतना की आरम्भिक अवस्था थी परन्तु ब्रिटिश बिरोधी मान्यता के बीच समझ पड़ चुके थे, समय और परिस्थिति के अनुसार वे धीरे-धीरे विकसित हो गए।

## १८५७ का विप्लव और राजस्थान

इस प्रकार राजस्थान में व्याप्त घराबक स्थिति ने १६ वीं सताब्दी के प्रारम्भ में राजपूताना के राज्यों को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त करने ■ लिए बाध्य कर दिया । एक प्रकार से राजस्थान के सभी राज्य किसी न किसी रूप में ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधि या समझौता कर चुके थे परन्तु इन संधि के बावजूद उनके आंतरिक गतिरोध समाप्त नहीं हुए । उत्तराधिकार का पन्ना और विवेक अधिकार ■ प्रश्न पर आमीरदारी और राजाघो के मध्य सघर्ष बराबर चलता रहा । ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा घनेक राज्यों में सशस्त्र हस्तक्षेप भी किया गया परन्तु कुछ समय तक जाति और व्यवस्था के बाद स्थिति पुनः बिगड़ती रही । इस प्रकार जब राजस्थान में आंतरिक अस्थिरता और अन्धवस्था फैली हुई थी उसी समय भारत में भी ईस्ट इंडिया कम्पनी के विरोध में आतावरण बनता दिखाई दे रहा था ।

जब भारत में १८५७ का विद्रोह फैला उस समय राजस्थान में एजेन्ट गर्बनर जनरल लार्सन थे । साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में ब्रिटन के रेजीडेन्ट भी नियुक्त किए जा चुके थे, उदाहरणन उदयपुर में कॅप्टन सी० एल० नाबर्स, जयपुर में कॅप्टन विलियम ईटन, जोधपुर में कॅप्टन भाक भसन, कोटा में मेजर बर्टन और भरतपुर में मेजर निकमन थे । राजस्थान में मुख्यतः चार सैनिक छावनियां थी जो नसीराबाद, नीमच, देवली और खजमेर में स्थित थी । नसीराबाद में नेटिव होम फील्ड बॅटरी नंबर ६, पण्डहवीं और तीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेन्ट्री और फर्स्ट बोम्बे रेजिमेंटरी नियुक्त थी । नीमच में चौथी द्रूप फर्स्ट ब्रिगेड बंगाल नेटिव होम फील्ड बॅटरी, फर्स्ट बंगाल रेजिमेंटरी, बहतरवीं

बगान इन्फेन्ट्री और मानवी इन्फेन्ट्री स्थानियर नियुक्त थी। देवगी में और कोटा में जो इन्ही प्रकार कुछ ब्रिटिश टुकड़ियाँ तैनात थीं। इनके प्रतिरिक्त एलनपुग ब्यावर और सेरकाज में भी न टुकड़ियों के साथ-साथ फर्स्ट बगान केबेनरी भी नियुक्त थी। अबमेर में फन्नेहरी बगान मैटिव इन्फेन्ट्री और मेर-काटा बटालियन तैनात थी। इन्ही प्रकार जयपुर हाडोबी, जोधपुर और भीमप में भी कुछ टुकड़ियाँ तैनात थीं लेकिन इनका स्पष्ट है कि विद्रोह के समय समूचे राजस्थान में एक भी यूरोपीय निवासी तैनात नहीं था। यही कारण है कि जब राजस्थान में भी १८५७ के विद्रोह की घात फेंकी तो ब्रिटिश सरकार बित्तहीन हो उठी।

मेरठ और दिल्ली में सैनिक विद्रोह के समाचार राजस्थान में १६ मई, १८५७ को उस समय पहुँचे जॉर्ज एलेक्स गवर्नर जनरल लार्ड माउण्ट बैटन में गवर्नर की लुट्रिया मना गये थे। यह समाचार मिलने ही कि मेरठ और दिल्ली में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हो गया है जनरल लार्ड ने भी राजस्थान में अनेक ऐसे आदेश जारी किए जिसमें कि यदि कभी राजस्थान में भी विद्रोह की घात फेंकनी तो तत्का सामना किया जा सके। २१ मई, १८५७ को एलेक्स गवर्नर जनरल ने दीमा में यूरोपीय सेना की सरकार नसीमगढ़ भेजे जाने का आदेश दिया। साथ ही साथ अग्यै सरकार से भी यह प्रार्थना की गई कि यह यूरोपीय सेना की कुछ टुकड़ी तत्का राजस्थान की भेज दे। २३ मई १८५७ को एलेक्स गवर्नर जनरल ने एक घोषणा प्रसारित की जिसमें राजस्थान के सभी राजाघा और प्रमुख जागीरदारों में यह अनुरोध किया गया कि वे अपने धर्म क्षत्रा में आति बनाए रखेंगे और ब्रिटिश विद्रोहियों को पकड़ने में ब्रिटेन की सहायता करेंगे।

### देशी राजाओं का ब्रिटेन की सक्रिय सहयोग

गवर्नर जनरल के महसूस की घपीन पर राजस्थान के सभी राजाघा ने ब्रिटेन की सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया। विद्रोह के महायत्न ने भारत प्रत्यक्ष की कि दिल्ली का विद्रोह बहुत जल्द ही समाप्त हो जायगा इन्ही प्रकार जयपुर के महाराजा न पोलिटिकल एजेन्ट कैप्टन ईडन को हर प्रकार की सहायता का जवाब दिया यहाँ तक कि कैप्टन ईडन के नेतृत्व में पाँच हजार ब्रिटिश सैनिकों को जयपुर से न भेजे हुए मथुरा और गुडगांव जाने तथा वहाँ पर नागरिक प्रशासन को स्थापित करने में मदद देने के लिए

अपनी सीमा का उपयोग करने की अनुमति दे दी। महाराजा भलवर ने भी दो हजार पाँच सौ भूमिपुत्रों को भेजकर कैंप्टन निमसन की सहायता की। इसी प्रकार जोधपुर के महाराजा ने भी अपने २००० घुड़सवार और पदयात्री सेना व ६ तोपों को एजेंट गवर्नर जनरल की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही साथ महाराणा स्वरूपसिंह (जोधपुर) ने ब्रिटेन ने समर्थन की स्पष्ट घोषणा की और जून १८५७ में राज्य के जागीरदारों के नाम एक असील प्रसारित की जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वह ब्रिटेन की हर प्रकार से सहायता करे। यह असील लाम लौर से देवल, बागरा सलुम्बर बनोता और जनमाना के जागीरदारों से भी की गई। यही नहीं महाराणाओं ने अपनी ममलू सेना तात्कालिक पोलिटिकल एजेंट कैंप्टन सी० एस० शावर के अनुरोध पर छीन दी और २७ मई १८५७ को एक और विशेष असील प्रसारित की जिसमें पुनः यह अनुरोध किया गया था कि लावस के आदेशों को महाराणा के आदेश माने जाएँ और उसी के अनुरूप आचरण किया जाए। अक्टूबर १८५७ को महाराणा ने घोषणा पनाहवा जावाम भक्तों और बानी आदि के मुखियाओं के नाम एक परवाना जारी किया जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया था कि खेरबाड़ा और कोटरा में ब्रिटेन की सेनाओं की हर सम्भव सहायता की जाए और पहाड़ी इलाकों में किसी भी प्रकार का विद्रोह न होने दिया जाए।

### नसीराबाद में विद्रोह

राजस्थान में १८५७ के विद्रोह का सकेन नसीराबाद से प्रारम्भ हुआ। २८ मई १८५७ को शाम के ४ बजे नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटेन की ओर से नसीराबाद स्थित सेनाओं को निरास्त करने के प्रयास में भाग में भी का काम किया। ऐसी अवस्थाएँ भी फैल रही थी कि सैनिकों को जो आटा दिया जाता है और जो कारतूस नाम में देने के लिए दिए जाते हैं उसमें गन्ध का माग मिलाया जाता है। २७ मई को यह भी समाचार फैला कि बीसा के योरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी नसीराबाद में रही है जो बड़ा स्थित सैनिकों का स्थान लेगी। इस समाचार ने ब्रिटिश विरोधी भावना को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। नसीराबाद की स्थिति बिगड़ने लगी। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया परन्तु फर्स्ट रेजीमेन्ट बोम्बे लाहौर ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और ब्रिटिश आदेश का पालन करते हुए उन पर गोली चलाई परन्तु साइन्स एव गनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इन्कार कर

दिया। डिपेंडिपर मेजर के जाने पोरोंन्दियन सैनिकों के साथ पीछे हटने की बाध्य हुआ, साथ ही कर्नल पैरी जो रि कार्पे कमन्डर थे—बटनगम्प पर ही मर गए। मम्मन इनका बारागु इनका सम्भर हो जाता है। दो अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की भी मृत्यु हो गई और दो घायल हो गए, और हमके साथ ही नमीराबाद विप्लवकारियों के हाथों में चला गया। दूसरे दिन विप्लवकारियों ने नमीराबाद छावनी को जल कर दिया और दिव्ही की ओर प्रस्थान किया।

मेजरीनेट मास्टर तथा मेजरीनेट हेक्कोट के नेतृत्व में लगभग एक हजार मेराठ के सैनिकों ने विप्लवकारियों का पीछा किया परन्तु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। मसकन इसका कारण यह था कि मेराठ और मारवाड के जागीरदारों ने नमीराबाद के विप्लवकारियों को माला प्रदेश में ले आगामी के गुजर जाने दिया। यह तथ्य हम बात का करने था कि मेराठ और मारवाड की महानुभूति विप्लवकारियों के साथ थी।

### नीमच में विप्लव

राजस्थान में विप्लव का दूसरा स्थान नीमच बना, जहाँ १ जून, १९१७ को फाति फूट पड़ी। २ जून की कर्नल प्रबोड ने हिन्दू और मुसलमान मिताहिना को मना और कुतान की कपड़ बिनाई की कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति बकायार रहेँ, कर्नल प्रबोड ने स्वयं ने भी बाइकिंग को हाथ में लेकर माला की थी, जिससे कि वह अपने सभी मिताहिनों का पूर्ण विरहास प्राप्त कर सकें परन्तु जब ३ जून, १९१७ को नमीराबाद के विप्लव का समाचार नीमच पहुँचा तो उसी दिन रात्रि के ११ बजे वहाँ की विप्लव हो गया। स्थान सेना ने समूची छावनी को घेर लिया और उसको घास लगा दी। यहाँ तक कि डिपेंडिपर मेजर के जाने तक की घास लगा दी गई। बगनों पर तेजाब सैनिकों ने विप्लवकारियों पर गोली चलाते से इन्कार कर दिया और कुछ समय बाद के भी उनके साथ मिल गए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि २ मिक्या तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुई और उनके बच्चों को घालि की ज्वाना के मेंट कर दिया गया। ब्रिटिश स्त्री पुरुष और बच्चे जो लवमग मस्या न ४० के विप्लवकारियों के द्वारा घेर दिए गए। यदि उदयपुर (मेराठ) के सैनिक उचित समय पर सहायता के लिए न पहुँचे होते तो मसकन उनका जीवन भी समाप्त हो जाता। ३ जून को विप्लवकारियों ने माला होला हुए दहली के

लिए प्रस्थान किया। उन्होंने आगरा जेल में बन्द सभी बंदियों को मुक्त कर दिया और सरकारी सजाने में से एक लाख छब्बीस हजार नौ सौ छाने लूटकर साथ से चले, परन्तु आगरा का प्रमुख सदर बाजार बहूत रहा।

उदयपुर महाराणा द्वारा ब्रिटिश सरकारों के प्रति सहानुभूति

जो योरोपीय विप्लवकारियों के हाथों बचकर सलुम्बर उदयपुर पहुच गए थे उनका महाराणा ने बहुत ही हार्दिक सत्कार किया। योरोपीय शरणार्थियों को पीछोला भीड़ स्थित जग मंदिर में जराण दो गई और उदयपुर के प्रधान गोकुलचन्द्र मेहता को विशपत जनकी देवभाल के लिए नियुक्त किया गया। तात्कालिक ब्रिटिश कप्तान एनेमने ने ब्रिटिश पोलिटिकल एजेन्ट कैप्टन कप्तान सी० एल० जार्व्स को अपनी रिपोर्ट भेजते हुए कहा था 'महाराणा ने ध्यनिगत रूप से हमारी दखभान में रुचि ली, उन्होंने प्रत्येक योरोपीय बालक को स्वयं अपने हाथ से दो दो सोने की मोहरें प्रदान की, सायकल पुनः पढ़ बच्चे महाराणा की सेवा में उपस्थित किए गए जहां महाराणा ने पुनः अपने और महाराणी के नाम पर दो दो स्वर्ण मुहरें और दी। वास्तव में महाराणा की दया और स्वागत सत्कार को भूला नहीं जा सकता।' ब्रिटिश सरकार ने महाराणा द्वारा दिए गए संरक्षण का विशेष रूप से 'धन्यवाद' दिया।

देवली छावनी का गूट किया जाना

नीमच के विप्लवकारी देवली भी पहुच और उन्होंने छावनी को घात लगा दी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवली छावनी में कोई भी ब्रिटिश सैनिक हताहत नहीं हुआ क्योंकि छावनी को पहुचने ही खाली किया जा चुका था और वहां से ब्रिटिश अधिकारियों को मेवाड़ स्थित जहाजपुर कस्बे में बसा दिया गया था। विप्लवकारियों ने कोण रेजीमेन्ट के ६० व्यक्तियों को देवली छावनी से अपने साथ चलन के लिए बाध्य किया परन्तु रास्ते में वे सैनिक भाग निकलने में सफल हो गए और कुछ दिनों पश्चात् वापिस देवली पहुच गए।

मासवास के समय स्थानों की स्थिति भी विस्फोटक होती जा रही थी। मानवा, महु, सलुम्बर इत्यादि स्थानों पर भी विप्लवकारियों के घातमारा टूटते जा रहे थे। उदयपुर स्थित खेरवाडा और सलुम्बर की स्थिति इतनी अधिक नाजुक बन चुकी थी कि कैप्टन जार्व्स ने विचार में इन क्षेत्रों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया था।

### मन्त्रमेर जेल में बिद्रोह

इसी बीच ६ मगरन को मन्त्रमेर स्थित केन्द्रीय कारागृह में कैदियों ने बिद्रोह कर दिया और लगभग ५० कैदी जेल से भाग छूटे । इस घटना के साथ-सुरद गहर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और स्थिति सामान्य बनी रही । मगर पुनित ने कैदियों का पीछा किया और जामे स बाधिकाज को मार डाला । इस सबमें से विशेष महत्वपूर्ण बात यह थी कि मन्त्रमेर नगर के मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और अपने आपको विप्लव से बिस्तुत दूर रखा ।

### मसीराबाद में पुन विप्लव

१२ जून, १८५७ को दीक्षा से यूरोपीय सेनाओं की प्रथम टुकड़ी मसीराबाद पहुँची और १० जुलाई १८५७ को एलेन्ड गवर्नर जनरल ने द्वारा इस टुकड़ी को नीमच भेज दिया गया । इस घटना ने मसीराबाद स्थित सैनिकों में पुन असंतोष को जन्म दिया । १२ बी बम्बई मेडिक इन्फेन्टरी के सैनिक प्रत्यक्ष उत्तेजित हो उठे, परन्तु उन्हें नीमच ही नि तारन कर दिया गया । १० अगस्त, १८५७ को बम्बई कैप्टेनरी के सैनिकों ने अपने कमांडर के आदेश को मानने से इन्कार कर दिया और अपने साथ सार्विकों को भी अपना अनुसरण करने को कहा परन्तु ब्रिटिश सरकार ने बठोर कदम उठाए । एक सैनिक को तत्काल गोली मार दी गई । पाँच और सैनिकों को फाँसी पर लटका दिया गया तथा शेष सभी भारतीय सैनिकों को नि शस्त्र कर दिया गया । इस प्रकार मसीराबाद में पुन गुप्तगती हुई विप्लव की आग को तत्काल दबा दिया गया ।

### नीमच में पुन विप्लव

१२ अगस्त, १८५७ को नीमच में द्वितीय कैप्टेनरी के कमांडर कर्नल जेम्सन ने इस सूचना के आधार पर कि भारतीय सेना में बिद्रोह होने वाला है और इनकी योजना तत्काल यूरोपीय अधिकारियों को हत्या कर देने की है, यूरोपीय सैनिकों को बुला भेजा । इस घटना ने नीमच स्थित भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया और परिणामस्वरूप वहाँ पुन अग्नि की ज्वालाएँ चमकने लगी । इस उत्तेजना में एक यूरोपीय सिपाही की हत्या कर दी गई । दो अन्य सिपाही घायल हुए और सेपटीनेट मिलेडर जिसी यूरोपीय की मदद से ही भाग्य हो गए । सैनिकों ने कर्नल जेम्सन के आदेश का पालन करने में इन्कार

कर दिया। वहाँ तक कि यूरोपीय अधिकारियों के मध्य भी आदेश दिए जाने सम्बन्धी बाद विवाद उठ सके हुए अतः यह निश्चय किया गया कि नीमच के विप्लवकारियों को दवाने के लिए और अधिक सैनिक जुटाए जाए। परन्तु इसी बीच उदयपुर के सैनिकों की सहायता से विप्लव को दबा दिया गया।

### राज बाबल का व्यवहार

इस सन्दर्भ में नीमच स्थित बाबल के० राज का व्यवहार और उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। ४ जून, १८१८ को नीमच के कार्यकारी अधीक्षक मिस्टर बर्टन ने बाबल के० राज से भेंट की। मिस्टर बर्टन के अनुसार बाबल के० राज का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही अधिक समीचीपूर्ण था। महात्मा कि राज ने यूरोपीय सैनिक व्यवस्था यूरोपीय नागरिकों की रक्षा का भार भी लेने से इन्कार कर दिया। यद्यपि नीमच के विप्लव को कुचल दिया गया था परन्तु कुछ ही दूर स्थित मदसौर में विप्लवकारी पुनः एकत्रित हो रहे थे और उनकी यह योजना थी कि मोहरम के तत्काल पश्चात् नीमच पर पुनः हमला किया जाय। मदसौर के गहनावा भी विप्लवकारियों के साथ वे और नीमच पर आक्रमण करने में सहायता देने के लिए अपने स्तर पर सैनिकों को भर्ती कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस विप्लव को कुचलने के लिए कठोरतम उपाय अपनाए गए। द्वितीय बर्ग बेवेलरी के ३ व्यक्तियों को ११ सितम्बर, १८५७ को फासी के कंदे पर लटका दिया गया और अन्य सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस घटना की साक्षी के रूप में परेड करें।

८ नवम्बर, १८१७ को विप्लवकारियों ने नीमच पर पुनः आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। लगभग चार घंटे तक ब्रिटिश सेनाओं ने इन विप्लवकारियों का सामना किया परन्तु उन्हें अन्ततः पीछे हटना पड़ा। अन्यथा यह निश्चित था कि ब्रिटेन की अधिकांश सेना को भारी क्षति पहुँचती। इसी बीच मदसौर के गहनावा ने एक "परवाना" जारी किया जिसमें प्रत्येक हिंदू और मुसलमान से अपील की गई थी कि वह विप्लवकारियों का साथ दे और घर्षों की भारत से निजालने में अपना योगदान दे। लगभग १५ दिन के नीमच के घेरे के बाद जब और ब्रिटिश कुमुक ब्रिटिश सहायता के लिए पहुँचे तो विप्लवकारियों को घेरा उठाना पड़ा। परन्तु उन्होंने हटते-हटते भी दो ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और घनेकों को पायल कर दिया।



इसी बीच २१ अगस्त को माउन्ट घाबू स्थित जोधपुर की सेंट्रल टुकड़ी ने जामिनी कर दी। साथ ही साथ उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों पर धातमरू किया जिसमें सैप्टेन हार्त, ए० लारेन्स तथा एजेन्ट गवर्नर जनरल के पुत्र गभीर रूप से घायल हुए। विप्लवकारियों ने अपने साथ लूटे हुए खजाने को लिया और वे एरनपुरा की तरफ रवाना हुए तथापि उन्हें एरनपुरा छावनी को भी लूट-भ्रष्ट किया और फिर पत्रभेर की तरफ बढ गए।

विप्लवकारी और छात्रा में उनकी गतिविधियाँ -

अगस्त, १८५७ में जामिनी की ग्यालाए सभ्यता राज्य में फैलने लगी। २१ अगस्त को एरनपुरा स्थित जोधपुर सेनापती ने बिट्टोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। परिणामतः सैप्टीमेंट कारमेलो को विप्लवकारियों के साथ चलने के लिए बाध्य होना पड़ा, यद्यपि तीन दिन पश्चात् विप्लवकारियों ने उसे रिहा कर दिया। जीन मैन्सिनी ने भी विप्लवकारियों का साथ दिया और ब्रिटिश शासन का साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। विप्लवकारियों ने अनेक ब्रिटिश नागरिक एवं अनेक परिवारों को अपनी दिगन्त में ले लिया यद्यपि कुछ समय पश्चात् उन्हें भी रिहा कर दिया। उत्तरवान् छात्रा के ठाकुर मुशाल सिंह ने भी विप्लवकारियों को सहयोग देना प्रारम्भ किया, इसका मुख्य कारण यह था कि सिद्धने कुछ वर्षों से ठाकुर मुशालसिंह और जोधपुर महाराजा के भावसी मध्य तनावपूर्ण थे और वर्तमान परिस्थितियों में ठाकुर मुशालसिंह ने अक्सर से लाभ उठाना चाहा।

८ सितम्बर, १८५७ को महाराजा जोधपुर की सेनापती और विप्लवकारियों एवं छात्रा के ठाकुर को समस्त सेनापती के मध्य भागी के समीप सम्पर्क हुआ, महाराजा जोधपुर की सेनापती को न केवल पराजय का ही मुद्दा देखा पड़ा यद्यपि उनके आदेशानुसार अल्प-संख्य विप्लवकारियों के हाथ लगे। जोधपुर स्थित के कित्तेदार कमन्डर अन्सरसिंह और महाराजा के अनेक विश्वासपात्र सहयोगी इस युद्ध में काम आए, यहाँ तक कि सैप्टीमेंट हेडकोच जिसे कि राजस्थान में ब्रिटिश एजेन्ट गवर्नर जनरल लारेन्स ने भेजा था, यही मुखिल से अपना बचाव कर सका। उसकी ममस्त सम्पत्ति विप्लवकारियों द्वारा लूट ली गई। इस गभीर परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं जनरल लारेन्स ने छात्रा की ओर कूच करने का निश्चय किया। उसने ब्यावर

क समीप सशस्त्र बटालियन तैयार का और छावा की आर चर पडा । १८ सितम्बर को जनरल 'नारेन्स' व नेतृत्व में ब्रिटिश सशस्त्र सन्नाथा न छावा पर असफल आक्रमण किया बिप्लवकारी सैनिकों ने न केवल आक्रमण को ही बिप्लव किया बलितु अनेक ब्रिटिश अधिकारियों का त्रिमम जाधपुर स्थित ब्रिटिश पालिगंघन एजेन्स मौक मन्त्र एवं एन योरोपीय अधिकारी भी शामिल था मार डाला साथ ही साथ जोधपुर सन्ना के अनेक सैनिक भी बिप्लव कारियों के हाथ मारे गए और की बना लिए गए । बिप्लवकारियों ने मौकमेसन का सर धड़ से अलग करके छावा के बिच पर गडका दिया जो एक प्रकार से उनकी बिजय का प्रतीक था । जनरल 'नारेन्स' को पीछे हटना पडा और छावा में लगभग तीन मीन दूर एक गांव में शरण लेनी पनी तदुपरांत यह अजमेर काबिल छावा । जनरल 'नारेन्स' की पराजय को ब्रिटिश सरकार ने यनी गभीरता में लिया इसका कारण यह था कि इस घटना का समूच राजस्थान पर व्यापक प्रभाव पड सकता था । अतः ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि हर कीमत पर आवा ठाकुर को कुचल लिया जाना चाहिए । उपर दूमरी ओर बिप्लवकारियों ने रिमानदार सम्बन्ध अली अम्बास अली का शेख मोहम्मद बख्श और हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के नाम पर मारवा और मेवाड की जनता से प्रतीन की कि वह उनकी हर सम्भव सहायता करे । ठाकुर कुमानसिंह ने भी मेवा के प्रमुख जागीरदार ठाकुर समर्पसिंह से ब्रिटेन में बिप्लव सहायता देने का प्रस्ताव दिया, ठाकुर समर्पसिंह ने और मारवा के अनेक प्रमुख जागीरदारों ने चार हजार सैनिकों की सहायता का आश्वासन दिया । ६ अक्टूबर १८५७ को आसोन के ठाकुर यमोनासिंह पुनर्नियाम के ठाकुर अजीतसिंह बोगावा के ठाकुर जोधसिंह बाणा के ठाकुर परमसिंह बमवाना के ठाकुर चान्सिंह तुनगिरी के ठाकुर अजयसिंह ने दिल्ली सम्राट से सहायता जन के लिए लिखा की ओर प्रस्थान किया । ठाकुर समर्पसिंह ने भी उपयुक्त जागरणों का साथ दिया ।

जनवरी १८५८ को ब्रिटिश मजिना की सहायता करने के लिए बर्बई की सैनिक टक्की नमीगवान पट्टी । माग में मिरोही के ठाकुर के प्रतीन मन्ना के बिच का नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और १६ जनवरी १८५८ को यह टुकड़ी छावा पट्टी । नम सन्ना की सहायता करने के लिए जोधपुर के कायकारी ब्रिटिश पोलिटिक्ल एजेन्ट मेजर मोरीमन भी छावा पट्टी । उपर दूमरी ओर जनरल हात्मन के नेतृत्व में बर्बई जन्म इन्फेन्ट्री भी छावा

पट्टी। तत्पश्चात् १६ जनवरी को ही कर्नेल होल्मस के नेतृत्व में घावा ज़िने पर घेरा डाल दिया गया परन्तु २३ जनवरी, १८५८ को घघकार और घर्षों व गूनाल का नापदा उठाने हुए घावा क्स्त्रसरारे बन गिरने। ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा विप्लवसरारिया का वीछा किया गया जिन्होंने १८ विप्लव कारियों को मौल के घाट उतार दिया और ७ को हिरासत में ले लिया, दूसरी घार, घावा माव में १२४ व्यक्तियों का घदी बनाया गया, ब्रिह्म ताकाल मोलियों का निशाना बना दिया गया। साथ ही माव घावा ठाकुर के निवास-स्थान को भी मिट्टी में मिता दिया गया और इस प्रकार २४ जनवरी, १८५८ को घावा पर ब्रिटिश सैनियों का कब्जा हो गया। तत्ता विश्वास किया जाता है कि सैनिक बाघबाहो के दौरान घनव निरुध नामरिकी की भी हुया की गई। जिनके जव सनिया में घटे दिगार्ई दत ॥। तैसा विश्वास किया जाता है कि ब्रिटिश सेना को भी बाकी शक्ति पट्टी और उनके कम से कम दस सैनिक घायल हुए। ब्रिटिश सैनियों न घाना में घवसर घलाचार ब्रिह्म। भीरता, भीमानिया और मन्वीश घावा को तह्प-नह्म कर काला गया और इस प्रकार जनता में भावक फैलाकर ब्रिटिश सैनिक नतीरावाद की घोर वडे।

**कोटा स्थित ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या**

१५ सितम्बर, १८५७ को मेजर बर्टन को ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा जाने का फाइल मिला। तदनुसार कोटा महाराज के वकील मेजर बर्टन को मने के लिए कीकव पट्टे। ५ अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दो पुत्रों के साथ कोटा के लिए रवाना हुए। मेजर बर्टन की पत्नी, उनकी पुत्री और उनके तीन पुत्र नीमच में ही रत गए व। १२ अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनो पुत्रों के साथ कोटा पहुच। उसी दिन दिल्ली का पतन हुआ और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अवसर पर महाराज कोटा ने लोगों की सलाहो दी। दूसरे दिन कोटा महाराज ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट ने मिलने उनके निवास-स्थान पर गए और उसी दिन शाम का पोलिटिकल एजेंट अपने दोनो पुत्रों के साथ महाराज से मिलने आए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपनी बातचीत के दौरान पोलिटिकल एजेंट ने महाराज से अनुरोध किया कि वह अपने कुछ प्रमुख सहयोगियों को पदमुक्त करदे। परन्तु १५ अक्टूबर को कोटा महाराज की दो पत्तनो न ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मेजर बर्टन, उनके दोनो पुत्र एक घसिस्टेट

सर्जन और एक स्थानीय क्रिश्चियन डॉक्टर को हत्या कर दी। यही नहीं मेजर वर्टन का सिर काट लिया गया और विप्लवकारी उसे अपने साथ लेते गए। ब्रिटिश सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। पांच महीने तक लगातार कोटा पर विप्लवकारियों का आधिपत्य रहा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मेजर वर्टन की हत्या में कोटा महाराज का भी हाथ था और संभवतः इसीलिए मेजर वर्टन को नीमच से वापिस बुलवाया गया था परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश एग्जेंट गवर्नर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार कोटा महाराज को मेजर वर्टन संबंधी आदेश-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था। मेजर वर्टन की हत्या की आश पड़ता करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कोटा महाराज को मेजर वर्टन की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। संभवतः यही कारण है कि एग्जेंट गवर्नर जनरल ने महाराज पर १५ लाख रुपये के जुर्माना करने की सफाई की थी, परंतु इस सबके बावजूद महाराज को ब्रिटिश सरकार ने दोषमुक्त ठहराया। संभवतः इसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार यह उचित नहीं समझती थी कि सार्वजनिक रूप से कोटा महाराज को विप्लवकारी घोषित किया जाय क्योंकि इसका देश के अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना थी। उधर महाराज कोटा ने अपने आपको इस घटना में बिल्कुल अलग बताया उन्होंने मेजर वर्टन की नृशंस हत्या पर दुःख प्रकट करते हुए ब्रिटेन से क्षमा-याचना की। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटेन से यह भी अनुरोध किया कि कोटा से विप्लवकारियों को हटाने में ब्रिटिश सैनिक सहायता तुरंत भेजी जाय। वास्तविकता यह थी कि कोटा पर पूर्णतः विप्लवकारियों का नियंत्रण था और कोटा महाराज एक प्रकार से अपने ही क़िस्में में बंदी थे। अतः मार्च, १८५८ में मेजर जनरल रीवट्स के नेतृत्व में ५५०० सैनिकों की एक टुकड़ी विप्लवकारियों का सफाया करने के लिए भेजी गई। २६ मार्च को नगर पर आक्रमण आरम्भ हुआ परंतु विप्लवकारी बच निकले और उनका केवल एक सैनिक हरदयान्न मारा गया। ब्रिटिश सैनिकों ने गोलाबारी की सहायता से नगर में प्रवेश किया और समूचे नगर को धूल धूमरित कर दिया।

राजस्थान में तात्यां टोपे

संभवतः राजस्थान में विप्लवकारियों का इतिहास उस समय तक प्रसूना ही रहेगा जब तक कि राजस्थान में तात्यां टोपे की गतिविधियों की

राजीव न की साथ । २२ जून १८१८ को शामी नदीपर स पराजित होने के पश्चात् तात्या टोपे राजस्थान की ओर मुखा । ऐसा विश्वास किया जाता है कि तात्या टोपे की सेना जिसमें लगभग १००० विप्लवकारी ग्वालियर के ओर लगभग ४००० भीत मजिद थे । तात्या टोपे को छात्रा थी कि उसे जयपुर ओर हाइली से आवश्यक सैनिक महाभवा प्राप्त हो सकेगी और इसलिए उसने इन राज्यों को अपने दून भी भेजे । तदनुसार यह जयपुर की ओर रवाना हुआ परन्तु उसने जयपुर पहुँचने से पूर्व ही जनरल रोमिंग जयपुर पहुँच गया, परिणामतः तात्या टोपे जयपुर पहुँचने से असमर्थ रहा । दूसरी ओर जर्मन होन्सम तात्या का पीछा कर रहा था, ऐसी प्रस्था में तात्या टोपे ने दो क्षय विप्लवकारियों-बारा के नवाब और रहीम मनी खाँ के साथ टोंक पहुँचने का निश्चय किया परन्तु टोंक के नवाब न तात्या को सहयोग देने से न वैभव इगार ही किया बल्कि उसका सामना करने के लिए अपनी सेना भी भेज दी और अचभीत होकर अपने प्रापको होने से बच भी कर दिया । लेकिन टोंक की सेनाओं ने तात्या टोपे की सेनाओं का माधवा करने के बजाय विप्लवकारियों को सहयोग दिया । इस सबसे बावजूद तात्या टोपे ने टोंक से ही टहलता उबिन नही समझा, मन यह इन्दरगढ़ और मायोपुर होता हुआ बूढ़ी पहुँचा, परन्तु उन्ने बूढ़ी महाराज से कोई सहयोग नही मिली मन सब यह मेवाड की ओर रवाना हुआ । उन्ने छात्रा थी कि उदयपुर और समुन्दर के सैनिक उसका समर्थन करेंगे परन्तु वहाँ भी तात्या टोपे को निराश होना पड़ा । कारण, ब्रिटिश अधिकारियों ने पहुँचे ही आवश्यक बरम उठा लिए थे । जनत ६ अगस्त, १८१८ को चौझगिया नदी के किनारे पर जनरल रोबर्ट्स और तात्या के मध्य सम्पर्क हुआ । तात्या सब निकला परन्तु १४ अगस्त, १८१८ को बनात नदी के किनारे एक बार फिर मुठभेड हुई, इस सम्पर्क के दौरान तात्या के लगभग ७०० व्यक्ति बाध पाए और उसकी ४ तीर्थें ब्रिटिश सैनिकों के हाथ लगी ।

इस प्रकार राजस्थान में तात्या टोपे को भारी असफलता का मुह देखा गया मन यह पम्बन नदी को पार करके आलावाड की राजधानी आलेरापटन पहुँचा । आलावाड की सेनाओं ने तात्या टोपे को सहयोग दिया नही कारण था कि आलावाड राजराजा ने अधिकार प्रत्य-प्रत्य गोला बारूद और अनेक घोड़े तात्या टोपे के हाथ लगे, साथ ही इन सैनिकों ने राजराजा के महल को नष्ट किया । तात्या टोपे ने राजस्थान से २५

साम रूप देने की मांग की जिसमें से राजाराम ने १ लाख रूपए तुरत दे दिए और उसी रात को राजाराम बहुत की ओर भाग गए। तत्पश्चात् तात्या टोपे इंदौर की ओर खाना हुआ जहाँ उनके मदद करने को होकर नैयार था। लगभग दो महीने तक मध्य भारत में रहने और छोटा उदयपुर में ब्रिगेडियर पार्क के हाथों पराजित होने के पश्चात् तात्या टोपे पुनः राजस्थान की ओर लौटा। १२ दिसम्बर, १८५८ को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया परन्तु मेजर जीन माउथ ने उसे वहाँ से भगा दिया। वहाँ से तात्या मेवाड़ पहुँचा, परन्तु वहाँ पर भी उसे मेजर रोक का सामना करना पड़ा। १३ जनवरी १८५९ को मध्य भारत के प्रमुख विप्लवकारी विन्स फिरोजगढ़ और उनके अनुयायी ने इन्दरगढ़ नामक स्थान पर तात्या टोपे की सेनाओं का साथ दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने तात्या की बैरने का असफल प्रयत्न किया और तात्या दीसा (जयपुर) की ओर भाग गया। १६ जनवरी को ब्रिगेडियर मोडर्स ने दीसा में तात्या की सेनाओं पर आक्रमण किया परन्तु तात्या टोपे फिर बच निकला और फिर २१ जनवरी, १८५९ को सीकर जा पहुँचा। जर्मन होलमस भी सीकर पहुँचा और उसी रात उसने तात्या के सैनिकों पर अचरित आक्रमण किया। विप्लवकारी सैनिक भाग गये हुए। इन पराजय के पश्चात् तात्या टोपे जगत की ओर भाग गया परन्तु नरवर के एक राजपूत जागीरदार मानसिंह के द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया। ७ अप्रैल, १८५९ को मानसिंह ने तात्या टोपे को ब्रिटिश सैनिकों के हथाने कर दिया। तत्पश्चात् १८ अप्रैल १८५९ को ब्रिटिश सरकार ने उसे फाँसी दे दी। सीकर के राज साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया और २० अगस्त, १८६२ को उन्हें भी फाँसी दे दी गई।

इस प्रकार १८५७ के विप्लव का राजस्थान पर भी प्रभाव पड़ा। मद्रवण इस घृष्टभूमि में यह अधिक उपयुक्त होगा कि राजस्थान के प्रमुख राजाओं के दृष्टिकोण की भी विवेचना की जाय जिसमें कि यह स्पष्ट हो सके कि भारत में किम सीमा तक ब्रिटिश राज का समर्थन कर रहे थे। वास्तविकता यह है कि राजस्थान के सभी प्रमुख राजाओं ने सहज होकर ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखना चाहा। इसका एकमात्र कारण यह था कि वे राजा लोग इनके प्रतिभासी नहीं थे कि अपना शासन अपने आप कर सकें। यही कारण था कि वे ब्रिटिश साम्य के अपने भक्त बन गए, क्योंकि

महजान वगैरे भारत में ब्रिटिश शासन को उनकी गरीबी की रक्षा कर सकता है।

### जयपुर

इस समय जयपुर में मुख्यतः दो दल कार्य कर रहे थे। जयपुर के महाराजा रामसिंह यहाँ ब्रिटिश की इस समय महायत्ना करने के लिए संघर्ष में थे जो जयपुर के दीवान गवर्न रामसिंह और जयपुर की सनाए ब्रिटिश विरोधी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जयपुर दीवान गवर्न गोसिंह ने महाराजा रामसिंह को परामर्श दिया था कि उन्हें ब्रिटिश और अंग्रेजों के सम्राट और ब्रिटिश के प्रति मित्रता का आह्वान आचरण करना चाहिए। इस प्रमाण उपलब्ध है कि एक यात्रा में यह कहा जा सकता है कि १८५७ के विद्रोह के समय जयपुर सनाए के ब्रिटिश सनाए के सहायता रहा की और उनके विद्रोह प्रवृत्त ब्रिटिशों के उत्पन्न करने में सहयोग दिया। यहाँ तक कि विद्रोह के दौरान ब्रिटिश हार्ड कमिन्स ने स्पष्ट रूप से कि जयपुर सनाए के ब्रिटिश सैनिकों की कोई सहायता की है और इस प्रकार जयपुर के साथ सैनिकों की गई शर्तों का उत्तरण किया है। यही नहीं जयपुर के राजा कम चारिषा में भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उत्पन्न होती थीं यही कारण है कि जने ही राजा गोसिंह गवर्न बनाया जानी का विषय समझाने का और सादरता का जब ही जयपुर गुरु ८५७ विद्रोह कर दिया गया। इसका था और सनाए का के समय का ब्रिटिश विरोधी एक व्यवहार हुआ था उसकी और का जयपुर महाराजा का ध्यान आकर्षित किया गया। इसका था के घर की तलाशी भी गई और संयम २०० रुदियार बरामद किए गए परिणामतः इसका था और उसका साथी बसायत घनी का गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें विभिन्न विचारों में डूब कर दिया गया। उपर्युक्त विवेचन इस समय का प्रमाण है कि यद्यपि जयपुर के महाराजा रामसिंह ब्रिटिश शासन के साथ सहानुभूति रखते थे परंतु वह एक जयपुर की सेनाओं और प्रशासनिक सेनाओं का मुख्य है वह विरोधी थे और साथ ही महाराजा के भी विरोधी थे।

### अलवर

अलवर के महाराजा रामसिंह एक सम्पत्ती बीषारी के दरबान् जुलाई १८५७ में स्वतन्त्र हो गए और उनके पुत्र के उत्तराधिकारी योगेश सिंह

तेरह बय की आयु में ३० जुलाई १८५७ को मनावर की राजगद्दी पर बठे । जैसे ही भारत में विप्लव होने की सूचना का समाचार चलकर पहुँचा वैसे ही चलकर मैं भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ तेजी के साथ फैलने लगीं । जयपुर के समान ही चलकर में भी दो प्रकार की शक्तियाँ काम कर रही थीं एक ब्रिटिश समर्थक और दूसरी ब्रिटिश विरोधी ब्रिटिश समर्थक सेनाओं का नेतृत्व जहाँ महाराजा मनावर कर रहे थे वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश विरोधी सैनिकों का साथ चलकर के प्रशासनिक अधिकारी और सेनाएँ कर रही थीं ।

### भरतपुर

आगरा के सत्यविक निरुद्ध होने के कारण भरतपुर विप्लवकारियों की गतिविधि में अपने आपको प्रयत्न नहीं रख सका । २८ मई १८५७ को मेजर मोरीसन ने भरतपुर रेजीडेन्सी का वायभार संभाला । ३१ मई १८५७ को भरतपुर सेनाओं ने भी विप्लवकारियों का साथ देने का निश्चय लिया । भरतपुर के अधिकारियों ने मेजर मोरीसन को यह स्पष्ट कह दिया कि उन्हें यदि अपनी सुरक्षा करनी है तो भरतपुर राज्य से ताराम भना जाना चाहिए क्योंकि यह सम्भव है कि भरतपुर के सैनिक कहीं उन पर आक्रमण न कर दें । साथ ही भरतपुर ■ अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि भरतपुर में मेजर मोरीसन की उपस्थिति नीमण के विप्लवकारियों को भरतपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर सकती है अतः यह उचित होगा मेजर मोरीसन भरतपुर छोड़कर आगरा चले जाएँ । मेजर मोरीसन ने इस परामर्श को स्वीकार कर लिया और वह आगरा आ गया लेकिन जब ५ जुलाई १८५७ को आगरा के निकट ब्रिटिश सैनिकों के साथ विप्लवकारियों का संघर्ष हुआ और ब्रिटिश सेना की आगरा के किले में बंद कर दिया गया तो मेजर मोरीसन की स्थिति की दम्भीरता का आभास हुआ । उन्होंने अपना वायभार तात्कालिक प्रथमस्क महाराजा गुलाबसिंह के मरसुम को सौंप दिया और स्वयं आगरा चले गए । यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जोधपुर की सेनाओं और प्रशासनिक अधिकारियों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ चरम सीमा पर थीं और वह हर सम्भव अवसर पर अपना ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण बना देना चाहते थे ।

### बीकानेर

समय- सभी देशी राजाओं ने बीकानेर के महाराजा ब्रिटेन को हर



मभव महायना देने में सबसे आगे थे। १८५७ के विप्लव की दबाने में महाराजा बीरानेर ने व्यक्तिगत दित्तचाम्पो दियाई, उन्होंने स्वयं अनेक स्थानों पर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विप्लवकारियों को कुचलने में योगदान दिया। विप्लवकारियों का सबसे अधिक दबाव भीमवर्गी प्रदेश हिसार और हासी पर था। महाराजा बीरानेर ने १७०० सैनिकों की टुकड़ी हिसार के लिए और लगभग १००० सैनिक एवं दो तोपें हासी की सहायता के लिए भेजी। महाराजा के इस अभूतपूर्व योगदान की ब्रिटिश सरकार ने प्रशंसा की और उनकी सेवाओं के फलस्वरूप हिसार जिले के ४५ ग्राम महाराजा को गैट स्वरूप प्रदान किए गए। महाराजा ने जनता के नाम से एक हुननगामा जारी किया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि सभी ब्रिटिश और सामंतों से सूबेदार, तामादार, अधिकारी और जमादार किसी भी रूप में विप्लवकारियों की सहायता न करें और बिना कर्न ब्रिटिश सेना के सम्मुख आकर समर्पण कर दें।

### भीमपुर :

भीमपुर के महाराजा राणा भागवतसिंह जी ने भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत बनाने में सक्रिय योगदान दिया। यहाँ तक कि महाराजा ने अपनी सेना की एक विशेष टुकड़ी पन्ना में भेजी जहाँ पर कि विप्लव होने की अधिक संभावना थी। ऐसा निश्चित किया जाता है कि ब्रिटिश सरकारों ग्वालियर से भागकर भीमपुर की ओर आ रहे थे। महाराजा भीमपुर के द्वारा इन सभी शरणार्थियों का आश्रय में महाराजा की तरफ से भावपूर्ण स्वागत किया गया। परन्तु इसके विपरीत भीमपुर के सैनिक और सरदार विप्लवकारियों के साथ सहानुभूति रखते थे यहाँ तक कि महाराजा के अधिकृत मुख्य अधिकारी विप्लवकारियों के साथ मिल चुके थे और व्यावहारिक दृष्टि से महाराजा की सत्ता केवल नाममात्र की ही रह गई थी। यहाँ तक कि भागदा से आने वाले विप्लवकारियों ने महाराजा राणा की भीमपुर में ही इस बात के लिए बाध्य किया कि वह उनकी मांगों को स्वीकार कर लें, अन्यथा महाराजा राणा का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सब सामंजस्य और हीरानाल के मेलजोल में लगभग १००० विप्लवकारियों ने अधिकतर भ्रष्ट शरद और भोला बाहद को अपने बन्धु में ले लिया और वे आश्रय की ओर वापस चले पड़े। इसी बीच इन विप्लवकारियों का ब्रिटिश सैनिकों से सामना हुआ और उनके अधिकृत अस्त्र-शस्त्र ब्रिटिशों के कब्जे में चले गए। महाराजा

राणा की सहायता के लिए पन्नाब पटियाला और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सलगभग २००० सिक्ख सैनिकों की एक टुकड़ी ४ तोपों के साथ धौनपुर भेजी गयी तब वही जाकर महाराज की सत्ता पुनः स्थापित हो सकी ।

जमी प्रकार करीबी टॉन और मानाबाद के महाराज ने भी भारत में १८५७ के विप्लव की दबाने में ब्रिटेन की हर समर्थ सहायता की सलगभग राजस्थान के सभी देशी गैरों ने उन मन धन में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बनाए रखने में अपना सन्निध योगदान दिया । परिणाम यह हुआ कि भारत में ब्रिटेन के बिरुद्ध इस प्रथम विद्रोह की सफलता पूर्वक कुचल गिया गया । ब्रिटिश शासकों ने इस विप्लव को कुचलने में कुछ न उठा रखा । यहाँ तक ब्रिटिश जेलक के (Hayes) उन ने स्वीकार किया है कि १८५७ के विप्लव की दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो गुप्त हत्याकांड किया गया है, उनके सबंध में मैं एक शब्द भी लिखना नहीं चाहता जिससे कि यह विषय विषय के सम्पूर्ण अधिक समय तक जीवित न रहे । नसीराबाद मोमच मावा और कोटा में विप्लवकारियों को कुचलने में दिन बंदर साधनों का सहारा लिया गया और जिस बेरहमी और निर्वयता के साथ उनके परिवार के साथ सदस्यों को मौत के घाट उतारा गया उसे भुलाया नहीं जा सकता । विप्लवकारियों की सम्पत्ति भी लूट ली गई और इन घटनाओं की चरम इतिथी तो सब हुई जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन सैनिक अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने नावगनिक सम्पत्ति को जी भर के लूटा था ।

क्या १८५७ का विप्लव भारतीय स्वाधीनता का प्रथम सपना रहा जा सकता है ?

१८५७ के इस विप्लव को किस नाम से पुकारा जाय प्रमाण ? क्या इसे सैनिक विद्रोह मात्र की मजा दी जाय प्रवा भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम सपना कहा जाय इस संबंध में विद्वानों में गभीर मतभेद है । जहाँ तक राजस्थान में पटिन घटनाओं का संबंध है यह स्पष्ट है कि इस क्रांति में भाग लेने वाले नागरिकों की संख्या अत्यन्त ही सीमित थी और अधिकांश जनता उत्तमोत्तम रही । वे व्यक्ति जिन्होंने विप्लवकारियों का साथ दिया वास्तव में अमनुष्ट छत्रु और जागीरदार थे जो किसी न किसी बात पर अपने महाराजा से अप्रसन्न थे । सामान्य नागरिक स्पष्ट रूप में विलकुल अलग रहा । अतः व्यापक समयान्तर के अभाव में इसे राष्ट्रीय जन विद्रोह की संज्ञा देना समस्त कठिन होगा ।

जहाँ तक भावा गूजर धामोय घोन गनुम्बर क ठाकुरो का संबंध है, यद्यपि उन्होने विप्लवकारियों का सहयोग प्रवर्ध किया परन्तु वह राष्ट्रीय भावना में प्रेरित नहीं थे। वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विप्लवकारियों को सहयोग दे रहे थे क्योंकि वे विजित मन्ता में असन्तुष्ट नहीं थे। यह तो केवल एक घमर को बात थी कि विप्लवकारी जगन्पुरा में भावा होने हुए नारनों का रहे थे, और इसी बीच भावा के ठाकुर पुनर्वासिह न उनका साथ दिया। वास्तव में यह कोई पूरा विद्योत्थित वापकम नहीं था। जहाँ तक मन्दसौर के महाजाद रिपोगाह और बीजा के महाजाद गा के द्वारा विप्लवकारियों को नेतृत्व प्रदान करने का संबंध है वास्तव में वे राष्ट्रीय भावना में प्रेरित नहीं थे, वे तो केवल धर्म के नाम पर दिनी मन्त्रा के पक्ष में लड़ने के लिए पैदा हुए थे।

दुर्भाग्य से राजस्थान के राजा महाराजाधो ने ब्रिटेन की हर सभ्य सहायता की प्रत जो भी कुछ होने लड़न विजित विरोधी भावनाएँ थी वह सामानी से कुचल दी गई। राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम की सतृप्ता जो पारवात्य जगत में स्वाधीनता कायमा की साधारणता रही है दुर्भाग्य से राजस्थान में परिलक्षित नहीं थी। वास्तव में विजित विरोधी दृश्य कुछ इने गिने व्यक्तियों का कार्य था परन्तु धीरे धीरे भारत में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना विरगित होने लगी भारतीय नागरिक भी यह समझने लगे कि स्वतंत्रता त्याग चाहती है इसी भावना ने भावे चलकर राजस्थान में और पारिपारिकों जैसे मन्तुन्नाल सेठी, विश्वमिह पबिर और राव गोपालसिह साका को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर राजस्थान के मस्तिष्क को कृपा लक्ष्य।

## सुधारों का युग और राजनैतिक चेतना का विकास

अद्यपि १८५७ का विप्लव ब्रिटिश सरकार के द्वारा सफलतापूर्वक कुचल दिया गया तथापि ब्रिटिश सरकार इस निष्कर्ष पर पहुची कि यदि उसे भारत में अपना साम्राज्य बनाये रखना है तो भारत में इडिया कंपनी के शासन के स्थान पर उसका स्वयं का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहना चाहिए। तदनुसार २ अगस्त, १८५८ को ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार भारत में ईस्ट इडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटेन के संसद भी घोषित किये गए। १ नवम्बर १८५८ को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया जहां महारानी विक्टोरिया की घोषणा भारत के प्रथम गवर्नर और वाईसरॉय लार्ड कनिंग के द्वारा पढ़कर सुनाई गई। महारानी की इस घोषणा के द्वारा ईस्ट इडिया कंपनी के साथ की गई सभी शर्तों को पुष्ट किया गया और भारत के देशी राज्य व महाराजाधों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके सभी अधिकार रक्षित किए जाएंगे और सभी रीति रिवाज और परंपराओं का पालन किया जायगा। घोषणा में यह भी कहा गया कि अब भविष्य में ब्रिटेन की नीति धर्म निरपेक्षता और निष्पक्षता पर आधारित होगी। वास्तव में महारानी विक्टोरिया की इस घोषणा ने परिणाम-स्वरूप भारत के देशी राजा महाराजा पूर्णरूप से अधीन बन गए।

राजस्थान के राजा और महाराजाओं द्वारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा का स्वागत

राजस्थान के सभी राजा और महाराजाओं के द्वारा एक स्वर से महारानी विक्टोरिया का उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया जो इस बात का प्रमाण था कि यह राजे महाराजे हर कीमत पर अपनी गद्दीया बनाए रखना चाहते थे। महारानी ने प्रति अपनी स्वाभिक्ति प्रकट करने के लिए राजस्थान के अनेक राज्यों में विभिन्न समारोह आयोजित किए गए, उदाहरणतः इस अवसर पर मेवाड़ में तार्वेजनिन स्थानों पर रोजनी की गई और धार्मिकवाजी का प्रदर्शन किया गया। इसी प्रकार यूरोपीय सैनिकों को रात्रि भोज दिया गया और राज्य के सैनिकों के मध्य मिठाई बांटी गई। तत्पश्चात् स्वास्थ्य की जायना करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। महाराणा उदयपुर के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्ञी को एक खरीबा भी भेजा गया जिसमें इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की गई थी कि भारत में ब्रिटिश सम्राट का शासन स्थापित किया गया है और राजा और महाराजाओं को प्रत्यक्ष सरकारण प्रदान किया गया है। जोधपुर, बीकान और जयपूर में भी विभिन्न समारोह आयोजित किए जाकर राजा महाराजाओं ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की, बीकान में ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट को सम्मानी दी गई और रात्रि के समय धार्मिकवाजी का प्रदर्शन किया गया।

साम्राज्ञी की घोषणा की तात्त्विक प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। ब्रिटेन के साथ अनेक समझौते हुए जिनमें नमक, रेतने, मुद्रा, डाक, और निष्क्रमण संधिया प्रमुख थी। इस प्रकार ब्रिटेन की नीति में भी परिवर्तन हुआ और अब भारतीय राजे महाराजे पूर्णतः ब्रिटेन के नियंत्रण में चले गए। सुधार-साधनों और रेत-सुविधा के विस्तार का परिणाम यह हुआ कि देशी राज्यों की आर्थिक व्यवस्था व्यावहारिक दृष्टि से ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई। वही कारण है कि अब ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के द्वारा राजस्थान के राजे महाराजाओं को यह परामर्श दिया गया कि वे भी अपने-अपने राज्यों में प्रशासनिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू करें और दिन प्रतिदिन के शासन-कार्य में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें। इसका एक परिणाम यह हुआ कि अब ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट देशी राजे महाराजाओं के आन्तरिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करते लगे। परिणामतः कुछ राज्यों में इसकी मधीर प्रतिक्रियाएँ

हुई। सुविधा की दृष्टि से यह अधिक उपयुक्त होया कि यदि राजस्थान के कुछ प्रमुख राज्यों का इस सन्दर्भ में विवेचन किया जाय।

### मेवाड़ (उदयपुर) और मुघार

१६ नवम्बर १८६१ का महाराणा स्वर्णसिंह की मृत्यु के पश्चात् मेवाड़ का समूचा प्रशासन भ्रष्टाचारी हो उठा, महाराणा के उत्तराधिकारी राणा शम्भूसिंह अभी अवयस्क थे, यह राज्य का प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के द्वारा एक परिषद् नियुक्त की गई, परन्तु वह अधिक समय तक सक्रियतापूर्वक कार्य नहीं कर सकी। इसलिए १६ अगस्त १८६३ को तत्कालिक ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार मेवाड़ का समूचा प्रशासन पोलिटिकल एजेंट ने संभाल लिया।

उपयुक्त आदेश की प्रतिक्रिया बड़ी गंभीर हुई। इस आदेश ने मेवाड़ के नागरिकों और जागीरदारों में रोष की एक सहर फैला दी और एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बसहुरा उत्सव का स्वीकार समीप था, ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट की भय था कि वही इस अवसर पर विशेष गड़बड़ी न हो जाय मत उसने अधिक सख्ता में ब्रिटिश सैनिकों की भेजने का अनुरोध किया, परन्तु इस सबके बावजूद बसहुरे के दिन यद्यपि कोई अमरु घटना तो नहीं घटी परन्तु राज्य के जागीरदारों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह मांग की गई थी कि मेवाड़ राज्य का प्रशासन पांच व्यक्तियों की परामर्शदात्री समिति के द्वारा चलाया जाय और सत्ता होने से संबंधित होने वाली घटनाओं पर किसी भी प्रकार का जुमाना न लगाया जाय तथा मेवाड़ में कस्टम क्यूटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाय। वास्तव में इस समय मेवाड़ का शासन अत्यधिक भ्रष्ट और अमरुदित था। बड़ा ग्याय के मिट्टान का कोई अस्तित्व नहीं था और शिशुमा का खरीदना और बचा जाना एक सामान्य बात थी। अभियुक्तों को अत्यंत खरंतापूर्वक दंड दिए जाते थे और सजा देते समय कानून को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। एभी अवस्था में पोलिटिकल एजेंट ईडन ने इस समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रशासन और न्यायालय ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिये। राजस्व एन्रित करने की पद्धति में भी परिवर्तन किया गया परिणाम यह हुआ कि बहुत ही कम समय में राज्य की आय २४ लाख ७५

हजार प्रतिवर्ष तक बढ़ गई, त्रिमसे से ३ लाख रुपये प्रतिवर्ष को राज्य को बचत भी हुई ।

इसी प्रकार कुछ सामाजिक मुद्धार भी लागू किए गए । पहली बार एक राजकीय विशालमय की, जिसे सम्भूरतल पाठशाला कहा जाता है—स्थापना हुई साथ ही एक राजकीय अस्पताल की भी स्थापना की गई, जिस पर एक साथ रुपये गन्ने किए गए राजकीय कारागृह। मे बस्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में भी मुद्धार किया गया और नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए गृह में सम्पत्ति संनिध भी फैला दिए गए । नगर की स्वच्छता की ओर भी ध्यान दिया गया और मन्दिरों की देखभाल एवं प्राकृतिक विपदाओं जैसे पतान, बाढ़ आदि के समय सहायता दिए जाने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई । मित्रता और बन्धों का प्रयत्न-चक्रम करना, बंधार किया जाता और सभी प्रथा को एक आदेश जारी करके समान घोषित कर दिया गया । मन्त्री का भी विकास किया गया और उदयपुर को महक माने के द्वारा जीपथ और गन्नाहा से जोड़ दिया गया ।

उपर्युक्त मुद्धारों को राज्य व जागीरदारी, अधिकारियों और जनता में सदैवास्पद दृष्टि से देना, उनका विकास था कि इन प्रकार के मुद्धार उनके रीति-रिवाज और परम्पराओं का उत्थान करते थे और यह उनके आधुनिक रूपों में मुद्रा हासिल था । इन मुद्धारों के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए समूचे उदयपुर में हड़ताल और प्रदर्शन आयोजित किए गए । इसी समय (२३ दिसम्बर, १८६३) ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि धान (स्वामी भक्ति की धर्म) लेने की प्रथा को समाप्त किया जाता है और यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे को 'धान' दिलाएगा तो वह दंड का भागी होगा । इस घोषणा ने समूचे उदयपुर गृह में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी । जनता, राज्यकीय अधिकारियों और महाराणा तक न इस प्रकार की धारणा का विरोध किया । विरोध प्रकट करने के लिए ३० मार्च, १८६४ को समूचे गृह में हड़ताल आयोजित की गई और नगर-नेट सम्मालाल के नेतृत्व में लगभग ३००० व्यक्तियों ने पोलिटिकल एजेंट ईडन के निवास स्थान के सामने प्रदर्शन किया । प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यह थी कि धान की प्रथा को पुनः शुरू किया जाए, बन्धों व स्थितियों का नव नियम जारी रहने दिया जाए और

व्यापारियों को पुलिस परेशान न करे। प्रदर्शनकारियों की यह भी मांग थी कि दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते समय नगर के प्रमुख व्यक्तियों को न्यायाधीश के रूप में प्राचीन परम्पराओं के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाय। पोलिटिकल एजेंट ने प्रदर्शनकारियों के समुच्च सरकार की नीति को स्पष्ट किया, परन्तु प्रदर्शनकारी हिनक हो उठे और उन्होंने पोलिटिकल एजेंट को न केवल गानिया ही दी बल्कि उस पर चूते और पत्थर भी फेंके। परिणामतः सशस्त्र सैनिकों ने शक्ति का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। सब प्रदर्शनकारी सहूलियों की बाड़ी की ओर रवाना हुए और उन्होंने एजेंट गवर्नर जनरल के समुच्च अपनी कठिनाइयाँ रखी। अतः एजेंट गवर्नर जनरल ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया और तब कही जाकर वातावरण शांत हुआ।

राज्य के प्रशासन को सुधारने के लिए १८७० में कुछ और सुधार लागू किए गए। सांगीरिक बातका देने के स्थान पर शुर्माना और कारावास की सजा देने की प्रवृत्ति प्रारम्भ की गई। समूचे मेवाड़ को अनेक जिलों में विभाजित किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया और रेलवे लाइन भी बिछाई गई। इसी बीच महाराणा अमर्सिंह की मृत्यु हो गई, परन्तु उनके उत्तराधिकारी महाराणा सगजनसिंह (१८७४-१८८४) ने सुधार जारी रखे और १० मार्च, १८७७ को उन्होंने एक नई राज्य परिषद् हजलास खास की स्थापना की। उपर्युक्त सुधारों के विरुद्ध एक बार पुनः उदयपुर के व्यापारियों के द्वारा आंदोलन प्रारम्भ किया गया। समूचे शहर में हड़ताल रखी गई, परन्तु इस बार महाराणा ने सख्ती के साथ सामना किया। ११ फरवरी, १८७८ को सेठ चम्पालाल और चार अन्य प्रमुख व्यापारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया महाराणा ने घोषणा की कि यदि हड़ताल तत्काल समाप्त नहीं की गई तो उनके विरुद्ध और अधिक कठोर कार्यवाही की जायेगी, परिणामतः हड़ताल बाधित ले ली गई।

आंदोलन

महाराणा फतहसिंह के अवसरक शासन-काल में नई नूतन राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारम्भ किया गया। वास्तव में इस प्रकार के आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले उदयपुर के महाजन, राज्य अधिकारी सलूम्बर के जागीरदार थे। २२ जून १८८० को रवि परगणा स्थित मानी कुण्डिया नामक स्थान पर हजारों आठ किसानों ने अवैध प्रदर्शन किया



घोर महं मीप को कि वह उस समय तक अपनी भूमियों को नहीं जोड़ेंगे जब तक कि उनकी भागे महाराजा उदयपुर के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की जाती और उन्हें दूर नहीं कर दिया जाता । १८ जुलाई १८८० को लगभग २५० किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल जिसमें मुख्य महाराज भी सम्मिलित थे, महाराजा उदयपुर से मिले, महाराजा ने प्रादोक्षणकारियों की विश्वास दिलाया कि जो मुघार लागू किए गए हैं वे उनके ही हित में हैं, और उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा । अंत में पुनर्जातिवाद समाप्त होते होते महं प्रादोक्षण भी समाप्त हो गया ।

परंतु इनका स्पष्ट है कि उदयपुर में मुघारों को लागू करने के नाम पर राज्य के प्राथमिक कार्य में ब्रिटिश का हस्तक्षेप दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा । इस ब्रिटिश-हस्तक्षेप को स्वयं महाराजा ने भी अच्छा नहीं समझा भले अनेक विषयों पर महाराजा और ब्रिटिश रेजीडेंट के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लगे । परिणामतः राज्य में दो दल बन गए, जिनमें से एक महाराजा का समर्थन करता था तो दूसरा ब्रिटिश रेजीडेंट का ।

ब्रिटेन में मुघार :

महाराजा सरदारसिंह (१८५१-१८७२) के शासन-काल में राज्य की प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई । राज्य के सभी विभागों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, यहां तक कि राज्य के दीवान वसिंत मनमूल पर भी महाराजा का कोई विश्वास नहीं रहा था । साथ ही साथ राज्य के बागीरदार भी साम्प्रतिक प्रशासनिक व्यवस्था के दिग्घट भावाग्र बने रह चुके थे । परिणामतः ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट रॉबर्ट ब्रैड फोर्ड के सुझावानुसार महाराजा को राज्य-कार्य में परामर्श देने के लिए एक पांच सदस्यीय परिषद् की स्थापना की गई, जिससे राज्य के दीवान मनमूल को भी परिषद् के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित किया गया । परिषद् का मुख्य कार्य महाराजा को प्रशासनिक कार्यों में परामर्श देना था, यद्यपि परिषद् के परामर्श को मानने के लिए महाराजा बाध्य नहीं थे तथापि महाराजा ने आश्वासन दिया कि वे परिषद् के परामर्श को मानते रहेंगे और राज्य-कार्य में सीधा हस्तक्षेप नहीं करेंगे । परंतु महाराजा ने इस आश्वासन का निर्वाह नहीं किया और व्यवहार में अपने एक अन्य विश्वासपात्र अधिकारी

वत्स्याराम को प्रशासन-व्यवस्था सौंप दी। परिणामतः सम्पूर्ण राज्य में एक समराजक स्थिति उत्पन्न हो गई।

१८८३ में महाराजा द्वारकासिंह ने शासनकाल में राज्य के जागीरदारों से रेश (जागीरदारों से उठाया जाने वाला कर) नामक कर की वसूली पर कई बार सभर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और ब्रिटिश सैनिकों को सहायता से ही स्थिति पर काबू पाया जा सका। इस प्रकार राज्य की स्थिति को देखते हुए विभिन्न मुद्दों का सामू किया जाना अत्यंत आवश्यक बन गया।

१८९६ में बीकानेर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य प्रत्यावर्तन संधि हुई जिसके अनुसार यदि कोई अपराधी ब्रिटिश राज्य में सरण लेगा तो उसे राज्य सरकार ब्रिटिश सरकार के सुपुर्द करने के लिए बाध्य होगी। इसी प्रकार १८७६ में बीकानेर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक नमक समझौता हुआ जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को भेजे जाने वाले नमक पर लगाई जाने वाली चुन्नी को समाप्त कर दिया। साथ ही साथ राज्य से भाग, गाजा, सिप्रट और आफीम के बाहर भेजे जाने पर रोक लगा दी गई। इसकी एवज में ब्रिटिश सरकार ने ६००० रुपये प्रति वर्ष और २०,००० मन नमक राज्य को देना निश्चित किया। वास्तव में इस संधि का परिणाम यह हुआ कि राज्य ने नमक को तैयार करने के अपने अधिकार को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार १८८६ में रेश, मुद्रा और डाक से संबंधित सभर्षीते हुए और इस प्रकार राज्य में विभिन्न स्तरों पर सुधार लाने किए गए।

### जोधपुर में सुधार

२६ दिसम्बर, १८९८ को ब्रिटिश एजेंट गवर्नर जनरल के मुर्काब पर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रलग से मन्त्रालय की स्थापना की गई। साथ ही १८९८ में प्रत्यावर्तन संधि और १८७० में नमक संधि भी सम्पन्न हुई जिससे अनुसार राज्य के चार प्रमुख उत्पादन केन्द्र डीडवाना, पचपडडा, फनीरी और खुनी ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर द दिए गए। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए १८७० में सम्पूर्ण प्रशासन महाराजा तत्त्वसिंह के पुत्र और राज्य के भावी उत्तराधिकारी जयचतसिंह को सौंप दिया गया। इस संबंध में यह भी कहा जाना है कि ब्रिटिश सरकार ने द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया था कि १८७० में बजमेर में जो दरबार आयोजित किया गया था वहां महाराजा तत्त्वसिंह द्वारा अपनाई गई नीति

और व्यवहार से ब्रिटिश सरकार प्रसन्न नहीं थी। कुछ भी हो, महाराजा कुमार जसवंतसिंह ने शासन-व्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक बड़ी सीमा तक राज्य में ज्ञानि और व्यवस्था स्थापित हो गई।

महाराजा जसवंतसिंह के शासनकाल में न केवल राजनैतिक सुधार ही लागू किये गये बल्कि मूलाजस्व-व्यवस्था को भी सुधारा गया। धावकारी कर-व्यवस्था को भी नियमित करने का प्रयत्न किया गया। समूचे राज्य को पांच क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक क्षेत्र एक इन्सपेक्टर के अधीन कर दिया गया। १८६४-६५ में धावकारी व्यवस्था के अधीन राजा और भाग जैसी नशीबी वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। १८६८ विदेशी शराब बेचने के लिए लाइसेंस देने की प्रथा का प्रारम्भ हुआ और इसी प्रकार राज्य की मुद्रा पर शाहवालय ने स्थान पर महाराजा की विनोदरिषा की छाप प्रकट की जाने लगी।

१८६८ से पूर्व राज्य में केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षा दी जाने की व्यवस्था थी, परन्तु अब प्राथमिक पद्धति पर आधारित नए स्कूल खोले गए। १८६३ में जसवंत कानेज की स्थापना हुई और १८६५ में महा बी० ए० की शिक्षा भी दी जाने लगी। १८८८ में बर्नस वास्टर, तत्कालीन एग्जेंट गवर्नर जनरल के नेतृत्व में जोधपुर वास्टर कृत राजपूत शिक्षाकारी सभा की स्थापना हुई जिसका एकाग्र उद्देश्य राजपूत जाति का विकास और उनकी सामाजिक कुदृष्टियों को दूर करना था।

**जोधपुर में सुधार .**

अन्य राज्यों के समान ही जोधपुर में भी विभिन्न राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक सुधार लागू किए गए। १८६७ में माठ सदस्यों की एक राज्य परिषद् बनाई गई जिसे विभिन्न प्रशासनिक विभाग सुपुर्दे किए गए। इसी प्रकार १८६० में पुलिस नियम बनाए गए, जिनकी १८७३ में पुनः समीक्षित किया गया। १८४४ में महाराजा राजेज की स्थापना हुई, जिसमें प्रारम्भ में बहाँ ४० विद्यार्थी थे वहाँ १८७५ में इनकी संख्या बढ़कर ८०० हो गई। १८४५ में एक ससून कलेज, १८६१ में राजपूत छात्रों के लिए एक विद्यालय और १८६७ में छात्राश्री के लिए एक माध्यमिक विद्यालय और मार्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स विद्यालय की स्थापना की गई। कुल मिलाकर अब ३३ राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और ३७६ प्राइवेट विद्यालय मौजूद थे, जिनमें कुल पितानेकर लगभग ८००० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे।

१८७० में प्रथम राजकीय अस्पताल की स्थापना हुई, जिनकी संख्या महाराजा रामसिंह के शासनकाल में बढ़कर २४ हो गई। इसी समय भजमेर आगरा रेलवे लाइन का निर्माण हुआ और डाक-तार-व्यवस्था भी स्थापित हुई। १८६८ में जयपुर नगर की देखभाल के लिए नगरपालिका की भी स्थापना हुई। इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि जयपुर शीघ्र ही भारत के इने-गिने व्यवस्थित राज्यों में से एक गिना जाने लगा।

### कोटा में सुधार

१८५७ के विप्लवकारियों को सफलतापूर्वक दबा देने के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के पुनर्गठन की थी। अतः ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के सुझाव पर महाराज कोटा ने राज्य में अनेक सुधार लागू किये। १८६२ में राज्य को अनेक जिलों में विभाजित किया गया और प्रत्येक जिले का प्रशासन एक जिम्मेदार की सौंप दिया गया। इसी प्रकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस विभाग पुनर्गठित किया गया और शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कोतवाल के सुपुर्द कर दी गई। विवेक बना कानूनों अथवा अधिष्ठित किया गया और सरकारी कार्यालयों के काम करने का समय निर्धारित किया गया। १८७४ में राज्य के प्रशासन की देखभाल के लिए फौजमती ला को नियुक्त किया गया, यद्यपि थोड़े ही समय पश्चात् कोटा महाराज और फौजमती ला के घापसी संबंध बिगड़ गए तथापि इस छोटी सी अवधि में फौजमती ला ने अनेक सुधार लागू किए, जिनके अंतर्गत डाक-व्यवस्था, टम्पन कचहरी का उद्घाटन एवं एक तीन सदस्यीय परिषद् की स्थापना प्रमुख थी।

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। पहली बार छात्रों एवं छात्राओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई जिस पर राज्य की ओर तब ३७६० रुपये खर्च किए गए। १८७२ में राज्य में पहले अस्पताल की स्थापना हुई जिसमें बन्हेपालाल नामक एक डॉक्टर, एक कम्पाउण्डर और एक इंसर की नियुक्ति की गई। राज्य के इतिहास में यह पहला अवसर था, जबकि दवाइयां खरीदने के लिए धनराशि स्वीकार की गई।

### भजमेर दरबार (१८७०)

२२ अक्टूबर १८७० को भारत के उत्कलसीन गवर्नर जनरल और वाइ सराय लार्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का भजमेर में

एक दरबार आयोजित किया। इस दरबार में भाग लेने के लिए लखनपुर, जोधपुर, बुंदी, कोण, जिननगढ़, भानसमरन, टोंक और बाहपुरा इत्यादि के महाराजाधो ने भाग लिया। दरबार को संबोधित करते हुए गवर्नर जनरल मेयो ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक राज्य के ग्याव जानि और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और राजाधो को चाहिए कि वे राज्य के बहुमुखी विकास में अपना योगदान दें।

प्रिन्स आफ वेल्स की भारत-यात्रा (१८७५)

वैसाकि पूर्व पृष्ठो में स्पष्ट किया जा चुका है, राज्यों में लागू किए गए मुघारों की प्रतिनिधिता अनुकूल नहीं हुई थी, परिणाम यह हुआ कि देशी राजा महाराजाधो और ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंधों में बड़ता उत्पन्न हो गई। इन घानाकरण को मन्त्र्य बनाने एवं आपसी संबंधों को मुघारों को स्थिति से ब्रिटिश सरकार ने प्रिन्स आफ वेल्स को भारत-यात्रा पर भेजने का निर्णय किया। प्रिन्स आफ वेल्स का स्वागत सत्कार करने के लिए राजस्थान के विभिन्न राजा-महाराजाधो ने आपसी होड़ होने लगी, समस्त वे ब्रिटेन के प्रति अपनी राजभक्ति का प्रदर्शित करना चाहते थे। जहां राजपूताना के सभी राजाधो को प्रिन्स आफ वेल्स के स्वागत सत्कार के लिए आमंत्रित किया गया था, वही दूसरी ओर कोड़ा के महाराव को निमंत्रित नहीं किया गया मनकर इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार कोड़ा महाराव से मेजर बर्टन हत्याकांड के मामले की लेकर असंतुष्ट थी। वहां तक कि जब महाराव कोड़ा ने तार भेजकर ब्रिटिश सरकार से यह प्रार्थना की कि उन्हें भी प्रिन्स आफ वेल्स के स्वागत सत्कार करने के लिए आमंत्रित करने की अनुमति दी जाए तो ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर कि घर बिलम्ब बहुत हो चुका है और व्यवस्था करना संभव नहीं है, कह कर महाराव की प्रार्थना को ठुकरा दिया।

१ जनवरी, १८७७ को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि से विभूषित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के सभी राजा-महाराजाधो ने दिल्ली में उपस्थित होकर सम्राज्ञी के प्रति सम्मान और निष्ठा प्रदर्शित की। इस अवसर पर जोधपुर के कवि मुरारीदान के द्वारा एक कविता भी लिखकर भेजी गई, जिसमें महारानी की चक्रवर्ती सम्राज्ञ के नाम से संबोधित किया गया था। विभिन्न राज्यों में अपने-अपने समारोह आयोजित किए गए और ब्रिटेन के प्रति स्वाधीन भक्ति का प्रदर्शन किया गया। परंतु महत्वपूर्ण

बात यह थी कि कोटा राज्य के सरदारों ने इस प्रकार के मायोजना का बहिष्कार करके अपनी ब्रिटिश विरोधी भावना का परिचय दिया।

अफगान युद्ध (१८७८-७९) और राजस्थान के राजाओं का सक्रिय सहयोग

हम देख चुके हैं कि १८५७ के विद्रोह के दौरान राजस्थान के राजा महाराजाओं ने ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन किया था, इसी प्रकार जब १८७८ में ब्रिटेन अफगान युद्ध प्रारम्भ हुआ तो भी इन राजाओं ने ब्रिटेन का ही साथ दिया। वास्तव में ब्रिटेन का समर्थन करके ये राजा महाराजा ब्रिटेन के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। भरतपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर आदि के महाराजाओं ने हर सम्भव सैनिक सहायता प्रदान की और कामना की कि शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार काबुल पर विजय प्राप्त करेगी। अफगान युद्ध की समाप्ति के पश्चात् जब ब्रिटिश अफगान संधि पर हस्ताक्षर हुए तब भी उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा आदि के महाराजाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की बधाई मदेश भेजते हुए ब्रिटेन के प्रति अपनी स्वामीभक्ति का आश्वासन दिया और अपने अपने राज्यों में विभिन्न समारोह आयोजित करके ब्रिटिश विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की।

स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज आशोसन

राजस्थान में राजनैतिक चेतना के उदय और विकास में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का अविस्मरणीय योगदान रहा है। यह वह समय था जब समूच राजस्थान में प्रसिद्ध नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति प्रेरित थे। हिन्दू धर्म में अनेक सामाजिक कुदृष्टियाँ जन्म ले चुकी थीं। इस अवसर पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने धाशा की किरण दिखाई। १० अप्रैल १८७५ को जबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। शीघ्र ही १८८० से १८९० के मध्य राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की शाखाएँ खोली गयीं। १८८३ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी मठा की स्थापना की जिसे कुछ समय बाद अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इस परोपकारिणी मठा के २३ सदस्य थे, जिनमें शाहपुरा के महाराजा उदयपुर के दीवान प्रथमाजी कृष्ण वर्मा और महादेव गोविंद रानाडे आदि प्रमुख थे। स्वामी दयानंद राजस्थान के राजाओं की रीति नीति से सन्तुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि राजा महाराजाओं

को जनता को मार्गदर्शक भन्नाई के लिए कार्य करना चाहिए जिन्होंने वि  
नागरिकों के सामाजिक और राजनैतिक बेनना का निवारण हो सके। जून,  
१८६५ में स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा की वे महाराजा  
करोली के प्रतिनिधि गये, तत्पश्चात् उन्होंने जोधपुर, प्रतापगढ़, बुध और उदयपुर  
की भी यात्रा की। ११ अगस्त १८८२ को महाराजा उदयपुर में मानवीन  
के दौरान स्वामी दयानंद ने उन बात पर बत दिया कि हमें पश्चिम का  
प्रभुत्वमय नहीं करना चाहिए और हम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा  
करनी चाहिए। ३१ मई, १८८३ को महाराजा जोधपुर के निमंत्रण पर  
स्वामी दयानंद जोधपुर पहुंचे। महाराजा जमकनसिंह के छोटे भाई सर  
प्रताप पर स्वामी दयानंद का गंभीर प्रभाव पड़ा। स्वयं महाराजा जोधपुर  
की इनने अधिकांश प्रभावित हुए कि उन्होंने मृत्युशीत और मद्यपान आदि  
दुरुस्ति पर सरकारी आदेश लगाने के निमंत्रण जारी किए। स्वामी दयानंद  
के बहुत हुए प्रभाव से अपने व्यक्ति कष्ट के घन जोधपुर में ही एक मुस्लिम  
बीबा के द्वारा उन्हें जहर दे दिया गया और ३० अक्टूबर १८८३ को प्रताप  
में उनकी मृत्यु हो गई।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के राजा महाराजों और  
जनता के नाम संदेश में मुख्यतः चार तत्वों पर बत दिया। ये चार तत्व थे—  
समर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। उनका यह परका विचार था कि  
कोई भी राष्ट्र उस समय तक उत्थित नहीं कर सकता जब तक कि वह  
अनुक्त चारों तत्वों को न अपना ले। मंत्रयन स्वामी दयानंद सरस्वती  
भारत के पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने  
पर बत दिया। उन्होंने ही १८७५ में पहली बार स्वराज्य शब्द का उपयोग  
किया जो बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला बना। स्वामी  
दयानंद सरस्वती ने हिंदी की राष्ट्रभाषा स्वीकार करने पर बत दिया।  
उनका विश्वास था कि जब तक कोई राष्ट्र अपनी ही भाषा में कार्य नहीं  
करता तब तक उस राष्ट्र की उत्थिति और विकास संभव नहीं है।

स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गये कार्य समाज आंदोलन का  
बड़ी प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह एक सामाजिक आंदोलन ही नहीं अपितु  
भारतीय नागरिकों के देश प्रेम उत्पन्न करने वाला आंदोलन भी था। सर्वाधिक  
रूप से स्वामी दयानंद का प्रभाव महाराजा जोधपुर, महाराजा उदयपुर और  
करोली के महाराज पर पड़ा। महाराजा जोधपुर ने तो यही सब आदेश जारी

कर दिये कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये छाड़ी पहनना अनिवार्य होगा। धर्म समाज आंदोलन ने अनेक सामाजिक कुसृष्टियाँ जैसे सती प्रथा बहु विवाह और पर्दा प्रथा को भी समाप्त करने में योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि राजस्थान के नागरिक राजनीतिक दृष्टि में जागृत हो उठे उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हुआ और इस प्रकार उनके हृदय में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ जन्म लेने लगीं।

---



## भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन ( १८८५-१९२४ )

१८८४ का वर्ष आन्तरिक गतिरोध की स्थापति और राजनीतिक पुनर्रचनाएँ का साल कहा जा सकता है। दशभई नारोजी और ए. ए. ए. के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप २८ दिसम्बर १८८५ को बंबई में गोकुलदास टेकपाल संस्कृत कॉलेज भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जो आगे चलकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला बनी।

भारत में कांग्रेस की याँवें केवल प्रजातन्त्रिक सुधार तक सीमित थी, परन्तु धीरे-धीरे जन-जागृति के स्वरूप इसके उद्देश्य में परिवर्तन हुआ और अंततः इसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की माँग की गई। दुर्भाग्य से राजस्थान के राजा महाराजोंसे द्वारा कांग्रेस के विच्छेद मोर्चा बनाया गया। ये राजा महाराजा कांग्रेस की नीति के प्रारम्भ से ही विरोधी थे क्योंकि वे यह जानते थे कि यदि कांग्रेस के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया तो उनके राज्य भी जनता भी अधिकारों की माँग करेंगी और उस अवस्था में उनका विरक्त शासन अधिक समय तक बना नहीं रह सकेगा। यही कारण है कि २५ अगस्त, १८८९ को महाराजा जयपुर के नाम भेजे गए अपने एक पत्र में सर संघ

अहमद खां ने इस बात पर बल दिया था कि भारतीय टिप्पणियों के राजाधों को कांग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करना चाहिए। सर सैयद अहमद खां ने इंडियन पैट्रीमोटिक एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना भी की, जिसका मद्दय्य बनने के लिए सभी राजा महाराजाधों से अनुरोध किया गया था। परन्तु सर सैयद अहमद खां के अनुसृत पत्र पर महाराजा जयपुर ने अपनी कोई प्रतिनिधिता व्यक्त नहीं की।

राजमेर में कांग्रेस कमेटी की स्थापना

/

राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। १८८७ में गवर्नमेन्ट कॉलेज राजमेर के छात्रों ने मिनहर्ष कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। १८८८ में प्रयाग (इलाहाबाद) में जार्ज यून की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुसृत अधिवेशन हुआ और पहली बार राजमेर का प्रतिनिधित्व गोरीनाथ साधु और कृष्णलाल के द्वारा किया गया। राजस्थान में राजनैतिक विकास की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी समय राजस्थान में पत्रकारिता का भी जन्म हुआ। राजस्थान का पहला पत्रिका पत्र 'राज्यन कीर्ति मुपाकर' जयपुर से प्रकाशित हुआ। १८८५ में ही राजमेर में 'राजस्थान टाइम्स' का पहला पत्र प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही पत्र का हिंदी संस्करण 'राजस्थान पत्रिका' का प्रकाशन भी शुरू हुआ। सारांश में ही इन पत्रों की नीति नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने की थी। इन पत्रों ने अपने सम्पादकीय में ब्रिटिश प्रशासन की खुलेर चालोचना की। यही कारण है कि दो वर्ष की सश्रित्त अवधि के पश्चात् यह दोनों पत्र ब्रिटिश सरकार के आदेश पर बंद कर दिए गए और इसके सम्पादक बंसी लक्ष्मणदास पर मुकदमा चलाया गया तथा १ वर्ष ६ महीने के कारावास की सजा दी गई। १८८६ में मुंशी समरचंदन चारण के द्वारा एक नए पत्र 'राजस्थान समाचार' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इस प्रकार राजस्थान में राजमेर पत्रकारिता का केंद्र-बिंदु बना और जेथ राजस्थान के नागरिकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता रहा।

कमिशनर रैंड की हत्या और स्वामीजी कृष्ण वर्मा

विभिन्न पत्रों के प्रकाशन का तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत तीव्रता से होने लगा। १८९७ में पुना में सफल पड़ा साथ ही प्लेग की महामारी भी फैली। महामारी को रोकने के लिए

ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट मयाए करने पारस हुए। इसी समय यह पसचाह फंकी कि इन इन्वेस्टमेंटों में एक का भाग उपयोग में लाया जाता है। इन सभाचार से महाराष्ट्र का आगावरण उनाकपूर्ण हो उठा। अब एक दिन जब महाराष्ट्र ने कमिन्स रेंड और अपने सहयोगी नेपटीनेट कापस्ट एक मकान से इन्वेस्टमेंट लगाकर लौट रहे थे तो उन्हें गोली मार दी गई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस घटना में स्वामीजी कृष्ण वर्मा का भी हाथ था, परंतु वे किसी तरह बच बिल्ले और इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड पहुंच कर स्वामीजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की और जातिकारी प्रतिविधियों का संचालन किया, परिणामतः जूही के एक विषय मदननाथ विगार ने १ जुलाई, १९०६ को तत्कालीन भारत के सचिव क्लब बिली को गोली मार दी।

स्वामीजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। उन्होंने आनकोटे विश्वविद्यालय से बी०ए० की परीक्षा पास की थी और अगले में बहालत प्राप्त की थी और बाद में के लखनपुर राज्य के दीवान भी नियुक्त किए गए। स्वामीजी कृष्ण वर्मा स्वामी बन्धुजी और बल्ल के उनके सम्पर्क में और अभीष्ट उन्होंने एक टैक्मटाइल मिल को भी स्थापना की। इन द्वारा उन्होंने राजस्थान में जातिकारियों की प्रतिविधियों के लिए जमीन भी तैयार की।

राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन :

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राजस्थान के नागरिकों में जन-जागृति उत्पन्न करने-देने स्वदेशी आंदोलन पारस किया गया। जैसाकि हम देख चुके हैं पाल्ठव में इस आंदोलन के जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का पारस नामरावा, मिरोही, मेवाड़ और लखनपुर में दुमा जहां स्वामी मोविन्द गिरि ने नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। मिरोही में सम्पा मया नामक सस्था की स्थापना की गई जिसका एकात्र उद्देश्य नागरिकों की प्रतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। मोविन्द गिरि के प्रभावशाली नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और केवल स्वदेशी वस्त्रों को ही पहनने का नियम किया। स्वामी मोविन्द गिरि ने नागरिकों की संस्थापना छोड़ने और अपने राजनीतिक मतकारों की शक्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। सम्पा मया

की इस प्रकार की गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी और तदनुसार १९०८ में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें सम्प्रदाय सभा की कार्यवाहियों को सम्बंध बताते हुए देशी राजाओं से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने राज्य में स्वदेशी आंदोलन को पूरी तरह कुचल दें। इस प्रकार सरकार की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की घनामयिक मृत्यु हो गई।

दिल्ली दरबार (१९०३)

रैंड और मायर्स की हत्याएं यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी कि भारत में ब्रिटिश विरोधी मानावरण बीरे-बीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। ऐसी अवस्था में वातावरण को शांत करने की दृष्टि से भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने देशी रियासतों के राजा-महाराजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए १९०३ में दिल्ली-दरबार का आयोजन किया, जिसमें इन सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। लार्ड कर्जन के इस निमन्त्रण का राजस्थान के सभी राजा महाराजाओं ने बहुत धोरदार स्वागत किया, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, सिरोही और बीकानेर इत्यादि के राजाओं ने इस अवसर को ब्रिटिश साम्राट के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने का एक उत्तम अवसर माना। सम्भवतः राजस्थान में जयपुर के महाराणा ही एकमात्र ऐसे राज्याध्यक्ष थे जिन्होंने बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ दिल्ली दरबार में उपस्थित होने की स्वीकृति भेजी थी, परंतु यह स्वीकृति भी तर्जान थी, अर्थात् जब महाराजा की यह विश्वास दिला दिया गया कि उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार ही उन्हें स्थान दिया जाएगा तब ही महाराणा दरबार में सम्मिलित होने के लिए तैयार हुए। परंतु इस सबके बावजूद जयपुर के गिरिक महाराणा के इस निर्णय से सहमत नहीं थे क्योंकि उनका विश्वास था कि ब्रिटिश राज दरबार में महाराणा की उपस्थिति जयपुर की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचावगी और साथ ही [ ] हिंदू और विशेषकर राजपूत जाति के लिए गौरव की बात नहीं होगी। यही कारण है कि जब महाराणा फतेहगढ़ दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए जयपुर से रवाना हुए तो उनके एक दरबारी नवि बारहठ केमरीगढ़ ने महाराणा की एक नविना दी जिसमें जयपुर में पूर्ववर्ती महाराणाओं के यज्ञ, वैभव और साहस की प्रशंसा की गई थी और महाराणा फतेहगढ़ को स्मरण कराया गया था कि जयपुर

राजपराने में तर्दह श्रेष्ठ परपराधो का निर्वाह दिया है, और कभी भी किसी विदेशी शक्ति के सामने मस्तन नहीं झुकाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराणा फतेहसिंह पर इस वकिला का बचीर प्रभाव पड़ा और उन्होने दिल्ली-दरबार में उपस्थित न होने का निश्चय कर लिया। ३१ दिसम्बर १६०२ को महाराणा दिल्ली पहुँचे नहीं उँहे यह जानना ही मिली कि उनका स्थान हैदराबाद, बड़ोदा, बैमूर और बागमोर के महाराजाधो के परचाह निर्धारित किया गया है। निश्चय ही यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए प्रासासन के विरुद्ध था, मत्त महाराजा यह महाना बनाकर रि. के रक्ष और उनके लड़ने लड़ो यात्रा के कारण अस्वरम हो गए हैं मत्त क्यूक का स्वागत करने और दरबार में उपस्थित होने में अनमर्ष है उदयपुर बाधत लीज गए। तबनेर जनरल महाराजा के उत्तर से स्पष्ट ही प्रसुष्ट थे, परन्तु इस समय ब्रिटिश सरकार ने महाराणा के विरुद्ध बरम उठाने का निश्चय नहीं किया।

इस प्रकार अभी एक और घबिलांन राजा और महाराजा ब्रिटेन के प्रति अपनी स्वाधी शक्ति प्रदर्शित कर रहे थे बही दूसरी ओर भारतीय जनता में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ तेजी से फैल रही थी। १६०४-५ में रुम जापान युद्ध हुआ। जापान जैसे छोटे से देश के हाथो रुस की पराजय ने भारत में एक नयी राजनैतिक चेतना को जन्म दिया। अब भारतीय भी यह विचारने लगे कि यदि जापान जैसा छोटा सा राष्ट्र रुस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को पराजित कर सकता है तो क्या भारतीय ब्रिटिश शासन से मोहा नहीं ले सकते? इसी समय कुछ लेखको ने जिनमे बकिमचन्द्र चटर्जी मुख्य थे ऐसे उपन्यास प्रकाशित किए जो राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण थे, उदाहरणत बकिमचन्द्र चटर्जी का 'मानव मर्द' और 'रुमान कुन्दला' भारत के जातिकारियों की गीता बन गया। इस प्रकार के वातावरण से राजस्थान भी प्रभावित हुए बिना न रहे तथा। बमपुर के देग भक्त बकि अन्धधर लर्मा गुलेरी ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो एक कविता लिखी जो फतेहपुर खेसावादी से प्रकाशित होने वाले एक मासिक पत्र 'देगोयकारक' में प्रकाशित हुई।

**बंगाल विभाजन (१९०५)**

१९०५-६ में भारत का राष्ट्रीय घादोलन जातिकारी और मानकवादी रूप धारण कर चुका था। इसी समय १९ मई, १९०५ को लार्ड कर्जन ने तयारकित प्रशासनिक कारणों के आधार पर बंगाल की दो भागों में

विभाजित करने की घोषणा की। वास्तव में यह क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने का एक निम्नस्तरीय कदम था। बंगाल विभाजन की घोषणा ने समूचे देश और खास तौर से बंगाल के नागरिकों को उत्तेजित कर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद में बन्देमातरम् शब्द ने एक नया महत्व ग्रहण किया। भव तो मुझ छान और नागरिक बन्देमातरम् कहकर हो एक दूसरे को अभिवादन करने लगे और इससे ब्रिटिश सरकार इतनी अधिक चिंतित हुई कि उसने बन्देमातरम् कहने पर भी रोक लगा दी।

बंगाल की हवा राजस्थान में भी पहुँचनी शायद हुई। ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन नियमों के अधीन राजस्थान के सभी राजाओं से अनुरोध किया कि वे अपने अपने राज्यों में किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी साहित्य और आतंकवादी साधन न तो छाने दें और न ही पवने दें। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड मिंटो ( १६०६ में ) ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, पलवर और बीकानेर आदि महाराजाओं को एक सदेश भेजा, जिसमें इस क्रांतिकारी आंदोलन को हर समय तरीकों से कुचल देने का निर्देश दिया गया था। अपने प्रत्युत्तर में राजस्थान के सभी राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को अपना पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। महाराजा बीकानेर ने तो भारतीय प्रेस को नियंत्रित कर देने की भी बात की। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर वृत्ति किसानगढ़ और अन्य राजाओं ने अपने अपने राज्य में आदेश जारी किए जिसके अनुसार किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी संगठन में शामिल होना अपना क्रांतिकारी साहित्य रखना या पढ़ाना और किसी भी साप्ताहिक सभा में बिना अनुमति के उपस्थित होना दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया। यही नहीं बल्कि प्रायः समाज के साहित्य को भी जप्त कर लेने के आदेश जारी कर दिए गए। इसी प्रकार ब्रिटिश विरोधी प्रचार पर भी पाबंदी लगा दी गई। इन सदन में एक महत्वपूर्ण घटना उद्घृत करना समीचीन होगा। कुमारी पेरिन मेरोजी जो कि ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी संगठन की एक सदस्य की मित्र थी—ने बीकानेर राज्य में निवृत्ति के लिए आवाहन पत्र भेजा परन्तु महाराजा बीकानेर ने न केवल उनके प्रार्थना पत्र को ही अस्वीकृत किया बल्कि राजस्थान के अन्य सभी राजाओं से भी यह अनुरोध किया कि उसे राजस्थान में वही भी निवृत्त न किया जाय। इसी समय राजस्थान के प्रायः सभी राजाओं ने एक नया आदेश जारी करके ब्रिटिश विरोधी कार्यों को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया।

महाराजा अलवर का दृष्टिकोण .

इस सन्दर्भ में अलवर के महाराजा जयसिंह देव का दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराजा अलवर ब्रिटेन को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मानने को तैयार नहीं थे और न ही वे भारत में ब्रिटिश शासन के बने रहने से प्रसन्न थे। १९०९ में जब भारत के गवर्नर जनरल अलवर की यात्रा पर आने वाले थे तो महाराजा ने वहाँ तब सुझाव दे डाला कि जिस बगाने में गवर्नर जनरल ठहरेंगे उस पर अलवर राज्य का ध्वज फहराया जाना चाहिए। इसी प्रकार जब ब्रिटिश संसद एडवर्ड सत्र में मृत्यु हुई तो महाराजा ने भले झुत्तने से इनकार कर दिया। संभवतः यह इसी घटनाओं का परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार ने महाराजा के आचरण के विरुद्ध आचरण का पत्र भेजा करने का आदेश दिया और ब्रिटिश नागरिकों को यह परामर्श दिया कि उन्हें अलवर राज्य में निष्पक्ष के लिए आदेश नहीं करना चाहिए।

राजस्थान में जातिकारी आंदोलन :

राजस्थान में सभी प्रकार की गतिविधियों पर निषेध लगा देने से बादरूढ़ भी जातिकारी आंदोलन चला देने लगा। जब भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए यथोक्तपूर्वक विचार करने लगे थे। उदाहरण के तौर पर भारतीय मुसलमानों के नाम एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उनके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में शामिल होने का अनुरोध किया गया था। इस समय उत्तर भारत में अनेक जातिकारी दल कार्य कर रहे थे जो राजस्थान के जातिकारियों से भी संबंधित थे। राजस्थान में जातिकारियों का नेतृत्व जयपुर, कोटा और अजमेर से कमल भुवनलाल सेठी, केसरीसिंह बारहट और राव गोपालसिंह एवं दासोदरदास राठी के द्वारा किया जा रहा था। अब हम संक्षेप में इन तीन प्रमुख जातिकारियों की गतिविधियों को विवेचना करेंगे।

भुवनलाल सेठी और उसका जातिकारी दल :

इस समय जयपुर का राजनैतिक वातावरण अत्यन्त ही तनावपूर्ण था, क्योंकि राज्य के द्वारा दाने अधिक निषेध लगाए जा चुके थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने विचार तब प्रकट करना असम्भव था। इस वातावरण में भी भुवनलाल सेठी और उसके जातिकारी सहयोगी ब्रिटिश शासन के

विद्वद्भ्यो योजना तैयार कर रहे थे। भजुनलाल सेठी एक सम्राट् परिवार के ग्रेजुएट थे, उन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से जयपुर में एक स्कूल प्रारम्भ किया जो वास्तव में जातिकारियों की प्रशिक्षण प्रदान किया करता था। भजुनलाल सेठी के हम विशालय में न केवल राजस्थान से ही अपितु भारत के विभिन्न भागों से जातिकारी शिक्षा दीक्षा लेने आते थे। इस प्रकार भजुनलाल सेठी का स्कूल सीधे ही राजस्थान में जातिकारी एवं मातृकावादी गतिविधियों का केन्द्र बन गया।

### निमेष हत्याकांड

तदनुसार भजुनलाल सेठी द्वारा एक धनिक महुत्त की हत्या करने का पद्धत तैयार किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि जातिकारियों के पास धन का सर्वाधिक अभाव था और मावी योजनाएँ तभी पूरी हो सकती थीं जबकि इन जातिकारियों के पास धन प्रचुर मात्रा में हो। अतः मुक्तसंसाधन स्थित एक धनिक महुत्त की हत्या कर उसके धन में घाने का निश्चय किया गया। इसके लिए भजुनलाल सेठी के स्कूल के छात्र सर्वश्री मानकचंद, मोतीचंद, जोरावरसिंह व जयचंद नियुक्त किए गए। बिष्णुदत्त के नेतृत्व में इस दल ने बनारस की ओर प्रस्थान किया और २० मार्च, १९१३ को उस धनिक महुत्त व उसके नीकर की हत्या कर दी गई परंतु कुर्माण्य से जातिकारियों ने हाथ केवल एक टाइमपीम घड़ी व पानी पीने के बर्तन के अतिरिक्त कुछ न लगा। इस समूची घटना का रहस्योद्घाटन तब हुआ जबकि शोना-रावण नामक एक मुबक जातिकारी मुखविर बन गया। परिणामतः उपर्युक्त सभी जातिकारी गिरफ्तार कर लिए गए जिनमें से मोतीचंद को मृत्युदंड तथा बिष्णुदत्त की आजीवन कारावास का दंड मिला। सबूत के अभाव में भजुनलाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

### दिल्ली पंडित कांड

२३ दिसंबर, १९१२ को भारत के गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग का जुनून बादमी चौक, दिल्ली में से होकर गुजरा और उसी समय उन पर बम फेंका गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के युवा जातिकारी पूर्णतः सक्षम हैं और पाटसराय का जीवन भी उनकी पहुँच के बाहर नहीं है। सैनिक एवं पुलिस की बड़ी व्यवस्था के मध्य पाटसराय के ऊपर बम फेंका जाना कोई मामूली बात नहीं थी। सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता



है कि यह कम रामबिहारी बोस ने फैला था, परन्तु यह प्रचिक शक्तिशाली प्रतीत नहीं होता। ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि वास्तव में यह कम रामचरण के प्रातिवारी छत्रुर जोरावरसिंह बारहठ ने जो कि जोधपुर महारानी के भूतपूर्व दोस्त थे, मुर्मा घोड़कर बादनी चौक स्थित मारवाडी सारोरी से फैला था। हाकिम बम-काठ भयवा दिल्ली-पञ्चम काठ के तिल-लिंगे ने भनेर प्रातिवारी निरफ्तार लिए गए जिनमे लावा समीरचद, सोरेलात सफे रामलाल, प्रबोध बिहारी, बाल मुबद, मोतीचद, विष्णुदत्त और मनुनलास सेठी प्रमुख थे।

इस पञ्चम काठ के फैसले के सतरांत सचिव बाल मुनन्द और मोतीचद को साई हाकिम एर कम फेंकने के सपराय में मृत्यु दंड दे दिया गया परन्तु सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह पूरा मुकदमा परिस्थितिपी ॥ सचिव सलिली पर साधारित था, प्रत्यक्ष साक्षी पर नहीं। समीरचद मुर्बार बन गया था और मशालत में किए गए उसी की गवाही से रहस्योद्घाटन हुआ कि इस पञ्चम को तैयार करने में मनुनलास सेठी का भी गहरा हाथ था। पुलिस ने मनुनलास सेठी को तो निरफ्तार कर लिया परन्तु यह रामबिहारी बोस व जोरावरसिंह बारहठ को निरफ्तार करने में समकल रही। सचिव मनुन पस मनुनलास सेठी के निरुद्ध कोई भी नामला बनाने में सकल नहीं सका इमार्ति बिना मुनदमा चलाए ही सेठी को जेल में बंद रखा गया और बाद में ५ दिसम्बर, १९१४ को जयपुर महाराजा के सादेश पर उन्हें पाँच वर्ष के कारावास की सजा दे दी गई। मनुनलास सेठी पर कोई मुनदमा नहीं चलाया जा सका, उपर्युक्त कारावास सेते तथय केवल इतना ही कहा गया था कि मनुनलास सेठी राजनीतिक पञ्चमों में सम्मिलित हैं और यह शांति व स्थिरता के लिए अभीर सतथा है। महा तक कि इस भय से कि कहीं जयपुर में शांति और स्थिरता सतरे में न पड़ जाय सेठी को महाम निज वेल्नोर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और बिना महाराजा जयपुर के सादेश के उनके जयपुर प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। बाद में १९२० में जब राजनीतिक बर्दियों को समाप्त-दान दिया गया तो मनुनलास सेठी को भी मुक्त कर दिया गया, परन्तु तबही सचिव तक कारावास में रहने के कारण रिहाई के बावजूद जेल समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं हो सका और इसीलिए अत में निराश होकर उन्होंने इस्लाय धर्म स्वीकार कर लिया, और बाद में सचमेर स्थित दरगाह में उनकी मृत्यु हो गई।

केसरीसिंह बारहठ और कोटा क्रांतिकारियों का दल

प्रजुनमान सेठी की तरह ही केसरीसिंह बारहठ ने भी कोटा में क्रांतिकारियों का संगठन बनाया जिनमें डा० गुरदत्त, लक्ष्मीनारायण और हीरानाथ लहरी प्रमुख थे। केसरीसिंह बारहठ का यह विश्वास था कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए राजस्थान में भी बंगाल में कार्य कर रही गुप्त समितियों के समान ही संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चय ही इस प्रकार के संगठनों की गठबन्धा के लिए धन की आवश्यकता थी जब इकैती और हत्या के द्वारा धन इकट्ठा करने की योजना बनाई गई। तदनुसार जोधपुर के एक धनिक साधू की हत्या करने का निश्चय किया गया। योजनानुसार प्यारेताल साधू को जोधपुर से कोटा लाने के लिए रामकरण नामक एक क्रांतिकारी को भेजा गया जो साधू को मकसदापूर्वक २३ जून, १९१२ को कोटा लाया। तत्पश्चात् साधू को दूर में मिलाकर जहर दे दिया गया परन्तु जब इसका प्रभाव होना दिखाई नहीं दिया तो २५ जून, १९१२ को हीरानाथ साहिरी ने साधू की हत्या कर दी। जवरदस्त चौधरीन व जाध पयस्तान के बाबूद पुनित किसी भी व्यक्ति को सशस्त्र ९ माह तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुनित द्वारा क्रांतिकारियों को पकड़ने में सफलता तब मिली जबकि रामकरण द्वारा केसरीसिंह बारहठ को गुप्त भाषा में लिखा गया एक पत्र पकड़ा गया। इस पत्र में यह कहा गया था कि जब तक घाटा खराब हो गया होगा तब उसे चबल में मछलियों को खिलाने के लिए फेंक दिया जाए। स्पष्टतः ही इसका अर्थ यह था कि साधू के अवशेष नदी में फेंक दिए जाए जिससे कि पुनित को हत्या किए जाने का कोई प्रमाण न मिल सके। परिणामतः केसरीसिंह बारहठ हीरानाथ साहिरी रामकरण और हीरानाथ जाधरी को साधू की हत्या किए जाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में वे हीरानाथ लक्ष्मीलाल कायस्थ मुखद्विर बन गया। केसरीसिंह बारहठ, हीरानाथ साहिरी और रामकरण को २०-२० वर्ष का कारावास तथा हीरानाथ जाधरी को मान वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। प्रथम महायुद्ध के बाद १९१६ में जब राजनीतिक बंदियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्षमा क्षमा दी गई तो धुन से केसरीसिंह बारहठ को भी रिहा कर दिया गया।

राय गोपालसिंह और क्रांतिकारी दल

छत्रमेर व परवा के राज गोपालसिंह व कृष्णा प्रियस नि० व्यास

के ठेठ दामोदरदास राठी राजस्थान में जातिकारी चांदोलन से परिचित रूप से अवगत थे। राज गोपालसिंह जहाँ योजनाओं को कार्य रूप देते थे वहीं ठेठ दामोदरदास जातिकारियों को भाषित सहायता देते थे। राज गोपालसिंह जातिकारियों के लिए मसन-जसन की भी व्यवस्था करते थे और इन कार्य में भूमिसिंह उर्फ बिजयसिंह बख्त भी उनकी सहायता करते थे। राज गोपालसिंह समान के प्रतिष्ठित जातिकारी राज बिहारी बोट और बेतारीसिंह बारहूट से भी गुप्त रूप में सम्पर्क स्थापित किए हुए थे। वाराणसी में भजमेर के इन जातिकारी दल का पता निमेष हुआरांड और बोट के हाथों की हुला के तिलसिंहे से लगा। इन राजस्थान में एजेंट गवर्नर जनरल ने राज को चेतावनी दी कि वे अपने मानको प्रिटिबि विरोधी एक जातिकारी गतिविधियों से अलग रहें, वरतु राज पर इस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने प्रथम महापुंड के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सार्वजनिक जाति की योजना बनाई।

**सार्वजनिक जाति योजना और प्रथम महापुंड .**

१९१४ में जब यूरोप प्रथम महापुंड में उत्पन्न हुआ था तो उत्तर भारत में सार्वजनिक जाति करने की योजना बनाई जा रही थी। राज बिहारी बोट और सविन्द्रनाथ सनियास इस सार्वजनिक जाति की योजना के वर्णधार थे। राजस्थान के जातिकारी मोरारसिंह बारवा भी इस योजना से संबंधित थे। राज बिहारी बोट के एक मदेशवाहक मलीमाल ने फरवरी १९१५ के मध्य सारवा की यात्रा की थी और यह संदेश दिया था कि २१ फरवरी १९१५ का दिन सार्वजनिक जाति करने के लिए निश्चित किया गया है और जाति का सारभ राज बिहारी बोट के द्वारा दिल्ली पर आयोजित करके सारभ दिया जाएगा। राज बिहारी बोट ने अपने संदेश में राज गोपालसिंह से सविन्द्र सहायता देने का अनुरोध किया था। राज गोपालसिंह को भी यह यात्रा थी कि यदि जाति हुई तो जोधपुर के सर प्रताप उसरी सक्रिय सहायता करेंगे। ऐसा विश्वास दिया जाता है कि बीकानेर और जोधपुर के महाराजाओं की महानुभूति जातिकारियों के साथ थी और वे सार्वजनिक जाति की सफलता के परभाव उदयपुर के महाराजा फतेहसिंह को दिल्ली का सम्पाद घोषित करना चाहते थे। ऐसी भी यात्रा व्यक्त की गई थी कि मुल्तान, लाहौर और मेरठ की सेनाएं राज बिहारी बोट का साथ देंगी और इस अवस्था में राज गोपालसिंह के नेतृत्व में जोधपुर और बीकानेर की सेनाएं भजमेर पर आक्रमण

करेंगी। तदनुसार राव गोपालसिंह और प्रतापसिंह उन्हें विजयसिंह पक्षिक भजमेर नजीराबाद रेलवे लाइन के समीप एक जंगल में घटो सकते की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु उन्हें पानि करने का कोई संदेश नहीं मिला। इसका कारण यह था कि मणिलाल मुखर्विर बन गया था और उसने अधिकारियों के साथ विश्वासघात करके योजना की समस्त सूचना पुलिस को दे दी थी, परिणामतः योजना विफल हो गई। ब्रिटिश सरकार ने २६ जून, १९१५ को राव गोपाल सिंह को आदेश दिया कि वे २४ घंटे के भदर-भदर खारवा को छोड़ दें और टाडगढ़ पहुंचकर ३६ घंटे के दौरान अपने अपने की सूचना तहसीलदार को दें। आदेश में यह भी कहा गया था कि टाडगढ़ निवास के दौरान राव गोपाल सिंह, तहसीलदार की पूर्ण अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल सकेंगे और उनके समस्त डाक पत्र तहसीलदार के द्वारा ही उन्हें भेजे जाएंगे। आदेश के अनुसार राव गोपालसिंह को दिन में एक बार अपनी उपस्थिति तहसीलदार के सम्मुख दर्ज कराना थी, और बिना तहसीलदार की अनुमति के वे टाडगढ़ की सीमा से बाहर नहीं जा सकते थे। आदेश के उल्लंघन करने पर जुर्माना और तीन वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता था। राव गोपालसिंह को टाडगढ़ के लिए रवाना होना पड़ा, जहाँ वे चलते समय अपने अव्यक्त उत्तराधिकारी गणपतिसिंह को जो उन्हें ब्यावर तक छोड़ने थाया था, कहा कि—अपने देश के प्रति बफादार रहना।

१० जुलाई १९१५ को राव गोपालसिंह टाडगढ़ से बच निकला परंतु बाद में २५ अगस्त, १९१५ को सलायबाद (विशनगढ़) स्थित एक शिवालय में राव ने पुलिस के समक्ष इस घोषणापत्र पर आत्मभ्रमपत्र कर दिया कि उसे एक राजनीतिक अभियुक्त माना जावेगा। तत्पश्चात् भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का आचारण कारावास का दण्ड दिया गया। राव गोपालसिंह को कानूनी सहायता देने में इनकार कर दिया और खारवा ग्राम सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय बाद राव गोपालसिंह को गाइबहापुर स्थित बिहार जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया।

प्रतापसिंह बारहठ और राजिन्द्रनाथ सन्निपाद की गतिविधियाँ -

यत्र घटना चक्र तेजी से घूम रहा था, भर्तृहरिदास सेठी, केसरीसिंह बारहठ और राव गोपालसिंह खारवा विरपनार हो चुके थे अतः अब जाति-कारी दल का नेतृत्व प्रतापसिंह बारहठ, बृजमोहनसाल और छोटेला के हाथों

में प्रताप । प्रतापसिंह बारहूट एक उत्साही क्रान्तिकारी था और उसने एक बार फिर भारतीय सेना से मिलकर सशस्त्र जाति करने की योजना बनाई । मानवक सहयोग एवं सशस्त्र शस्त्र की प्राप्ति के लिए पिछले को घेरठ भेजा गया । साथ ही वह भी नियंत्रण किया गया कि जाति आरम्भ करने के संकेत के रूप में भारत सरकार से कुछ सदस्य सर्व रेगिमेंटरी फंडोस की हत्या कर दी जाए । फंडोस की हत्या करने की जिम्मेदारी जयचन्द नामक एक क्रान्तिकारी को सौंपी गई जो हरिद्वार में वाचा वाली कम्पनी वाला के आश्रम में ठहरा हुआ था । अतः एक अन्य क्रान्तिकारी रामनारायण चौधरी को हरिद्वार भेजा गया जिससे कि वह जयचन्द को साथ ला सके । पुलिस की कड़ी व्यवस्था के बावजूद रामनारायण चौधरी सम्पत्तापूर्वक हरिद्वार पहुँच गए परन्तु जयचन्द ने वहाँ से चलने में समयवैता-वक की क्योंकि उग समय वह एक मोर बँसती बालने में व्यस्त था । परिणामतः रामनारायण चौधरी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा । मध्य क्रान्तिकारियों ने फंडोस की हत्या करने की जिम्मेदारी प्रतापसिंह बारहूट को सौंपी, परन्तु फंडोस निश्चिन्त समय पर नहीं पहुँचा और इस प्रकार उसकी हत्या नहीं हो सकी । दूसरी ओर घेरठ में पिछले को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह सशस्त्र शस्त्रों के साथ वहाँ से रवाना होने ही वाला था, और इस प्रकार जाति की सम्पन्न योजना छिन्न भिन्न हो गयी ।

**प्रतापसिंह बारहूट की गिरफ्तारी और बनारस-वडवान्त-काठ**

बनारस-वडवान्त-काठ के मिलनिय में प्रतापसिंह बारहूट के बिछड़ गिरफ्तारी के बारट जारी हो चुके थे, परन्तु वह भूमिगत हो गया और हैदराबाद (मिन्ग) के एक घरनाल में बम्पाउन्डर बन गया । इसी बीच पुलिस को प्रताप के बारे में खबर मिली और वह सोचबोच करते करते जयपुर पहुँच गयी । पुलिस द्वारा प्रताप के परिवार को बहुत धक्का लगाए जाने पर वह बड़ा दिया गया कि प्रताप हैदराबाद में है परन्तु हैदराबाद (मिन्ग) के स्थान पर हैदराबाद (दक्षिण) का पता दे दिया । परिणामतः पुलिस हैदराबाद दक्षिण की ओर रवाना हुई और तब प्रताप के मुख्य सहयोगी रामनारायण चौधरी हैदराबाद मिन्ग की ओर रवाना हुए, जिससे कि प्रताप को मध्य सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके । अतः पुलिस से बचने के लिए प्रताप हैदराबाद से रवाना हुआ और जोखपुर ने निकट आसानादा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से जो कि उन्हीं के दल का एक सदस्य था, मिलने के लिए

उपर पड़ा। परन्तु कुछ ही दिन पूर्व भामानादा स्टेशन पर बम की एक धारसल बरामद हुई थी और प्रपने भाषको बचाने के लिए स्टेशन मास्टर मुखबिर बन गया था। परिणाम यह हुआ कि प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बनारस पड़यंत्र के सिनमिन में पांच वर्ष के कारावास की सजा दी गई। निर्णय में यह भी कहा गया था कि जानिफ़रियों ने मध्य भारत के सातकबादियों के सम्पर्क साधनों में प्रताप की सेवाओं का सहारा लिया था।

### रामनारायण चौधरी की गतिविधियाँ

जब प्रतापसिंह बारहठ भामानादा रेलवे स्टेशन पर उतरा था तब यह निश्चय किया गया था कि रामनारायण चौधरी उसी बीकानेर में प्रतीभा करेगा। अतः जब प्रताप बीकानेर नहीं पहुँचा तो योजनानुसार रामनारायण चौधरी ने भामानादा के स्टेशन मास्टर को एक पत्र लिखा। यह पत्र पुलिस के हाथ लग गया और तीन दिन के बाद ही भन्दर सी घाई की पुलिस इन्स्पेक्टर मगनराज व्यास रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार करने बीकानेर पहुँचे परन्तु चौधरी के भाचा के प्रभाव के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। रामनारायण चौधरी पुलिस से दबने के लिए जयपुर पहुँच गए जहाँ यह निश्चय किया गया कि उसे भूमिगत हो जाना चाहिए और सामर में कृष्णा सोडानी नामक एक भय आधिकारी के साथ रहना चाहिए। नवम्बर, १९१५ में जब बनारस पड़यंत्र कांड के निमित्तने में सचिदनाथ सचियाल और प्रतापसिंह बारहठ को लम्बे लम्बे कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी उस समय रामनारायण चौधरी बीम का शिकार (किमा सीकर) स्थित अपने निवास स्थान परिसर लौग परन्तु यहाँ भी सी घाई की इन्स्पेक्टर मगनराज व्यास उनका पीछा कर रहा था। अतः यह निश्चय किया गया कि किसी तरह मगनराज व्यास को भयनेर ले जाया जाय और वहाँ छोटेनाम नामक एक आधिकारी उसे गोली मार दे। परन्तु योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। तत्पश्चात् रामनारायण चौधरी रामगढ़ जेलावाटी के एक मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गया उसने वहाँ भी आधिकारी दण का सम्पर्क किया परन्तु यह मगडन कोई विशेष कार्य नहीं कर सका।

१९१५ में जयपुर के एक जैन वकील ने जयपुर के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश रेजिडेंट के विरुद्ध कुछ हस्तहार बांटे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हस्तहार का प्रारूप रामनारायण चौधरी के द्वारा तैयार किया गया था

और एक साद्विधि जाने की दुकान पर जैन बकील ने इसे साइकलीस्टाइम लिया था तथा मजदूर विलास कंपनी ने मैनेजर के द्वारा इसे खिचलिया किया गया था। चलने ही दिन गहर के सभी प्रमुख स्थानों रात्रभवत, स्कूल और जानेद व पुलिस थानों पर उपर्युक्त हथियार बिखरे हुए देते गए। काफी खोजबीन के बाद साइकलीस्टाइम दफ्तार का एक वर्क जैन बकील के महा से बरामद हुआ, उसके साथियों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा जैन बकील को भारी धाकड़ा दी गई, परन्तु चला तक चलने चलने सहयोगियों का नाम नहीं बताया और इस प्रकार जैन बकील के अन्य जानिबारी सहयोगियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

**प्रथम महापुछ और भारतीय राजाओं का इतिहास :**

इन, १९१४ के प्रथम महापुछ धारम्भ हुआ। महात्मा गांधी का विचार था कि इस विपत्ति के समय भारत को ब्रिटेन की तन, मन धन से सहायता करनी चाहिए। देशी राज्यों के राजा भी ब्रिटेन को हर समय सहायता दिए जाने के पक्ष में थे, तदनुसार बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जलन्धर, भरतपुर, धौलपुर इत्यादि सभी राजाओं ने ब्रिटेन को हर समय सहायता दी। देशी राजाओं द्वारा ब्रिटेन को सहायता दिए जाने का एक कारण यह भी था कि वे लोग इस समय के भारतीय परिचित थे कि ब्रिटिश-शासन ही उनकी पहिचान को बचाए रख सकता है।

**प्रथम महापुछ की समाप्ति और विभिन्न राजनीतिक गतिरिधियाँ :**

१९१९ के प्रथम महापुछ समाप्त हुआ। भारत में पान्टंगू वेम्सफोर्ड दुबारा लागू किए गए। इन सुधारों के प्रारम्भ देशी राज्यों के गवर्नरमण्डल की भी स्थापना हुई। साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश विरोधी मान्दोलन ने एक नया रूप धारण किया और भारत में मान्दोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने संभाला और इस प्रकार जनताकारी मान्दोलन के स्थान पर धार्मिक मान्दोलन धारम्भ हुआ। इन समय राजस्थान में दो नए समाचार पत्रों 'राजस्थान केसरी' और 'तारा राजस्थान' का प्रकाशन धारम्भ हुआ। इन समाचार पत्रों का एक-मात्र उद्देश्य मान्दोलन की जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना था साथ ही विभिन्न राज्यों में होने वाले मान्दोलनों के प्रति राजस्थान की जनता का ध्यान आकषित करना था। राजस्थान केसरी के सम्पादक विजयसिंह पणिकर ने तथा समाचारपत्र धौलपुरी, हरिनाई किकर और कन्हैयालाल कलसिंह उनके

महोपाधी थे । प्रभु नानास सेठी और नेनरीसिंह बारहठ ने पत्र लिखकर जन-जागृति में योगदान दिया । इस समय घग्गेर में मुख्यतः तीन दल कार्य कर रहे थे । पहले दल का नेतृत्व विजयसिंह पथिक, दूसरे दल का नेतृत्व प्रभु नानास सेठी और तीसरे दल का नेतृत्व गाबीवादी जमनालाल बजाज और हरिभाऊ जगध्याम के हाथों में था ।

१५ मार्च, १९२१ को राजस्थान पोलिटिकल कौंसिल का द्वितीय अधिवेशन मोनीलाल मेहता की अध्यक्षता में घग्गेर में सम्पन्न हुआ । इन कार्यक्रमों में एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया जिसमें मुसलमानों से असहयोग-आन्दोलन के समर्थन करने की अपील की गई थी और साथ ही प्रत्येक भारतीय नागरिक से यह मांग की गई थी कि वे विदेशी वस्तुओं और वस्तुओं का बहिष्कार करें । घग्गेर में भी असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । पथिक गौरीशंकर घग्गेर के उन प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने महारथ गांधी के सत्ये सिद्ध के रूप में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया । प्रथम महापुरुष के पञ्चान्न दिनेश के द्वारा राजनीतिक कैदियों को भोजन उपहार दिया गया, पत्र राजस्थान के गानिकारी नेना प्रभु नानास सेठी, नेनरीसिंह बारहठ और गाब गोपालसिंह रिहा कर दिए गए । एक बार फिर राजनैतिक हलचल प्रारम्भ हुई और परिणामतः मार्च १९२० में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 'राजस्थान मध्यभारत' सभा की स्थापना हुई । साथ ही साथ १९१६ में वर्षों में "राजस्थान सेवा सभ" की भी स्थापना की गई जिसे १९२० में घग्गेर में स्थानान्तरित कर दिया गया । इस सभ का मुख्य उद्देश्य जनता की कठिनाइयाँ दूर करना और जनता और जागीरदारों के बीच तटस्थ बनाना था । बूडी, जयपुर, बीकानेर और कोटा में सेवामण की प्रत्येक शाखाएँ स्थापित की गई । परन्तु सभ के पदाधिकारियों में व्यापक मतभेद होने लगे कि १९२८ के अन्त तक एक प्रकार से सभ समाप्त हो गया ।

### राष्ट्रीय कांग्रेस का दृष्टिकोण (१९२१-२४)

कांग्रेस ने १९२५ में ही राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने की नीति अपना रखी थी । १९२० में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, साथ ही साथ 'राजस्थान मध्यभारत सभा' का भी अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था जिसमें देशी रियासतों की जनता पर होने वाले अन्यायों की बहारी को दर्शाया गया था, साथ ही जनता की गरीबी और अविश्वसनीय व्यवस्था का भी चित्रण किया गया था । परिणाम



यह हुआ कि कांग्रेस ने पत्र राज्यों की जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना आरम्भ किया। १९२१ में कांग्रेस ने मनहरोर-आन्दोलन आरम्भ करने सबसे प्रस्ताव पारित किया। इसी बीच राजस्थान में भी विशेषतः विजोलिया (जूदी) देगू (मेवाड़) और केरावाटी (अजमेर) में किसान आन्दोलन भड़क उठा।

### विजोलिया आन्दोलन (१९१९-२२)

१९१९ में पहले साधु सीताराम दास और बाद में विजयसिंह पथिक के नेतृत्व में विजोलिया आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य जागीरदारों द्वारा विजोलिया की जनता पर लगाया गए करोड़ों विभिन्न साम्राज्य के विरुद्ध आवाज उठाना था। विभिन्न रथोंद्वारा एवं घवसरीयों पर जैसे फसल की कटाई, विवाह, जन्मदिन समारोह और जागीरदार के विभिन्न सामाजिक उत्सव पर प्रत्येक किसान को एक निश्चित भाषा में बोलना पड़ता था और इन्हें बोलने की अवस्था में उसे भारी शारीरिक मानव सहायता पड़ती थी। इसी प्रकार बेकार प्रथा प्रचलित थी। परिणाम यह हुआ था कि कुछ दिनों में शान्त एक परिवर्तन करने के बाद किसानों ने लिए गए पेट भोजन पर सहायता प्रदान हो गया था। समूचे इलाके में जागीरदारों के जुल्म का बीजबाना था और ग्राम जैसे मित्रता की समाप्ति हो चुकी थी। अतः विजोलिया के किसानों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए एक वर्ष तक के लिए खेती करना स्थगित कर लिया और साथ ही साथ भूराजस्व देने से इन्कार कर दिया। इस समय आन्दोलन का नेतृत्व साधु सीतारामदास कर रहे थे परन्तु इसी बीच १९२५ में के विजोलिया में विजयसिंह पथिक से मिले और उनके आन्दोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया। साधु सीताराम दास ने जागीरदारों द्वारा असहाय जनता पर किए जाने वाले नुकसान पर जागीरदारों की कहानी सुनाई। पथिक ने नेतृत्व संभालना स्वीकार किया और इस प्रकार विजोलिया आन्दोलन को एक नया उत्साही और साहसी नेता मिला। १९२६ में विजोलिया के किसानों ने साधु सीताराम की अध्यक्षता में एक किसान पंच-बोर्ड की स्थापना की। विजयसिंह पथिक से प्रेरणा पाकर विजोलिया के किसानों ने मुद्रा प्रत्यक्ष देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने जागीरदारों को किसी भी प्रकार का सहयोग देने से इन्कार कर दिया और स्थिति बहुत तब तक बिगड़ गई कि किसान पंचायत ने निर्णय ले लिया कि वे प्रत्यक्ष रूप से जागीरदारों से कोई संबंध नहीं रखेंगे और बचान के माध्यम से ही सब कार्य होंगे। स्थिति



यही कारण है कि कई बार ए. बी. जी. ने जिसना व्यक्तिगतियों को डाट लिया और कहा उन बहुत दिनों में वेकम गुन्ना नहीं चाहता। घन ए. बी. जी. ने हमारे के परिणामस्वरूप जिसके क. मा. केरदारों और जिसी जिसी किमती के मध्य समझौता सम्पन्न हुआ। सबभौने के अनुसार जिसनों की घनेन मागे स्वीकार करनी गई जिसने केमर प्रकाश की मध्याह्न और व्यक्ति-बांध मालबाध का सम्पूर्ण सम्पत्ति न. त. मा. पर भी न. प्रकाश कि जिसनों के विरुद्ध करने जाने मुद्रादेन कातिन न. निर. न. न. घोर निर. र. र. ए. बी. जी. की गई है उसका भूराश्रय यही निर. तादात। इस प्रकार मदेमालरु के उत्पत्ती के बीच १९२२ म. जिसी निर. घा. न. न. म. फ. न. ता. न. न. समाप्त हुआ।

**११. पाठ्योपन (१९२१-२२) :**

शिवजीविद्या-महाप्रह की मंत्रवना म धेनि नील देव के विमानों में भी छिपाने के प्रयासों के विरुद्ध साक्षात्कार पारंगत विद्या धरनु छिपाने के रास्ता टाटकर मैं हमन चक्र की महान विद्या को न पाश्र्विक की गोपी मार देने तक की धमकी दी। राजस्थान के मा मंत्र मीन मन्त्रिणात्मक के प्रवर्तकों के फलस्वरूप पीछे पीछे जन शत्रुति हो रही था। विद्या के निराप विद्या या कि घर के मन्त्रान नहीं करेगा, छूटा हुआ की मन्त्रान कर देने की मन्त्रिणी बहन धारण करेंगे। निश्चय ही हम बका - विद्या के विद्या जागीरदार और शक्ति भयभीत हो उठे की न मान घ. मन्त्रान की दुबाने न विद्या हर तरह के हिमात्मक सत्ता मानाए तथा न विद्या के मन्त्रान मन्त्रान के विद्या के साथ भी समझना एक बर्बरता पूर्ण मन्त्रान विद्या विद्या मन्त्रान मन्त्रान विद्या माना गठित है।

राजस्थान सेवानाम की घोर से रामनारायण चौधरी ने बेगू पहुंच कर स्थिति का मा'खन किया । उन्होंने देखा कि उन्हूँ के स्वामीय सेठ अमृत लाल घोर पुलिस के आ'गवा'रों ने उ'ड़ाने अ'र्पणीय है । बेगू के किसानों ने मेराठ के देखे'रू कमिश्नर मिस्टर ट्रेच से ह'म'ने'न की घ'ने'न की । १३ जुलाई, १९२३ को ट्रेच एक सैनिक टुकड़ी के साथ मोरिंदपुरा गांव पहुंचा घोर किसानों की मददना करने के स्वाम पर अपने गांव की आ'ग लगा देने घोर किसानों पर गोली चला देने का आदेश दिया । ऐसा रि'वा'स किया गया है कि दो व्यक्तियों की मददना करने पर ही मृत्यु हो गई घोर घने'क

घायल हो गए। १०० बच्चों सहित लगभग ५०० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिन्हें दुरी तरह पीटा गया और बेधुं से जाया गया। इस दमन-चक्र के दौरान सिपाही घरों तक में घुम गए और उन्होंने स्त्रियों का बड़े ही शर्मनाक ढंग से सनीत्व हरण किया। परिणामतः बानावरण भयानक उत्तेजित हो गया और किसानों ने रावदा ठाकुर को हत्या तक करने का निश्चय कर लिया। जनता के संघर्ष और उनके साहस को बनाए रखने के लिए विजयसिंह पब्लिक और हरिजी मानक गुप्त रूप से बेधू पकड़ गए परंतु पुलिस को पता चल गया और वे दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। पब्लिक को उदयपुर लाया गया जहां उन पर राज्य विरोधी कार्य करने, छात्रकवादी साहित्य को वितरित करने और महाराणा उदयपुर के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मुकदमे के दौरान विजयसिंह पब्लिक ने इस बात पर बल दिया कि देश भक्त होना कोई अपराध नहीं है और भत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना व्यक्ति का अधिकार है। यद्यपि पब्लिक के विरुद्ध नियुक्त किए गए प्रायोग ने उन्हें रिहा कर दिया तथापि मेवाड़ सरकार ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें पांच वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया। १९२८ में पब्लिक को रिहा कर दिया गया और साथ ही मेवाड़ से निष्कासित भी कर दिया। मेवाड़ राज्य और ठिकाने के अधिकारियों के द्वारा किसानों पर किए जाने वाले भत्याचारों की कहानियां प्रत्येक समाचार पत्र में प्रकाशित हुईं, यहाँ तक कि ब्रिटिश संसद में भी प्रश्न उठाया गया। जनतः ठिकाना अधिकारियों और किसानों के मध्य समझौता हुआ जिसके अंतर्गत किसानों की अधिकार मांगें स्वीकार कर ली गईं।

**बूंदी और शेवासाटी में किसान आंदोलन :**

ब्रिटीशिया और बेधू के किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बूंदी के किसानों ने भी आंदोलन प्रारंभ किया। बूंदी में भी किसानों को घने प्रकार की लाग देनी पड़ती थी और उनसे बेगार भी ली जाती थी। इसके प्रतिरिक्त समूचे राज्य में सार्वजनिक समारोहों, राष्ट्रीय गान और नारों पर पूर्ण प्रतिबंध था। अतः १५ जून, १९२२ को बूंदी के किसानों ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। राज्य ने दमन चक्र का सहारा लिया, परिणामतः संकड़ों किसान गिरफ्तार किए गए जिनमें से दो की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस समय बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैदुराम शर्मा के अधीन था जिसे दिसंबर १९२२ में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उस पर राज्य विरोधी कार्य

करने का आरोप लगाते हुए १० मई, १९२३ को छठे पार वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया साथ ही राज्य ■ भी निष्कासित कर दिया गया । सत्याग्रह आंदोलन उत्तरोत्तर जोर पर डगा गया, मई, १९२३ में पुलिस ने मनेक स्थानों पर गांधीपुर्खे डग से सत्याग्रह करने वाले किसानों पर गोली चलाई जिससे मानक भील बाबक कर्मचारी की घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गई । तदुपरांत इस क्रूर दमन के सामने आंदोलन धीमा पड़ गया ।

१९२१ में बिछावा (झेलावाटी) के मास्टर बालीचरण शर्मा की सम्पत्ति में सेवा समितियों का गठन किया गया । जयपुर राज्य में इसे एक साठकवादी गतिविधि समझा और मास्टर बालीचरण शर्मा और प्यारमान गुप्त को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही रुहे खेतड़ी तक गने पैर चलने के लिए बाध्य किया । इस घटना की वहीर प्रतिक्रिया हुई और न केवल झेलावाटी में बल्कि बलकला और बवाई में कड़ा विरोध प्रकट किया गया, परिणामस्वरूप छोटे समय बाद दोनों ही नैसर्गिकी को रिहा कर दिया गया । बाल्लव के यह एक राजनीतिक आंदोलन का आरम्भ था जो बाद में धामे चलकर १९३२ में हीकर आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ ।

### भरतपुर में विद्यार्थी आंदोलन

इन वर्षों की एक महत्वपूर्ण घटना राजस्थान में पहलीबार एक विद्यार्थी आंदोलन होना था । १९२०-२१ में भरतपुर के विद्यार्थियों ने आंदोलन आरम्भ किया । आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सम्राट् जार्ज पचम के विरोध का प्रमाण किया और इन विरोध की होली जलाई । विद्यार्थी आंदोलन ■ संगठन गोरीलात मादव और जुगलकिशोर चतुर्वेदी द्वारा किया गया । विद्यार्थियों के मुख्य नारे महात्मा गांधी की वय और भारत माता की वय थे । तत्कालीन समय में इन नारों ने भरतपुर में हलचल मचारी । आंदोलनकारियों ने विभिन्न समारोह एवं जुलूस का भी आयोजन किया । साथ ही साथ गांधी दोषी और खादी पहनने पर भी बल दिया । इसी समय राष्ट्रीय बीरता नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ जो राष्ट्रीय भावना से प्रोत्प्रेत थी । जुगलकिशोर चतुर्वेदी के द्वारा पुस्तक को वितरित करने का प्रयत्न किया गया परंतु नीध ही राज्य सरकार के द्वारा यह पुस्तक खाल कर ली गई ।

इस प्रकार कांग्रेस के जन्म से लेकर १९१६ तक किस प्रकार उत्तर भारत में आंदोलनारी एवं साठकवादी आंदोलनों का बीजबसा रहा उसमें

राजस्थान ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। १९२०-२१ में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तब भी राजस्थान उससे प्रभावित हुए बिना न रह पाया। यह राजस्थान के प्राचीन इतिहास के अनुरूप था। राजस्थान योग्ना, शौर्य और साहस की भूमि रहा है। उपर्युक्त वर्षों में राजस्थान के आधिकारी नेनामो ने अपना योगदान देकर इसी परंपरा का निर्वह किया।

---

## भील-आन्दोलन

राजस्थान में राजनीति का कानून के प्रतिष्ठान में भील आन्दोलन का घटना एक विज्ञान गृहस्थ है। राजस्थान के मागसाल झुंझार और तिरौली प्रदेशों में भील बहुसंख्यक रहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में भी भीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन इतिहास में हमने पहले कि हम राजस्थान में भील आन्दोलन की विशेषता करें, इसलिए उपर्युक्त यह होगा कि पहले हम भीलों की प्रकृति और उनका चरित्र का वर्णन करें।

**भील, उनकी प्रकृति और चरित्र**

भील भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक जाती जाती है। १९४१ की जनगणना के अनुसार भारत में उनका आसपास १० लाख हो कर रहा है। भीलों की उत्पत्ति की वजह विभिन्न प्रकार की निम्नलिखित प्रचलित है। ब्राह्मणों की कान्तिरी के अनुसार भील का इका उपयोग प्राचीन महान और माधव ज-साहित्य के भी मिलता है। यथाशक्ति ज्ञान के भील शब्द का उपयोग संभवतः सर्वप्रथम माना जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार भील शब्द की उत्पत्ति भिल्ला शब्द से हुई है। शब्द टाट इन्ड या पुत्र मयका जगदी शिबु के नाम से पुकारता है। एक मय निम्नलिखित के अनुसार भील महादेव के बीच से उत्पन्न हुए हैं। कुछ भीलो राजस्थान में भीला का विशेष योगदान रहा है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के प्रतिष्ठान भील के और उन्होंने गुप्त साक्ष्य से रहा करने के महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भील अन्धविश्वासी होते हैं और भूतप्रेतों से बचने के लिए अपने सीधे हाथ पर विभिन्न प्रकार के चिह्न बनाते हैं। भील भोगाओं में विश्वास करते हैं और उन्हें के माध्यम से भूतप्रेत को मगाते हैं। वास्तव में यह एक बहुत ही अयोग्य जाति है और आधुनिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा वर्ग रहा है, परन्तु इस सब के बावजूद भील एक साहसी और बफादार जाति है। इनके मुख्य हथियार तीर और कमान हैं। वास्तव में भील एक सच्चा मित्र भी है, यदि भील को प्रसन्न कर दिया जाय तो वह सर्वत्र बफादार रहेगा। परन्तु यदि उसे अप्रसन्न कर दिया जाय तो वह बहुत खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। अनेक शताब्दियों से भीलों का शोषण किया जाता रहा है यही कारण है कि उनमें राजनीतिक चेतना का विकास शून्य जातिश्रेणी के साथ साथ नहीं हो पाया है, फिर भी वे अपने रीति रिवाज और परम्पराओं के प्रति बहुत अधिक सज्जन हैं और उसका उल्लंघन करना उन्हें अचिन्त नहीं लगता। यही कारण है कि जब किसी कानून के द्वारा उनके रीति-रिवाज और परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है तो उन्होंने सर्वत्र कानून की अवहेलना करने का प्रयत्न किया है। उदाहरणस्वरूप १६ वीं शताब्दी में उन्होंने मराठों के विरुद्ध सन्धियाँ किया तो १९ वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। यह स्पष्ट बात है कि कर्नल टॉप भी सफल कूटनीति के परिणामस्वरूप १२ मई १८२५ को भीलों और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता हो गया जिसके अनुसार भीलों की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वे और आगे अथवा ब्रिटिश सरकार के मनुष्यों को कभी शरण नहीं देंगे तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों का पालन करेंगे।

### नए सुधार और भील प्रतिरोध

भील एक स्वतन्त्र जाति रही है। स्वभावतः वे अपने ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहते। यही कारण है कि १ नवम्बर, १८५८ के पश्चात् जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और महाराष्ट्रीय विक्टोरिया के शासन काल में अनेक सुधार आयोजित किए गए तो भीलों ने इसे अपने अधिकारों का हनन समझा और तदनुसार राज्य अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की।

१८८१ में सर्वप्रथम कुछ सुधार लागू किए गए जिनके अन्तर्गत भीलों की जनगणना किया जाना, मद्यपान पर नियंत्रण लगाना भील क्षेत्र में पुलिस



या धुंगी खोली भी स्थापना करता और जन्यविधवाओं पर नियन्त्रण लगाना सम्पत्ति का। जैसाकि स्पष्ट हो है इन सुधारों को लागू करने का प्रथम पुर्ण-पुर्णों से खली या रही भील परम्पराओं का उल्लंघन करना था। स्वभावतः इन सुधारों को कार्यान्वित करने पर भील प्रयत्न हुए। ये दा सुधारों के लाभों को नहीं समझ सके। या भील समाज में घनेर प्रकार की संप्रदाह फैलाई गयी। कुछ लोगों ने मतानुसार जनगणना का कार्य प्रकटान मुद्र के लिए पत्र एवं विन करना था, कुछ भीलो का विरासत या नि जनगणना के माध्यम से स्वयं भीलो को सेवा में भर्ती करदे प्रकटान मोर्चे पर भेजा जाएगा। कुछ अन्य लोगों का विरासत था कि इस जनगणना के द्वारा स्फुल्लताय स्थिती मोटे युवकी की घोर मतली दुर्गती स्थिती पाने दुर्गती युवकी को दी जाएगी। इन समस्त पदनामों का परिणाम यह हुआ कि जैसा ही १८८१ में सुधार लागू किए गए भीनों ने जनगणना विद्रोह कर दिया। मेवाड़ के भील विद्रोह का पहला समाचार राजस्थान में गजानर जनरल के एजेन्ट को २५ मार्च, १८८१ को मिला। समाचार में कहा गया था कि बडावास के मानेदार ने बडुनावास की भूमि सखी बाद विवाद के निष्पत्ति में मुनाने के लिए एक सिपाही भेजा था। परन्तु भील उसी जिन हो उठे उन्होंने सवार को मार डाला और लगभग तीन हजार भीलो ने बडेवास के माने की घेर लिया और मानेदार सहित ११ व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। भीनों ने उदयपुर खेरवाड़ मार्ग को भी बंद दिया और माने व सभी महारणों की दुर्गती की मांग सपा थी। महाराणा मेवाड़ ने स्थिति पर बाजू पाने के लिए तत्काल एक संनिन टुकड़ी भेजी, परन्तु इसी बीच मतलीगढ़ के भीनों ने भी विद्रोह कर दिया और स्थिति इतनी अधिक गंभीर हो गई कि ब्रिटिश सरकार ने एजेन्ट बर्बनर जनरल को आदेश दिया कि वह तत्काल उदयपुर पहुँचे और कार्यवाही का स्वयं निर्वहन करे। मानेदार और अन्य व्यक्तियों की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उस पर टिप्पणी करते हुए बर्नल जेनरल ने कहा कि बडावास और रसायनाय के सभी भीनों ने विद्रोह कर दिया है उसने मतानुसार भीलो की प्रमुख मांग यह है कि यदि किसी स्त्री पर शाकिन होने न सके हो तो उसे बिना किसी व्यव पदनाम के तुरत मार देने की आज्ञा दी जाए, भील क्षेत्र में पुनिरा खोली की स्थापना न की जाए तथा यदि भीलो में पापन में कोई भगडा होता है तो महाराणा मेवाड़ उसमें हस्तक्षेप न करें। भीलो की यह भी मांग थी कि भविष्य में जनगणना जैसा कोई कार्य नहीं किया जाए क्योंकि उनका विरासत

था कि यह जनगणना का कार्य उन पर कर सगाने की दृष्टि से किया जा रहा है। कर्नल कोयर के अनुसार मेवाड़ के अधिकारियों ने बहुत ही अनुत्तरदायी ढंग से स्थिति को समझने की कोशिश की। घटना की जांच स्वयं कर्नल कोयर ने ही की। भीनों का कहना था कि बिना किसी कारण से मेवाड़ राज्य की सेनाओं ने उन पर गोरिया चनायी और निरपराधी व्यक्तियों की हत्या की गई। कर्नल कोयर ने भीनों को परामर्श दिया कि उन्हें मेवाड़ के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। तदनुसार लगभग १०० भीन राजबन्दास में एकत्रित हुए जहाँ राज्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कर्नल कोयर के अनुसार बान्नील सनोय जनक ढंग से चले रही थी कि इसी समय राज्य-अधिकारी रामनदास ने भीनों में एक प्रश्न पूछा तुम लोग समझौता क्यों नहीं करते और इसके साथ साथ ही राज्य में कुछ सिपाही यन्त्रों को भरने लगे। यह देखते ही भीन जो कि निरक्षर व भाग छड़े हुए और इसी समय एक राज्य कर्मचारी न गोली चला दी। परिणामस्वरूप समस्त भीन जाति महाराणा के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गई। अतः १९ अप्रैल, १८८१ को महाराणा मेवाड़ के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप भीनों और राज्य-अधिकारियों के मध्य समझौता हुआ जिसमें भीनों की सभी मांग (सर्वान् जनगणना कार्य स्थगित कर दिया जाय बान्दार और अन्य सिपाहियों की हत्या करने वाले भीनों को क्षमादान दिया जाय इत्यादि) स्वीकार कर ली गई।

परन्तु इन सबसे बावजूद शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। १३ जून १८८१ को झगरपुर में भीनों द्वारा नी मकरानियों की निमम हत्या कर दी गई। अब राज्य अधिकारी दयानाथ गिरिजावर के नेतृत्व में स्थिति पर नियंत्रण करने पड़ने लगे उन पर भी तत्कालीन और तीरों द्वारा आक्रमण किया गया। अतः भीनों को दवाने के लिए राज्य ने ३०० सैनिक भेज भेजे गए। जिन्होंने भीनों की कोपटो की श्रावण बना दी और चार भील मार डाले गए तथा अनेक भाग्य हुए। १६ मार्च, १८८२ को मेवाड़ सैनिकों ने व्यापक पैमाने पर बायबाही की। अतः भीनों को समझण करना पड़ा और उन्होंने २८ फरवरी, १८८३ को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार भीलों ने वचन दिया कि वे सदेह व आचार पर दायित्व मानकर उसकी हत्या नहीं करेंगे। भीनों ने बाबी जी के नाम पर शपथ ली कि वे समझौते का पालन करेंगे। उपर्युक्त समझौते के परिणामस्वरूप भीनों ने अपने सभी भस्त्र यस्त्र राज्य अधिकारियों के हथाने कर दिए और अपने पास केवल तीर

[illegible]

**मौतिलाल तेंगड्या घोर भीत-माहोरा**

[illegible]

इसी प्रकार सिरोही में भी भील आंदोलन धीरे-धीरे तेज होता आ रहा था। बानावरण में व्याप्त तनाव को कम करने के लिए भील समुदाय के निमंत्रण पर विजयसिंह को आमंत्रित किया। भील इस बात पर सहमत हो गए थे कि वे राज्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और अपनी कठिनाइयाँ उनके सम्मुख रखेंगे, परन्तु राज्य की ओर से दमन-चक्र का सहारा लिया गया। इसी बीच महात्मा गांधी की ओर से मसीनार कोठारी सिरोही पहुँचे जिन्होंने सफलतापूर्वक मोतीलाल तेजावत और राजस्थान में एजेंट गवर्नर जनरल हार्नेण्ड को आपसी बातचीत के लिए राजी कर लिया, परन्तु राजपूताना एजेंसी में पुनः अपने बचन का निर्वाह नहीं किया और ८ मई, १९२२ को भूना और बलीहिया नामक दो भील गाँवों को आग लगा दी, साथ ही साथ रोहटा तहसील के शांतिपूर्ण भीलों पर पुलिस ने गोली चलाई। विजयसिंह पब्लिक पर भी मुनदमा चलाने का फैसला किया गया। पुलिस के अत्याचारों की यह कहानी अग्रेज म राजस्थान सेवा सच के पाम ६ मई, १९२२ को पहुँची। दूसरे दिन अधिकार समाचार पत्रों में भीलों पर डाले जा रहे अत्याचारों का वर्णन प्रकाशित था। राजस्थान सेवा सच की ओर से सत्य मक्त और रामनारायण चौधरी को स्थिति का अध्ययन करने को भेजा गया। ये लोग १५ मई, १९२२ को बलीलिया पहुँचे जहाँ इनको अनेक पत्रों और नागरिकों ने पुलिस द्वारा किए गए बर्बर अत्याचारों की दर्दनाक कहानी सुनाई। इसके अनतिरिक्त सेवा सच के प्रतिनिधियों ने लगभग ११५ ग्राम साक्षियों के बयान भी लिए, इनके अनतिरिक्त १३० भीलों ने अपने बयान पत्रों से दर्ज कराए। यदि सेवा सच की रिपोर्टों की सही माना जाय तो ३२५ परिवार पुलिस के द्वारा तहस नहस कर दिए गए, १८०० नर नागरियों की हत्या की गई, ६४० मकानों को आग लगा दी या नष्ट कर दिया गया, ७०८५ मन अनाज को नष्ट कर दिया, ६०० बैलगाड़ियाँ जला दी गई, १०८ पशुओं को मार डाला गया था ले जाया गया और लगभग दस हजार रुपये की सम्पत्ति नष्ट की गई। भीलों पर डाले गए इन अत्याचारों ने उन्हें अपने नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया और इस प्रकार वे अभिशाप भी उनके लिए बदलाने साबित हुए।

परन्तु इस निर्यम दमन चक्र के बावजूद भील आंदोलन को पूरी तरह नहीं दबाया जा सका। मोतीलाल तेजावत का भीलों पर अभी भी उतना ही प्रभाव था। वास्तव में वही उनके सुम-दुःख का मापी था। तेजावत ने घर

भीनों ईसे बरत धारण करने शुरू कर दिए और १९२३ के भारतम्ब में उसने एकी मान्दोनन शुरू किया, जिसने कि भीनों को पुनर्गठित किया जा सके। ईइर प्रकटित भीन मान्दोनन में अब बरत तेन मया। इस प्रकार भीनीमान तेजा-  
बन के बरते हुए प्रभाव को देखकर ब्रिटिश सरकार और राज्य सरकारें बिलित  
हो उठी। भीनीमान तेजाबन भूमिगत बहुरंग मान्दोनन का नेतृत्व कर रहा  
था, क्योंकि ब्रिटिश और राज्य की सरकारें उसे पकड़ने की हर संभव कोशिश  
कर रही थी। भीनीमान तेजाबन की गतिविधियों को दबाने देने के लिए ४  
जून, १९२१ को उसके विरुद्ध एक गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और  
वही नाटकीय दंग में ईइर दुनिया के एक विपानी न तेजाबन को उस समय  
विस्तार कर दिया जब वह ईइर स्थित किया पब्लिश न एक भीन समा में  
जाग तेने जा रहा था। भीनीमान तेजाबन को जुलाई १९२१ में मेवाड राज्य  
की और दिया गया। मेवाड सरकार ने बिना मुकदमा कपाए और बिना  
समिपण लगाए माअन ६ वर्ष तक तेजाबन को केन्द्रीय कारावास उदयपुर में  
बन्द रखा। तेजाबन की रिहाई के अनेक प्रयत्न किए गए परन्तु सफलता नहीं  
मिली।

३ नवम्बर, १९२२ को मणीमान कोठारी के द्वारा तेजाबन की रिहाई  
के लिए प्रयत्न शुरू किए गए। मणीमान कोठारी न उदयपुर महाशाला के  
प्रधानमंत्री पर्य नारायण और ब्रिटिश केबीनेट कबन बेवम से भीनीमान  
तेजाबन की रिहाई का अनुचीन किया, परन्तु मेवाड सरकार बिना भई तेजाबन  
की रिहाई के लिए तैयार नहीं थी। मेवाड सरकार की मांग थी कि तेजाबन  
की सभी रिहा किया जा सकेगा अत्रकि वह यह बचन द कि वह राज्य विरोधी  
गतिविधियों में भाग नहीं लेगा और बिना महाशाला की अनुमति के मेवाड  
क्षेत्र में बाहर नहीं जाएगा। मणीमान कोठारी ने भीनीमान तेजाबन से भी  
मेट की परन्तु उसने सख्त रिहा होने में द्धार कर दिया। अन्तत तेजाबन  
इस भई पर रिहा होने के लिए तैयार हो गया कि ब्रिटिश सरकार यह घोषणा  
करे कि जेने कोई आराय नहीं किया है और दूसरे तेजाबन के विरुद्ध  
पदाय करने वालों के निवारक उने कार्यवाही करने का अधिकार हो। राज्य  
सरकार ने इन दोनों ही मांगों को स्वीकार कर लिया अत १६ अप्रैल १९२५  
को भीनीमान तेजाबन ने बचन दिया कि वह बिना मेवाड राज्य की अनुमति  
के मेवाड राज्य से बाहर नहीं जाएगा और राज्य विरोधी कोई कार्य नहीं  
करेगा। इसकी पूरा में राज्य सरकार की ओर से भी यह मान्यता दिया

गया कि तेजावत को अच्छे परिणाम प्रमाण पत्र दिया जायगा और उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने उसका अपमान किया है—के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा। मोतीलाल तेजावत ने यह भी मांग की कि यदि सरकार उसे किसी कार्य के उत्तुंग समझती है तो वह उसे स्वीकार कर लेगा। तदनुसार २३ अप्रैल १९३६ को उदयपुर केन्द्रीय बारापहा से मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। उससे घट पृच्छा गया कि अब वह किस प्रकार का कार्य करना पसन्द करेगा। तेजावत ने विचार प्रकट किया कि वह खादी का प्रचार और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहता है परन्तु महाराजा उदयपुर ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया, उनका कहना था कि तेजावत को रनाट और सागी जादियों के सम्बन्ध बनाना चाहिए जो कि पानि और व्यवस्था के लिए सार्वजनिक बन रही हैं।

१९४२ में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान मेराड में तेजावत को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में २ फरवरी १९४७ को तेजावत को पुनः रिहा कर दिया गया जहाँ जनता में उसका मध्य स्वागत किया।

भीलो में राजनीतिक चला जागृत करने और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बनवामी सेवा सच भी स्थापना की गई। १९४० में बनवामी सेवा सच भी दूधपुर जागृत न एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया था। इस सच का मुख्य कार्य भीलों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना था और उनमें फैले हुए अन्धविश्वास को दूर करना था। निम्नलिखित इस दिशा में बनवामी सेवा सच का कार्य अत्यंत मर्यादनीय था।

## राजस्थान में राजनीतिक आन्दोलन और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना ( १९२५-१९३९ )

भारतीय गणनिष्ठ १९१६ की मन्त्रालय नीति द्वारा चलाया गया सश्रुयोग प्रारोचन का न केवल प्रारम्भ । भारत पर ही प्रसार पना था । अतः भारतीय राजनीति की जनता भी प्रभावित हुई थी । अतः १९२४ से १९३९ तक राजस्थान में भी यह प्रारोचन हुए निम्नलिखित द्वारा विभिन्न राज्यों में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की उत्तरदायी सरकार की भावना की गई । निम्नलिखित पत्रिकाओं में इसी प्रारोचन के निहितार्थ को विस्तारित करने का प्रयत्न किया गया है, जिनके परिणामस्वरूप अनेक राजस्थान के विभिन्न राज्यों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ । विषय की महत्ता और पाठकों की सुविधा को देखते हुए हमने प्रत्येक राज्य का पत्राचार अलग विवेचन करना अधिक उपयुक्त समझा है ।

### अजमेर

१९२५ में अजमेर राज्य का राजनीतिक वातावरण बहुत अधिक कुटिल था । किसी भी व्यक्ति का अपने विचार प्रकट करने की न तो स्वतन्त्रता थी और न ही किसी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा सकता था । यहाँ तक कि राज्य से कोई समाचार पत्र तक नहीं निकलता था । परिणामतः

राज्य विरोधी वातावरण धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुँचने लगा। मई, १९२५ में धनवर राज्य की दो तहसीलों बानमूर और गाजी बा बागा में सरकार द्वारा लागू किए गए नए करों को लेकर एक प्रादोन्नत द्दिग गया। जनता का कहना था कि उन पर पहले ही कर भार बहुत है और अब और अधिक कर नहीं दिए जा सकते। परन्तु महाराजा जयसिंह ने किसानों की स्थिति सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया और दमन चक्र का सहारा लिया। १४ मई १९२५ को राज्य की सशस्त्र सेनाओं ने उपर्युक्त दोनों गावों को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के शाल किमानों पर गोली चलाई। यहाँ तक कि स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा गया और बड़े ही निर्लज्जता पूर्ण ढंग से उन्हें अपमानित किया गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन गोलीबारी में कम से कम ३५३ मकान जगकर नष्ट हो गए जिनमें ७१ पशु भी जीवित जल गए और लगभग ५०००० रुपये से लेकर १००००० रुपये तक की सम्पत्ति लूटी गयी। इसके अनिर्दिष्ट लगभग ६५ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए जबकि २५० से अधिक घायल हुए। इस घटना ने समूचे राज्य में भ्रूतक फैला दिया।

परन्तु सरकार की दमन नीति जारी रही। १९२७ २८ में महाराजा झलवर के आदेश के अन्तर्गत बाहर से आने वाले पापे दर्जन से अधिक समाचार पत्रों के राज्य प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया। आदेश में यहाँ तक कहा गया था कि यदि प्रतिबन्धित समाचार-पत्रों का एक कागज भी किसी नागरिक के पास बरामद हुआ तो उस पर पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है और यदि आवश्यकता हुई तो उसे राज्य में निष्वासित भी किया जा सकता है। इस दमनकारी नीति का परिणाम यह हुआ कि महाराजा जनता में बहुत अधिक घनोद्विग्न हो गए और अब वे सनातन धर्म सभा की एक बैठक में भगवत् लेने के लिए पहुँचे तो जनता ने सर्व शय के नारे लगाए स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि महाराजा को पुलिस सरदाय में बाहर ले जाया गया।

मेव प्रादोन्नत

राज्य की शिक्षा-नीति के परिणामस्वरूप मुसलमानों में बहुत अधिक असन्तोष था। मुसलमानों की माय थी कि राज्य में कुरान की शिक्षा देने पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए और उन्हें माध्यम से भी शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन मायों के साथ १९३२ में मुस्लिम प्रादोन्नत परिषद हुआ। महाराजा का कहना था कि वास्तव में मुस्लिम प्रादोन्नत में कोई



सबसे नई थी। परन्तु चांदोनन और-और बढ़ना गया और राज की सीमा के बाहर तक पहुँच गया। स्थिति यह बन गयी कि मुइयाँवा और मोहनवा में वेद मुसलमानों के जलसे घनघन राज्य में प्रवेश करने लगे और उन्होंने सीधी कार्यवाही करने का भी धमकी दी। स्थिति को दृष्टिगत देखकर महाराजा खन्वर ने ब्रिटिश सरकार से मुख्य सैनिक सहायता प्रेषण का अनुरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने मुख्य कार्यवाही की और ६ जनवरी १९१३ को ब्रिटिश सेनाएँ घनघन पहुँच गयी तथा मोहनवा और मुइयाँवा समाप्त हो गई। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा को प्रामाण्य दिया कि वे ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता और महा सार्वभौम पुलिस के रूप में नियुक्त करें। परिस्थितियों से राज्य और प्रजासत्ताक महाराजा ने सभी महामति दे दी।

समस्त वास्तविकता यह थी कि ब्रिटिश सरकार महाराजा से प्रसन्न नहीं थी। जैसा कि हम देखा चुके हैं, महाराजा का दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी था, यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने महाराजा से यह अनुरोध किया कि वे अपनी समस्त सैनिक प्रमाण सभी एक ही वाद की सीमाओं की वर्य के लिए राज्य से बाहर चले जाएँ क्योंकि उनके विरुद्ध एक प्रायोगिक स्थिति किया जायगा, जो उनके कार्यक्षेत्रों की जाँच करेगा। प्रसन्न, महाराजा की राज्य छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और वे इंग्लैंड चले गए। बाद में सन १९१७ में उन्हें वापिस राज्य में लौटने की अनुमति मिली।

उत्तरवासी सरकार की भावना .

सन १९१७ में जैमि ही महाराजा खन्वर राज्य में वापिस लौटे तो लोकप्रिय सरकार की सहायता की भावना को लेकर चांदोनन बिद्व गया। १९१८ में राज्य में प्रजासत्ताक की स्थापना हुई। राज्य सरकार ने दमनकारी नीति का प्राथम्य दिया और उनके व्यक्तियों की निष्ठापूर्ण कर दिया जिनमें सर्वप्रथम स्वर्ण विपरीत, प्रजासत्ताक, कावेम कमेटी, प्रजासत्ताक के सचिव हरि नारायण शर्मा और कावेम कमेटी के सचिव राधाचरण गुप्त भी शामिल थे। इन सभी को दो वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। इनके परिवारिक दो अन्य कार्य-कर्ता इन्दरसिंह साहू और नारायण मोदी को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास का दंड दिया। राज्य की दमनकारी नीति का परिणाम यह हुआ कि समूचे राज्य में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति का घण्टीय करने के लिए हरिभाऊ उपाध्याय ने राज्य की भावना को, नागरिकों ने कावेम

के द्वारा हस्तक्षेप करने की भी मांग की, परन्तु इसी बीच मिनम्बर, १९३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और परिणामतः राज्य का वातावरण एकदम ठण्डा पड़ गया।

सीकर आंदोलन

अलवर के समान ही सिनवर, १९२४ में सीकर के किसानों पर भी कुछ नए कर लगाए गए। परिणामतः उनमें धनसंग्रह की मांग बहुत उठी और उनमें यह मांग की कि सरकार यह नए कर वापिस ले ले। साथ ही माघ अषाढी मास पर जोर देने के लिए किसानों ने एक आंदोलन भी प्रारम्भ किया। रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया और गेलावादी में आयोजित आम सभाओं में भाषण दिए। सभजन यही गारण था कि जबपुर राज्य सरकार द्वारा रामनारायण चौधरी को यह आदेश दिया गया कि वह १२ घंटे के अन्दर मन्दिर जबपुर राज्य की सीमा छोड़ दे। परन्तु इन सबके बावजूद आंदोलन तेजी से फैलने लगा और इसकी गूँज न केवल केंद्रीय विधान सभा में अखिल भारतीय सभ में भी सुनाई दी। अतः मई, १९२९ में ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के बीच एक सम-झौता हुआ जिसके अनुसार किसानों ने फसल के अनुपात में जागत (कर) देना स्वीकार किया। परन्तु यह समझौता अल्प समय तक जीवित नहीं रह सका क्योंकि अधिकारियों ने समझौते की शर्तों का ईमानदारी से पालन नहीं किया और उन्होंने भू-राजस्व की दर १२ रुपये ८ आने प्रति सैकड़ा एकड़ से बढ़ा कर २५ रुपये कर दी। परिणामतः २७ फरवरी, १९३७ को एक मार्क्सवादी सभा का आयोजन किया गया जिसमें किसानों ने अपना यह निश्चय व्यक्त किया कि वे सरकार की दमनकारी नीति के बावजूद उस समय तक बढ़ा हुआ भू-राजस्व नहीं देंगे जब तक कि उनकी मांगें स्वीकार नहीं कर ली जाती।

१९३२ में अखिल भारत जाट सभा का अधिवेशन भुवनेश्वर में सम्पन्न हुआ जिसमें अधिकारियों से यह मांग की गई थी कि वे किसानों की मांगें तुरन्त स्वीकार कर लें, परन्तु इसका कोई सतर्क परिणाम नहीं निकला। इसी प्रकार १९३५ में सीकर में विमान आंदोलन की सफलता के लिए एक जाट महासभा का आयोजन किया गया जिसमें नवमग बस्ती हज़ार किसानों ने भाग लिया। परन्तु सरकार की दमनकारी नीति जारी रही और सेकड़ों जाट किसान

त्रेन में बर कर दिष्ट गए । स्वामी नरमिहदास, माण्टर रनविन् और कृष्ण मान जीजी जैसे नेताओं को राज्य से नुरन अने जान के घादेश दिष्ट गए । स्वामी नरमिहदास और कृष्णमान जीजी ने घादेश मानने से इकार कर दिया, परिणामतः उन्हें दो-दो वर्ष के बढीय बागवात का दण्ड दिया गया वन्तु घाशेनन फिर भी जारी रहा । मई, १९१५ मे मूगी और नूदा में गातिपूरा किसानों पर पुलिस ने गोली चलवाई जिससे ऐसा विश्वास किया जाता है कि कम से कम १०-१२ व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, लगभग १०० व्यक्ति घायल हुए और घनेय स्थलों पर भी प्रहार दिष्ट गए ।

राज राजा सीकर का निष्कासन :

जिस समय यह किसानों का घाशेनन चल रहा था उसी समय स्थिति में एक गया मोर दिया । कारण यह था कि राज राजा सीकर और महाराजा जयपुर के सापसी संबंध तनावपूर्ण थे । इन तनाव का मुख्य कारण यह था कि महाराजा जयपुर राज राजा के पुत्र राजकुमार हरदयास सिंह को उसके पिता के मर्यादा से हटाना चाहते थे, सीकर के प्रशासनिक अधिकारी कैप्टन वेब के अनि राज राजा का समर्थन और जयपुर अधिकारियों द्वारा राज राजा सीकर की निरक्षारी का प्रयत्न तथा जयपुर राज्य सरकार पुलिस का सीकर भेजा जाता था । वन्तः इन सब घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि राज राजा सीकर को विक्षिप्त घोषित करते हुए उन्हें राज्य में निष्कासन कर दिया गया । इन गदर्ष में यह सच महत्वपूर्ण है कि जाट घाशेननकारियों ने राज राजा का समर्थन किया और कैप्टन वेब को हटाने की माग की । अपनी माग पर जोर देने के लिए मधुमे नहर में हड़ताल भी आयोजित की गई । नारायण को टण्डा करने के लिए कर्नल गिलन की अध्यक्षता में एक जाब प्रायोग की स्थापना की गई जो १० जून, १९१८ की सीकर पहुंचा और जिसने दूमेरे ही दिन सीकर के नागरिकों से भेंट की वस्तु नागरिकों ने जाब प्रायोग को कोई महयोग नहीं दिया क्योंकि उनका कहना था कि इन प्रकार का प्रायोग जयपुर महाराजा द्वारा नहीं प्रयुक्त भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे कि प्रायोग के सदस्य विपक्ष रह कर कार्य कर सकें ।

उत्तरदायी सरकार की मांग

१९ जून, १९१८ को ठाकुर बालविह की अध्यक्षता में सीकर दिवस

मनाया गया सात ही उम्र निम्न भूग हस्तान भी रही गई। साधकाल एक मावजनिक सभा हुई जिसमें राव राजा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की मांग की गई परन्तु स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। ४ जुलाई, १९३८ को पुलिस कामन्वेन जगत पुरोहित और धर्म नागरिक उस समय गोली के निशाने बन गए जबकि जयपुर राज्य की संरक्षण सभाओं का प्रतिरोध मोकर नागरिकों के द्वारा किया गया। ५ जुलाई १९३८ को जयपुर सभाओं के साथ घात हुआ राजपूत और सीकर प्रांतोपकारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर जमकर मारपीत हुआ जिसमें पांच व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए और अनेक घायल हुए। सेठ जमनालाल बजाज रामकृष्ण मेगान और सेठ पोद्दार द्वारा शांति स्थापना के प्रयत्न किए गए परन्तु असफल रहे। दूसरी ओर जयपुर अधिकारियों ने और कड़ा दम धपनाया महा तक कि सीकर राज्य के गांव के प्राइवेट सेक्टरों तक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामस्वरूप स्थिति बहुत अधिक नाजुक हो गई। पुलिस गोलीकांड और नागरिकों की गिरफ्तारी पर चर्चा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में कहा था कि पूरे मामले की व्यापक जांच होना आवश्यक है। पंडित नेहरू के मतानुसार यह अधिकतर देशी राज्यों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और उन्हें बदलती हुई स्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित करना चाहिए। स्थिति उस समय और भी अधिक खराब हो गई जब जयपुर के अधिकारियों ने सीकर के नागरिकों को ४८ घंटे का नोटिस देते हुए यह धमकी दी कि या तो वे शहर के दरवाजे खोल दें अन्यथा ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। परन्तु स्थिति उस समय सुवर्णीय नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए २३ जुलाई १९३८ को महाराजा जयपुर ने गृहमंत्री चंचरील के ठाकुर हरिमिह और रिमांड के ठाकुर विजयसिंह के साथ सीकर की यात्रा की। राव राजा सीकर ने बिना शर्त महाराजा जयपुर से क्षमा मांगी और अपनी समस्त भूमियां जयपुर महाराजा द्वारा नियुक्त प्रशासक को सौंप देने का और प्रशासन में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया। परिणाम यह हुआ कि राव राजा सीकर के विरुद्ध जो जांच आयोजित की गयी थी उसको समाप्त कर दिया गया इस प्रकार सीकर की स्थिति में नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ।

जयपुर

जयपुर में भी महाराजा के निरंकुश शासन के विरुद्ध धीरे-धीरे प्रभावित बहना जा रहा था जिसकी पहली भलक जयपुर शहर में १ सितंबर

१९२७ को देशन को मिला । इसी दिन राज्य के हजारों नागरिकों ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और नए कठोर के विरुद्ध आन्दोलन किया । पुलिस ने गोली चलाई जिससे एक मारा गया और पांच पुलिसमैनो सहित ३७ व्यक्ति घायल हो गए स्थिति यहां तक बिगड़ी कि ब्रिटिश रेजीडेंट को सना ठक बुलाना पड़ी । जल्दा इतनी अधिक उत्तेजित हो गई कि उसने नगर कोरवाली पर भी आक्रमण कर दिया तथा यहां तैनात सगस्त पुलिस टुकड़ी को घेर लिया परिणामतः पुलिस ने गोली चलाई जिससे जय बाईर मारा गया और दो घायल हो गए । २ फेब्रुअरी, १९२७ को सायनाल एं सांख्यिक समा समावेदन की गई जहां पुलिस गोलीबाज की निशाने करते हुए निर्दयता से की मार की गई और साथ ही साथ एक उत्तरदायी सरकार की भी मांग की गई तथा १३ प्रस्ताव पारित किए गए । ५ दिना तक नगर में हड़ताल रही और ६ फेब्रुअरी १९२७ को इसी समय समाप्त हुई जब ब्रिटिश रेजीडेंट ने यह आश्वासन दिया कि वह स्वयं स्थिति को शांत करेगा ।

### मौलीलाल दिवस समारोह

फरवरी १९२९ को जब मौलीलाल दिवस मनाया जा रहा था तो एक बार पुन गड़बड़ी शुरू हुई । गड़बड़ी का कारण यह था कि राज्य सरकार ने मौलीलाल दिवस समारोह को मनान की अनुमति नहीं दी और दमन चक्र का सहारा लिया । गुलाबचंद मोरारी कुशवान और बिजौरसिंह सावी कार्यकर्ताओं सहित उनके स्थानियों की विरूपण कर लिया गया और उन्हें विभिन्न अवधि के लिए जेल भेज दिया गया । इस प्रकार जब राज्य सरकार ने सभी राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना जारी रखा तो मई १९३७ में राष्ट्रीयों ने जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना की ।

### जयपुर प्रजामण्डल और उसकी गतिविधियां

प्रजामण्डल का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना नागरिकों को उनके प्राथमिक अधिकार दिखाना और राज्य की बहुमुखी प्रगति करना था । दूसरे शब्दों में प्रजामण्डल ने राज्य-सरकार को स्पष्ट रूप में बताना दिया था कि जनता राज्य की प्रतिनिधितावाली नीति में आवश्यक अनुपस्थित है । इसीलिए प्रजामण्डल ने राज्य का चलाकला देत हुए कहा कि यदि सरकार जानि और व्ययक्त बनाए रखना चाहती है तो इसे समय के अनुसार चलना चाहिए । परंतु जब राज्य अधिकारियों ने प्रजामण्डल की इस योजना को

घोर कोई ध्यान नहीं दिया तो प्रजामण्डल के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसकी मुख्य मांगें यह थी कि एक विधान सभा की तत्काल स्थापना की जाय, दिना पूर्व सूचना के नागरिकों को एकत्रित होने का अधिकार हो, प्रेस को स्वतंत्रता दी जाय स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए एक एम्पलायमेंट एक्सचेंज की स्थापना की जाय, सागवाय धर्बध घोषित किया जाय और अशाल से प्रभावित क्षेत्रों में भू-राजस्व को समुन्नी स्थगित कर दी जाय परन्तु राज्य ने दमनकारी नीति का सहारा लिया और उसके प्रत्युत्तर में जनता ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया। आंदोलन को कुचलने के लिए राज्य ने जमनालाल बजाज के जयपुर में प्रवेश करने पर प्रतिवन्ध लगा दिया परन्तु जमनालाल बजाज ने घोषणा की कि वे फरवरी, १९३६ को राज्य के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए सत्याग्रह करेंगे। स्थिति इतनी अधिक विस्फोटक बनी कि महात्मा गांधी ने अपने बंधान में कहा कि यदि जयपुर के अधिकारियों ने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला तो कांग्रेस के समुच्च कोई कड़ा कदम उठाने के अनिवार्य अर्थ कोई विकल्प नहीं रह जायगा। वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का कारण जयपुर के प्रधानमंत्री सर बीचम का तानाशाही पूर्ण रवैया था। प्रजामण्डल की गतिविधियों पर अपने विचार प्रकट करते हुए सर बीचम ने कहा था कि राज्य किसी भी मण्डल या संस्था का यह अधिकार स्वीकार नहीं कर सकता कि वह जनता की कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। भारतीय राज्यों में अभी ऐसा करने का समय नहीं आया है। परिणामतः सेंट जमनालाल बजाज के नेतृत्व में १ फरवरी, १९३६ को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ किया गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जमनालाल बजाज और मण्डल कार्यकारिणी के सदस्यों सहित लगभग ५०० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन १६ मार्च, १९३६ को सभी समाप्त हुआ जबकि राज्य ने प्रजामण्डल को वार्षिक समस्त सच के रूप में मान्यता देना स्वीकार कर लिया और सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया।

### भरतपुर

राज्य की भू-राजस्व नीति को लेकर १९२४ से ही भरतपुर ने वित्तानों में असंतोष भड़क रहा था, परन्तु राज्य की ओर से इस असंतोष को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया वरन् दमनकारी नीति के द्वारा

उन चुनने देने का प्रयत्न किया गया। सरकार की नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए १ अप्रैल से १२ अप्रैल, १९२७ के मध्य अनेक सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर वी० ए० बन्धु, पंडित मदनमोहन मालवीय और चादकराव गारदा जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। राज्य की नीति के परिणामस्वरूप न केवल शान्ति और व्यवस्था को ही नष्ट हो रहा था अपितु राज्य के ऊपर काय भी बहुत अधिक हो गया था अतः ब्रिटिश सरकार ने भरतपुर महाराजा को परामर्श दिया कि वे अपनी समस्त शक्ति का इस्तेमाल करके राजा से राजा के लिए एक भाव प्रयोग का सामना करें जो राज्य की वर्तमान स्थिति और महाराजा के उत्तरदायित्व के संबंध में जांच पड़ताल करेगा। अतः महाराजा ने मजबूर होकर ब्रिटिश दीवान मेजरजी को अपनी सम्पूर्ण शक्ति ६ फरवरी, १९२८ को सौंप दी।

### मेजरजी का आगमन और आंदोलन का प्रारंभ होना

सत्ता सम्हालते ही मेजरजी ने चार राज्य अधिकारियों को सचिवालय के कारोब में पदभूक्त कर दिया। इन चारों ने राज्य के अन्तर्गत की बहुत अधिक तनावपूर्ण बना दिया। १९२६ में भरतपुर पीपुल्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। साथ ही साथ राजस्थान स्टेट पीपुल्स काँग्रेस ने भी अपना अपना अधिवेशन १९२६ में भरतपुर में ही करने का विचार किया। भरतपुर का ब्रिटिश दीवान इन राजनीतिक गतिविधियों को बर्दाश्त करने में तैयार नहीं था, इसीलिए १३ जनवरी १९२८ को भरतपुर पीपुल्स एसोसिएशन के सक्रिय देशराज को उनसे साथ जुड़े हुए विरक्त कर दिया गया और भरतपुर तक लगभग ४१ मील बिना मोड़ों के हुए पैदल चलने के लिए बाध्य किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष का गैरमान सम्मान जो कि सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में एम० ए० का विद्यार्थी था—क गिरफ्तारी के बाद जारी कर दिए गए। गयाप्रसाद चौधरी और लाला गणेशदास ने मकानों की तलाशी ली गई और उनके लोगों की आपत्तिजनक आपत्तियाँ इन के कारोब में गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार की घटनाओं ने राज्य में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी और जनता ने ब्रिटिश दीवान को तुरंत हटाने की मांग की परन्तु राज्य में अतक फैलाने की दृष्टि से ब्रिटिश दीवान ने सभी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूम और राजनीतिक आपत्तियों पर पाबंदी लगा दी।

### जाट महासभा-आंदोलन

इन परिस्थितियों में अखिल भारत जाट महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करत हुए बाईनराय से भरतपुर में हस्तक्षेप करने की अपील की और साथ ही चेतावनी दी कि यदि भरतपुर के नागरिकों की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ किया जायगा। ३१ मार्च, १९२८ को दिन के बारह बजे जाट महासभा का एक प्रतिनिधि मण्डल सिमला में भारत सरकार के पार्लियामेंट सेक्रेटरी से मिला, जिन्होंने आश्वासन दिया कि महासभा की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा। यद्यपि यह आश्वासन कभी पूरा नहीं हुआ। परिणामतः गोरीशंकर मिश्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल २० सितंबर १९३७ को भरतपुर रेलवे स्टेशन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला। जिना कांग्रेस कमेटी आगरा के निर्देशन में एक मण्डल कमेटी की भी स्थापना की गई। राज्य से मांग की गई कि वह प्रजामंडल को कानूनी मान्यता प्रदान करे परन्तु राज्य सरकार ने यह मांग मानने से इकार कर दिया और अपने दमनकारी कृत्यों को जारी रखा। परिणामतः राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ हुआ और कुछ ही समय में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या ४७३ तक पहुँच गई। अंततः दिसंबर, १९३६ में राज्य ने प्रजामंडल को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया।

### बोम्बे

अन्य राज्यों ने समान ही राज्य में निरंकुश शासन पद्धति विद्यमान थी। समूचे राज्य में भ्रष्टाचार का बोझावाला था और जनता स्वच्छ प्रशासन की मांग कर रही थी परन्तु राज्य की ओर से समूचे राज्य की सीमाओं में सभी प्रकार के समाचार पत्रों गवर्नरी से संचालित पुस्तकों और चित्रों पर भी इस आधार पर रोक लगा दी गई थी कि इनमें अश्लीलता का साहित्य होता है। राज्य की दमनकारी नीति का पहला शिकार ७ मार्च, १९३१ को पंचायत बोर्ड का सरपंच रामनारायण सेठ हुआ जिसको पुलिस ने इसलिये बुरी तरह पीटा क्योंकि उसने एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना और बेगार प्रथा की समाप्ति की मांग की थी। राज्य में अलख फैलाने की दृष्टि से महात्मा गांधी की जय जैम नारो पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।



## बोकारो लखर-कांड

बोकारो में ध्वज प्रामन क विरुद्ध आचार उद्यम क लिए १९१३-१४ में म्यादी गौतमधम के द्वारा बुरू में एक हिमकारिणी दला की व्यापना की गई थी। धर्म और नागरिकों में गवर्नेटिक चेतना विकसित हुअो जा रही थी और राज्य सरकार पर एक उद्दी और उभर मंड प्रकटनाथ बनाए प्रचुर नार मेडो और बादकाल शास्त्रा का गण्ड क विनाशित कर दिया। परन्तु इस कदमकारी नीति के बावजूद भारत क सभी समाचारपत्रों में भारत में ध्वज आच्छादार की कही आलोचना की गई। इनके समाचारपत्रों में भारत के गहन सभी महागवा मानाका मिह्र पर आच्छादार क आगमन महाग गौतम उनक नाम से नए प्रकाशित हुए। १९१० में इंग्लैंड में द्वितीय मोनमर सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें बोकारो के महागवा गमाविह्र न भी भाग लिया। इस अवसर पर 'बोकारो प्रामन' जीवन क अवर्णन एक पुस्तिका प्रकाशित की गई जो द्वितीय बादमर क प्रतिनिधित्व और विटिंग लन्दन दम्पती में विनिमित की गई। इस पुस्तिका में महागवा गमाविह्र क निरुद्ध प्रामन का मन्त्रीय विवरण प्रस्तुत किया गया था। परिणामतः राज्य सरकार इन्वेस्टिड हो उठी और मन्त्रागणाल बकील, सुवर्गम, म्यादी गौतमदाम, बदनमन, बड़ीप्रसाद, माहननाथ व्याख्यात और बहमीचद मुगना की गिरफ्तार कर लिया गया। द्वाविह्र में बहमीचद मुगना बाद में मुनवीर बन गया। इन व्यक्तियों पर अतिरिक्त बिना पविष्ट्रिड का मुकदमा चलाया गया। राज्य सरकार की ओर से यह सर्वे दिया गया कि मन्त्रागणाल बकील और उनके साथियों द्वारा त्रिपती उन्धिया में गुप्त एक निम्न गण है, और इस प्रकार बोकारो राज्य का बदनाम किया गया है। अतः अन्तर्गत में उपरुक्त सभी व्यक्तियों की अतिरिक्त मान लिया और उन्हें मेगन सुपुर्द कर दिया गया में ११ जनवरी, १९२४ का मुकदम का फैसला हुआ जिसमें सबों अतिरिक्तों की छ. महीने में लेकर तीन वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में महागवा के पुत्र के जन्म-मयागेह्र पर गरित व्याख्यात और गरित पौद्गलान को दिया कर दिया गया जिसका जन्म द्वारा मध्य व्यापन किया गया।

## बोकारो -

बोकारो में भी राज्य की निरुद्ध व्यवस्था क विरुद्ध आच्छाद जिन-

वारिसी सभा के द्वारा जयनारायण व्यास के नेतृत्व में १९२५ में प्रारंभ हुआ। चांदसराय के नाम से कई चुने पत्र भी लिखे गए। कांग्रेस का मुख्य कारण यह था कि नागरिकों को किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार देने या देना लेना निलंबित की स्वतंत्रता नहीं थी और राज्य का समूचा प्रशासन प्रशासन मंत्री सरमुखदेव के नेतृत्व में प्रशासित अभ्यास हो गया था। ११ सितंबर १९२५ को जोधपुर में एक सांख्यिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें लालाभाईपूरा शासन की समाप्ति की मांग की गई। मुखदेव प्रसाद की नीतियों की कट मालोचना करने हुए महाराजा से यह अनुरोध किया गया कि वे मुखदेव प्रसाद को अविमर्श अपने पत्र से मुक्त कर दें। ब्रिटिश रेजीडेंट ने मुखदेव प्रसाद का पक्ष लेते हुए शासन को बल प्रदान करने की नीति को बढ़ाया। परंतु जब राज्य ने जनता की भाषा पर कोई ध्यान नहीं दिया तो जयनारायण व्यास ने सुनेयाम शिक्षा से शुरू राजस्व न देने की धमकी दी। १६ सितंबर १९२६ को जयनारायण व्यास और मानस राज मुराणा ने सांख्यिक सभा को संबोधित करते हुए पोपनबाई की पोल नामक पुस्तक विवरित की जिसमें प्रशासन की कट मालोचना की गई थी। मन जयनारायण व्यास आनंद राज मुराणा और भदरनाथ सराफ को राज्य विरोधी कार्य करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तीन घण्टे से पांच घण्टे तक के बागवान की सजा सुनाई गई। जनता के द्वारा भी इस फैसले का बड़ा विरोध किया गया यहाँ तक कि पुलिस को साड़ी बांध करना पड़ा जिसमें से कई व्यक्ति घायल हुए। लगभग १० व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए जिनमें कुछ विद्यार्थी भी शामिल थे।

**सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ**

१९२१ में जयनारायण व्यास और अन्य व्यक्तियों की रिहाई के बाद साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। १० मई १९२१ को जोधपुर युवा संघटन द्वारा आयोजित एक सांख्यिक सभा में स्वदेशी वस्त्र धारण करने विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने और विदेशी सराफ की दुकानों के सामान धरना देने का निश्चय किया गया। साथ ही साथ नागरिकों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार दिए जाने के लिए और लागू करने के समर्थन करने तथा राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की गई। राज्य ने युवा दमन चक्र तेजी से चलाया प्रारंभ किया और जयनारायण व्यास मानस राज मुराणा व्यास अभयमन मर्ता

और जोधपुर राजा परिषद् के अनेक सदस्यों को आपत्तिजनक सामग्री वितरित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया परन्तु इनसे जन-उत्तेजना और अधिक बढ़ी, यहाँ तक कि २९ जनवरी, १९३२ को मारवाड़ हिन कारिणी सभा को गैर कानूनी समझ घोषित किया गया और दामनराज चौधमजी दावा महिन अनेक नागरिक गिरफ्तार कर लिए गए। राज्य सर्वकारियों सर को चेतावनी भी गई कि वे किसी भी आन्दोलन में भाग न लें अन्यथा उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।

■ मार्च १९३२ को राज्य द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें नागरिकों से किसी भी आन्दोलन में भाग न लेने के लिए आग्रह किया गया था—इस के रूप में छ महीने का सारावाय और जुर्माना किए जाने का प्रावधान भी था। १९३४ में मारवाड़ रजिस्टर सोसाइटी सोर्गिमेंट जारी किया गया, जिसमें नागरिकों पर और भी अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए।

**प्रजामंडल की स्थापना :**

परन्तु राज्य की दमनकारी नीति के बावजूद १९३४ में मारवाड़ राजा मंडल की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य जनता की नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा करना और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। १० मार्च १९३५ को स्थिति का अन्वेषण करने के लिए अवाहूरनाल महारु ने जोधपुर की यात्रा की। एक स्वागत समारोह में बीजते हुए महारु जी ने जोधपुर के नागरिकों से घरील की कि वे अपने आपको ब्रिटेन के विक्रम भाण्ड के तत्पर्य का एक अभिन्न अंग समझें। इसी बीच राजन सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया अतः "नागरिक अधिकार रक्षक सभा" के नाम से एक नए समूह की स्थापना की गई। अर मई-जून, १९३५ ■ राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पीठ में वृद्धि की तो इस समूह ने विद्यार्थियों का नेतृत्व करते हुए आन्दोलन किया और २१ जून, १९३५ को शिक्षा दिवस मनाया। अतः राज्य सरकार को झुकना पड़ा और पीठ वृद्धि वापस लेनी पड़ी। जुलाई, १९३६ में "नागरिक अधिकार रक्षक सभा" द्वारा जनता को नागरिक अधिकार दिए जाने और विधान सभा की स्थापना की मांग की गई परन्तु आन्दोलन को कुचलने की दृष्टि से २१ सितंबर १९३६ को दामनराज चौधमजीवाला, मानमन जैन और मधुसूदन जैन को गिरफ्तार करके जमना आसी, दीनतपुरा और पर्वतसर के किलों में एक वर्ष के लिए

नजरबंद कर दिया गया। जब केवल सचनेहार प्रसाद जर्मन ही सभासदियों का एकमात्र नेता बचे थे। परन्तु उन्हें भी नवम्बर, १९३७ में गिरफ्तार कर लिया गया। जब क्योंकि मारवाड़ प्रजामंडल और नागरिक अधिकार रक्षक समाज और बाटूनी मण्डल घोषित किए जा चुके थे। अतः १९३८ में मारवाड़ लोक परिषद् के नाम से एक नई मण्डल की स्थापना की गई। १९४० में मारवाड़ लोक परिषद् द्वारा महाराजा के मन्त्रिमंडल में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन आरंभ किया गया।

### उदयपुर

अन्य राज्यों के समान ही उदयपुर में भी राज्य के निरंकुश शासन के विरुद्ध जन असंतोष उभर रहा था। ब्रिटिश सरकार के प्रति करने पर महाराजा उदयपुर में राजपूतों के नाम एक असील प्रसारित करने हुए धनुरोध किया कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन से बिल्कुल दूर रहें। परन्तु महाराजा की यह असील अधिक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकी और अतः यह जन असंतोष एवं राजा की विजोतिया आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ।

### विजोतिया आंदोलन

जमाकि हम सिद्ध वृष्णी में दब चुके हैं १९३२ में कनक हातड की मध्यस्थता के परिणामस्वरूप विजोतिया का आंदोलन तात्कालिक समाप्त हो गया था परन्तु ठिकाने का जागीरदारों ने असंतोष का पालन नहीं किया और विजोतिया के विमानों पर पुनः नए कर लगाए। परिणामतः बाध्य होकर किसानों को ठिकाने के विरुद्ध पुनः सभासद आरंभ करना पड़ा। आंदोलन की गति देने के लिए विजोतिया विमान पंचायत ने विजयसिंह पविक को आमंत्रित किया जिन्होंने १८ मई १९३७ को विजोतिया के निवृत्त स्वामिन्वर नाम पर किसानों से अग्र की। पविक ने परामर्श दिया कि किसानों को बड़ा हुआ भूराजस्व दन से इकार कर दना चाहिए और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना चाहिए। पविक के परामर्श पर विजोतिया पंचायत का विमानों ने प्रतिवाचक गांवों की घराने गाँव पट्टन और मछरान न करने का दबन किया। कई नागरिकों ने पविक का प्रतिवाचन थड़ा स्पष्ट करने के रूप में घराने जान बखार। वे समाचार जब मन्त्रिमंडल कमिशनर जी० सी० टॉच को मिले तो वह मन्त्रिमंडल मंत्रियों को लेकर विजोतिया की ओर रवाना हुआ जिसमें विजोतिया किसानों की आतिथ्य किया जा रहा।

हिमालों की परिभाषा जमीन जल वर भी मई और ऊपर का मविहरी म  
 बग रान बना । परन्तु हिमाली न राननी नी बि जा बोर्ड अभीन लेगा बह  
 दरी देन योग्य और इस गजान नितीन्या न गिवात के दग्नामारे का  
 मपना करने के निग के दग्निउ हा मग । घादावन को बुचनन की दृष्टि मे  
 महाराष्ट्र उदयपुर के घादेन मे घादा नवावन वा गंग काउनी गीगिन कर  
 दिया गया ।

## हरिमाउ उपाध्याय की मध्यम्यता

विश्वोन्मिषा विमाना गी और मे १६२६ म हरिमाउ उपाध्याय न द्वेष  
 मे मरुत क्पागिन किया बिषये गणितापम्बल्य एर समझीया हुआ । इनके  
 अनुसार विमान की और मे बह घादावन दिया गया कि १६२२ के समझीये  
 का पूर्ण रूप मे गवन दिया जायता परन्तु १६३१ मे डिवाडे के द्वारा समझीये  
 का पुन उन्नयन किया गया । इन घरेन, १६३१ मे मागिकवरात बर्मा के  
 केदृव मे विमानों के जवदम्बी बुधि पर कता किया और बुनाई की ।  
 डिवाडे और राउत के द्वारा दमन-नीति का मापन लिया गया और मागिकव  
 नाव बर्मा म मादुमाल मद्रि २६ विमानों को पुनिन मे बुरी तरह गीन  
 परन्तु घादीनन निर भी घीया नहीं हुआ और ३० घरेन, १६३१ को विमानों  
 ने निर जमीन को जोना, ७ विमान गिगनार लिए गए परन्तु ३ मई को  
 उन्हें वेनाबनी देकर छोड़ दिया गया । इस घादीनन के दौरान मरुत  
 म्बिषी ने भी भाग लिया बिमने भीमनी बिषया, भीमनी घजना भीमनी  
 बिमनादेवी, भीमनी दुर्गा, भीमनी मागीरभो भीमनी गुरगी, भीमनी  
 रमादेवी बीगी और भीमनी म्कुन्नात गयी ने भाग लेते हुए मायापह  
 दिया गया घरे माहून के माय पुनिन-दमन बह का सामना किया । घनेक  
 विमान मायापहियों की गिरफ्तार किया गया और लम्ह विभिन्न म्बधि के  
 बाराधान का दंड दिया गया । म्बिषी और म्बिषी न बिगरे दग् दृष्टि मे  
 महाम्मा गादी और म्मनामान बजाव मे म्बल्लकता करने का अनुरीय किया  
 गया परन्तु दोनो ने ही इस प्रस्ताव को म्मशीनार कर दिया । हरिमाउ उपाध्याय  
 न पुनिन के दमन बह की जाव करने की माग की । उबर दूमरी और सेठ  
 म्मनामान बजाव न मेवाड की मावा की और म्मना म्भी मर मुवदेन  
 म्माद मे घेंट की । म्मनामान बजाव के निर्देश पर २६ जुलाई, १६३१ को  
 म्मनामान गुप्ता ने विश्वोन्मिषा की मावा की परन्तु उन्हें गिरफ्तार कर लिया  
 गया और पुनिन ने बुरी विममता मे उनकी पिशाई की । परिणामन घादीनन

ने धीरे-धीरे पकड़ा। घनन प्रगणन सभी सुजदेवसिंह के इस आग्रहान पर कि बिजोलिया किसानों की जपत की गई सजति और भूमि सीधे सीधे जायगी, बिजोलिया सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार बिजोलिया बिमान सत्याग्रह के समुप टिनाने की झुनना पडा और सत्याग्रहियों की मांगें स्वीकार करनी पडी।

### उदयपुर में आंदोलन

ऐसा प्रतीत होता है कि बिजोलिया आंदोलन का प्रभाव उदयपुर शहर पर भी पडा। २ जुलाई १९३२ को नए करो के बिरोध में उदयपुर के नागरिक पीरबीराट में एकत्रित हुए और उन्होंने महामण्डल में प्रार्थना की कि नए कर समाप्त किए जाए और पंडित मुनदेव प्रसाद सहित सभी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाए परन्तु मांगें मानने के स्थान पर पुलिस ने भी गोली बनाई जिसके परिणामस्वरूप लगभग ५० व्यक्ति हताहत हुए जिनमें से एक व्यक्ति का प्राय गिलोश भीषण में लैरा हुआ मिला। लगभग ३० व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए बि हे बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिया गया। बाद में १३ जुलाई १९३२ की नगरियों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराणा से मिला जि होने यह आश्वासन दिया कि वे जनता की कठिनाइयों की स्वयं देखेंगे।

१९३४ में राज्य का राजनीतिक वातावरण बड़ा ही दमघोड़ था। नागरिक बिचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मण्डल बनान और स्थलकता पूर्वक घूमने फिरने की मांग कर रहे थे। परन्तु मेवाड़ राज्य प्रगणन इन मांगों की मानने के लिए तैयार नही था। घन १९३७-३८ में भारतीयजनता दली के नेतृत्व में एक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया और राज्य की समनकारी नीति के बावजूद मघेय १९३८ में प्रजामंडल की स्थापना की गई, यद्यपि इसे राज्य के द्वारा मंद कानुनी घोषित कर दिया गया। राज्य-पुलिस ने प्रजामंडल कार्यालय पर छापा मारा तथा भारतीयजनता दली और रमेराचन्द्र व्याम को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। ३० सितंबर १९३८ को मण्डल प्रजा मंडल के उपाध्यक्ष भूरेनाथ बघा को गिरफ्तार कर लिया गया। इन परिस्थितियों में २१ सितंबर १९३८ को सर्वजन्य घनना आंदोलन आरंभ किया गया। यह आंदोलन सीधे ही समुचे राज्य में फैल गया। राज्य के द्वारा सभी प्रकार की सावर्जिक सभाओं एवं मण्डलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था

परन्तु इसके बाद एक घटनामान जोशी द्वारा घोषित एक राजनैतिक सभा मानवाधिकार सम्पन्न हुई जिसमें लगभग ३००० व्यक्ति उपस्थित थे । मजिस्ट्रेट अज्ञात आंदोलन राज्य के अन्य भागों में भी फैलने लगा । ११ अक्टूबर, १९३८ को नाथद्वारा में मजिस्ट्रेट अज्ञात आंदोलन धारण हुआ, जहाँ पास स्थिति गिरफ्तार हुए । २३ अक्टूबर, १९३८ को मेवाड़ प्रजामंडल की कार्य-कारिणी के सदस्यों का चुनाव हुआ जिसमें माणिक्यनाथ वर्मा गोपालान गुज, प्रोफेसर प्रेमनाथराव मावुन, सरदारविहारी चौधरी और सरदार प्रतापनाथ शामिल थे । इस भी निश्चय किया गया कि १५ मिनट की सभाओं की एक जमा अज्ञात में फैला जायगा । इस समय माणिक्यनाथ वर्मा का यह विचार था कि राज्य को दमनकारी नीति को देखते हुए प्रजामंडल को मानिपुल भीति के स्थान पर मानववादी नीति बनानी चाहिए परन्तु हरिभाऊ उपस्थित ने इसका विरोध किया । वे गांधीवादी एवं अहिंसक साधनों में विश्वास करते थे ।

३ फरवरी, १९३९ को माणिक्यनाथ वर्मा ने राज्य के आदेश का उल्लंघन करते हुए मेवाड़ सीमा में प्रवेश किया । उन्हें जहाजपुर तहसील में गिरफ्तार कर लिया गया जहाँ वे अपने अन्य सहयोगियों के साथ मेवाड़ प्रजामंडल के गीत गा रहे थे और उनकी जय गहरार कर रहे थे । माणिक्यनाथ वर्मा को एक वर्ष के बंदी कारावास और २५१ रुपये के जुर्माने का दंड दिया गया, जुर्माना सदा न करने पर ३ माह के बंदी कारावास का प्रावधान था । कुल मिला कर मजुबे राज्य में २८८ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिसमें से ३५ व्यक्तियों को विभिन्न अवधि के कारावास का दंड दिया गया । जमानालाब अज्ञात न हरिनाथ नारदा ने अनुरोध किया कि वे मेवाड़ के प्रधान मंत्री वर्मा नारायण को प्रजामंडल में सम्मिलित करने के लिए राजी करें । अतः महात्मा गांधी के परामर्श पर ३ मार्च, १९३९ को सभाओं-आंदोलन स्थगित कर दिया गया ।

**अज्ञात (१९३५-१९३९)**

ब्रिटिश भारत प्राप्त होने के कारण अज्ञात राजस्थान के राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र बना । १९२५ में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई । अज्ञात की कार्य समिती ने भी यह निश्चय किया कि सार्वजनिक कमीशन की यात्रा के दौरान उनका सहिष्कार किया जाय ।

१९२१ से १९२६ तक सरकार में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी परन्तु जब १२ मार्च १९२० को महात्मा गांधी ने दांडीकूच भारत किया तो इसके सरकार में भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। सरकार कांग्रेस कमेटी को सरकार के द्वारा गैर कानूनी समझन घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही अन्य राज्यों के समान सरकार में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ हुआ। विनायक सावरकर महाराष्ट्र का आयोजन किया गया और विदेशी वस्तुओं एवं शराब को दुकानों पर धरना दिया गया। इन मांगवाहियों में रामनारायण चौधरी बीकानेरवास प्रभावशाली भूमिकाएँ निभाईं। बालकृष्ण कौन सावरकर जयपीनारायण जयानुदीन जयधूर और चन्द्रमान शर्मा प्रमुख थे। इन सविनय अवज्ञा आंदोलन में गवर्नमेंट कांग्रेस कांग्रेस के विद्यार्थियों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण था। विद्यार्थियों ने कांग्रेस में भी सरवाग्रह किया। इन विद्यार्थियों में डाक्टर गोपीनाथ शर्मा भी शामिल थे जिन्होंने सरवाग्रह करने के आरोप में कांग्रेस से निवृत्त किया गया। इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना भी घटी। कुछ विद्यार्थी राष्ट्रीय भंडा लिए हुए सड़को कोमल सरकार की कारोबारियों में से गुजरे कि इसी बीच कांग्रेस के बाइस दिवसियल बनल हाउस ने विद्यार्थियों को प्रभावित किया और राष्ट्रीय भंडे का अपमान करते हुए उनका दुकानें दुकानें कर दिए। परन्तु जब रामनारायण चौधरी ने इस घटना के प्रति सड़को कांग्रेस के दिवसियल और बाइस दिवसियल में बड़ा विरोध प्रकट किया तो उन्होंने सड़को ही दिन सविनय अवज्ञा में समाप्त करी। मार्च १९२१ में गांधी दक्षिण अफ्रीका हुआ जिसके परिणामस्वरूप समूह भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया तदनुसार सरकार में भी आंदोलन स्थगित हो गया।

### राजस्थान में आन्दोलन की गतिविधियाँ

परन्तु गांधी इतिहासकारों के बावजूद देश के युवा छात्रवासियों को समुचित नहीं किया जा सका। समूहों उत्तर भारत में छात्रवासियों की एक महार दौड़ घटी और राजस्थान भी छोड़ना नहीं रह सका। १० जून का प्रवाद शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में छात्रवासियों की गतिविधियों का केंद्र सरकार बना। पंडित जवाहर प्रसाद शर्मा की शिवा-दीक्षा दयानंद स्कूल एवं गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार में हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जवाहर प्रसाद पर दयानंद स्कूल के एक अन्य विद्यार्थी रामनिह का प्रभाव रहा और १९२० में वे



राजकीय मतिविधियों में सम्मिलित हो गए। इस समय की पुष्टि इस घटना से होती है कि ज्ञानाग्रमाद ने रामचंद्र और रामचंद्र के साथ ही डी० ए० सी० स्कूल के एक चपरासी और मन्ना साहिब बदन अग्रमेर के निमित्त से २ रुपये और बारहपन गरीबों के लिये छद्म डी के जमान में लगभग ६ महीनों का प्रगतिशील प्रान्त किया था।

अग्रमेर के कमिशनर की हत्या का प्रयत्न

मार्च, १९३२ में ज्ञानाग्रमाद और उनके सहयोगियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की धमकित करने के लिए अग्रमेर के चीफ कमिशनर की हत्या करने का प्रयत्न रखा। ज्ञानाग्रमाद के एक सहयोगी रामचंद्र बापत ने चीफ कमिशनर की हत्या करने का प्रयत्न प्रयत्न किया। इस घटना में संपूर्ण अग्रमेर शहर में भड़कना मचा दिया। ज्ञान पुनिम द्वारा निष्कारण कर दिया गया और भारतीय बंद छद्मता की धारा ३०७ के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया गया।

राजकीय कानून अग्रमेर के चपरासी की मृत्यु का प्रयत्न

राजकीय के अंतर्गत ही इन की घन की कमी का सामना करना पड़ रहा था घन ज्ञानाग्रमाद तथा उनके अन्य सहयोगी जगदीश दत्त, मदनमोहन, हेमचंद्र और रामचंद्र बापत ने अग्रमेर एक छोड़ना तैयार की जिसके अनुसार राजकीय कानून अग्रमेर के चपरासी को इन समय मृत्यु था जब वह इन्तोरिया बंद अग्रमेर से कानून-स्टाफ का बैग लेकर लौट रहा हो। छोड़ना के अनुसार जैसे ही चपरासी बैग लेकर बैंक में बाहर निकलेगा हेमचंद्र जिसके पास रिवाल्वर थी या चपरासी को मारकर देकर गिरा देगा और इसी समय ज्ञानाग्रमाद दफने का बैग छीन लेगा। सहयोग के लिए ज्ञानाग्रमाद ने भी एक विस्तृत प्रान्त पास रखा था। यह भी निश्चय किया कि रामचंद्र बापत और मदनमोहन दफने का बैग लेकर भाग जाएंगे। एक अन्य सहयोगी जगदीश दत्त को थोड़ी दूर पर तैयार किया गया जो पुलिस के जाने की सूचना दे मने। तदनुसार गिरफ्तार के सदस्यों ने अपने वस्त्र बदले और अग्रमेर मित्रा बोर्ड के कार्यालय के शीर्षक अग्रमाद अग्रमाद से लिया कानून का चपरासी बैग की राशि लेकर बाहर भागा। हेमचंद्र ने उसे मारकर दिया परंतु ज्ञानाग्रमाद दफने का बैग छीनने में प्रयत्न रहा। रामचंद्र बापत ने जोर से चिल्ला कर हेमचंद्र को धमका दिया कि वह बैग

छीन के परतु बहुत भी सम्पन्न रहा इसी बीच पुलिस धा गई परिणामतः सभी धानकबादी भाग गए ।

बापसराय की हत्या का असफल प्रयत्न

१९३४ के आरम्भ में ज्वालाप्रसाद ने बापसराय की बीकानेर यात्रा के दौरान हत्या करने की पुनः एक योजना तैयार की । ज्वालाप्रसाद ने २ रिवास्तगी एवं बारनूगी की व्यवस्था की और अपने सहयोगी रामचन्द्र बापत के साथ बीकानेर रवाना हो गए परन्तु पुलिस की सतर्कता के परिणामस्वरूप योजना क्रियावित नहीं की जा सकी ।

मेयो कानेज घम केस

१९३४ के मध्य में एक बार फिर बापसराय की हत्या करने का प्रयत्न किया गया । बापसराय अपनी यात्रा के दौरान मन्नेवर से होकर गुजरने वाले थे । यत पत्र निश्चिन्त किया गया कि इस यात्रा के दौरान बापसराय की हत्या कर दी जाए । धानकबादियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हथियारों को कहां ठुकाया जाए क्योंकि यह निश्चिन्त था कि बापसराय की यात्रा के दौरान पुलिस की बड़ी व्यवस्था रहेगी यत धानकबादियों ने यह निश्चिन्त किया कि मेयो कानेज के समीप के मकान जो श्रीधामराज के कारण खाली पड़े थे में हथियार छिपा दिए जाए । इस कार्य को करने का उत्तरदायित्व कन्हूचन्द नामक धानकबादी को भौता गया जो हथियारों से भरे तीन घंटे साइकिल पर चढ़कर मेयो कानेज के समीपस्थ मकानों में एक घाटा परतु छ सात दिन के पश्चात् ही पुलिस ने छापा मारा और हथियार बरामद कर लिए । कन्हूचन्द गिरफ्तार कर लिया गया ।

जयपुर के सूरजवरण की घमकी भरा पत्र

धानकबादियों को धन की निरन्तर कमी हो रही थी भल ज्वालाप्रसाद और उनके सहयोगी रामदास शर्मासह और नृसिंहदास न जयपुर के सेठ सूरजवरण दिया न नाम एक घमकी भरा पत्र भेजा जिसमें यह कहा गया था कि पत्र मिलने ही ५००) रुपये धान समाज मंदिर में रख पाए प्रत्येक यभीर परिणाम भुगतने होंगे । सूरजवरण ने पुलिस को सूचना दे दी और इस प्रकार यह योजना सम्पन्न हो गई ।

सुरक्षित बाज नृसिंहदास और कुमारानंद ने मिलकर योजनावादी

में शाका खाने की योजना बनाई परन्तु किसी मुख्यविश्व ने सी० आर० डी० को सूचना दे ली और इस प्रकार यह योजना भी विफल हो गई ।

### डोंगरा गोलीकाण्ड

४ अप्रैल, १९३५ को धर्मपुर के उप अधीक्षक, पुलिस पी० ए० डोंगरा और सी० आर० डी० के सर्वइस्पेक्टर ललीनउद्दीन को हत्या करने का प्रयत्न किया गया । ज्वालाप्रसाद के नेतृत्व में एक योजना तैयार की गई थी जिससे अनुसार यह निश्चय किया गया कि पी० ए० डोंगरा की हत्या कर दी जाए क्योंकि ये ब्रिटिश समर्थक विचारधारा के थे । योजना के अनुसार तब हुआ कि मांगीलाल नामक आतंकवादी डोंगरा को सिनेमा दिखाने के लिए ले जाया और जब वह सिनेमा देखकर वापस लौट रहा होगा तब रामसिंह नामक एक अन्य आतंकवादी उसे गोली मार देगा । सबनुसार मांगीलाल और रामसिंह व्यास जो कि स्थानीय सभापति पद का रिपोटर था न डोंगरा को मुभाब दिया कि 'जोड्डर ए सभधोर' नामक चलचित्र देखा जाए जो कि बहुत शिक्षणस्प था । डोंगरा ललीनउद्दीन और मांगीलाल सिनेमा देखने गए । वापस लौटते समय मांगीलाल को सिनेमा में ही रह गया और डोंगरा और ललीनउद्दीन लाइविल पर पर लौट पड़े । रात में रामसिंह ने घर में रिवास्वर से डोंगरा पर गोली चलाई जो कि उनके हाथ पर लगी और ललीनउद्दीन गिर पड़े । रामसिंह के द्वारा २ गोलियाँ और चलाई गई जिसमें से एक ललीनउद्दीन के हाथ में लगी तत्पश्चात् आतंकवादी भाग पड़े हुए । बाकी ललीनउद्दीन के पश्चात् रामसिंह को विरूपण कर दिया गया । पुलिस को दिए गए अपने बयान में रामसिंह ने इस समय का उत्पादन किया कि ये समूची योजना ज्वालाप्रसाद द्वारा तैयार की गई थी और उसी ने रिवास्वर भी दिया था ।

### ज्वालाप्रसाद की निरक्षरता

२६ अप्रैल, १९३५ को ज्वालाप्रसाद विरूपण कर लिए गए उसे २३ सितंबर, १९३५ तक हिरासत में रखा गया । इस हिरासत के दौरान ज्वालाप्रसाद ने अपने आई बालीचरण को एक कुतथाया में पद लिखा जिसमें बालीचरण से यह फावट किया गया था कि यह १४ या १५ मई की रात को १२ बजे से २ बजे के समय उसे 'एक सिगरेट बेस और सिगरेट' पचाई 'रिवास्वर और वास्तु दे दे । इसी बीच ज्वालाप्रसाद बर्मा ने बेल से

हो एक घमकी मरा पत्र ताकासिक एव पुलिस अधीक्षक सी घाई ही मुमताज हुसैन को भेजा जिसमें यह घमकी दी गई थी कि यह गिरफ्तार घातकवादियों को तलाश और बिना शर्त गिरा कर दे "घमका उसका भी बही हाल होगा जो डोंगरा का हुआ था" । ज्वालाप्रसाद को इस भयकर गतिविधियों को देखते हुए उसे १२ सितंबर, १९३५ को १८१८ के रेगुलेशन अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली की जेल में भेज दिया गया ।

ज्वालाप्रसाद की रिहाई और उसका अजमेर में मध्य स्वागत -

नवंबर, १९३८ में भारत सरकार ने ज्वालाप्रसाद को इस शर्त पर रिहा करने का निश्चय किया कि वह अत्यंत या अपत्यंत कम घातकवादी राजनीति से सम्बन्धित नहीं रहेगा और न किसी भी ऐसे संगठन में सहयोग करेगा जो हिंसा से विश्वास रखता हो और साथ ही बिना चीफ कमिश्नर की अनुमति के दिल्ली प्रांत की सीमा में शामिल नहीं होगा । परन्तु ज्वालाप्रसाद ने सगर्त रिहा होने से इफार कर दिया और भूल हजताल आरंभ कर दी । उसने महात्मा गांधी को भी सूचित किया कि वह सरकार द्वारा प्रस्तावित अपमानजनक शर्तों पर रिहा होने को तैयार नहीं है । अतः महात्मा गांधी के हस्तक्षेप पर १६ मार्च, १९३९ को ज्वालाप्रसाद को दिल्ली जेल से रिहा कर दिया गया ।

२२ मार्च, १९३९ को ज्वालाप्रसाद अजमेर पहुंचा जहां उसका मध्य स्वागत किया गया । अजमेर रेलवे स्टेशन से उन्हें एक जुलूम में ले जाया गया जो कैसरगंज और मंदार गेट होना हुआ बासीराम की धर्मशाला पहुंचा । जुलूम का नेतृत्व मागीताल सीताराम बकित, जयप्रकाश, राधावल्लभ और स्वामिहारी सिंह कर रहे थे तथा जुलूम में "इकनाक जिदाबाद" "रामसिंह को रिहा करो" और "मगनसिंह, महात्मागांधी और अवाहूर लात नेहरू की अपत्रयकार" के नारे लगाए जा रहे थे । जब जुलूम बासीराम की धर्मशाला पर पहुंचा तो स्वामी कुमारानंद ने ज्वालाप्रसाद का आतिथ्य कर स्वागत किया ।

२२ मार्च, १९३९ को ज्वालाप्रसाद की रिहाई पर मुबारकबाद देने के लिए एक और सभा का आयोजन किया गया जिसका समापन जय-नारायण व्यास ने किया । सभा में अनेक बतारों ने भाषण दिए जिनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजमेर के सचिव बाबा नृसिंहदास, डा० जे० एल० मुखर्जी,

श्यामी कुमारानंद, रामजीलाल और राधाकृष्णन सम्मिलित थे । बाबा मुनिह-  
दास ने अपने विचारोत्तेजक भाषण में देशभक्ति की भावना पर बल दिया और  
यह आग्रह किया कि भारतीयों को जर्मनी व इटली से शिक्षा ग्रहण करनी  
चाहिए तथा ज्वालाप्रसाद का अनुसरण करना चाहिए । अंत में सभा में एक  
प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ज्वालाप्रसाद शर्मा की बिना शर्त रिहाई  
पर प्रसन्नता प्रकट की गई ।

इस प्रकार जब १९३६ में महात्माजी की विधियां अपनी चरम सीमा  
पर थी उसी समय द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया । महात्मा गांधी की अपील  
पर ब्रिटिश भारत तथा राजस्थान में सर्वत्र महासत्याग्रह स्वर्गित कर दिया  
गया । एक बार फिर भारतीय राजा महाराजा ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा  
के लिए आगे आए और उन्होंने तन, मन, धन में ब्रिटेन की सहायता की ।



## जागरण और एकीकरण (१९३९-४७)

विभिन्न राज्यों में प्रजासत्ताकता की स्थापना का परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की देशी रियासतों में 'उत्तरदायी शासन' की भाग की जाने लगी परन्तु १९३६ में द्वितीय महायुद्ध हो जाने के फलस्वरूप जब ब्रिटिश भारत में आन्दोलन स्फुरित हो गया तो इसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। परिणामतः राजस्थान में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की माग को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन संस्थापनी तौर पर स्वरहित कर दिया गया। दुर्भाग्य से देशी राजाओं की स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझ के यही सोचते रहे कि भारत में ब्रिटिश शासन के बने रहने से ही उनका निरंकुश राज्य बना रह सकता है।

**द्वितीय महायुद्ध और राजस्थान में राजाओं का बुद्धिकोश —**

अगस्त, १९३९ में यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि विश्व द्वितीय महायुद्ध के कगार पर था पहुँचा है। बीकानेर के महाराजा सभ्यतः भारतीय राजाओं में प्रथम थे जिन्होंने ब्रिटेन के सम्राट को सहायता प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ५ सितम्बर १९३९ को द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने पर महाराजा बीकानेर ने ब्रिटिश सम्राट को पुनः अपनी ओर से सहायता देने के प्रस्ताव को दोहराया और सम्राट के नाम तार भेज कर यह घोषणा प्रकट की कि ब्रिटेन को महायुद्ध में सीधे सफलता मिलेगी। महाराजा बीकानेर ने ब्रिटेन की ओर से महायुद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की जिसे ब्रिटेन ने द्वारा स्वीकार कर

दिया गया। परिणाम २६ मई १९४१ को बीकानेर के महाराजा ने पोरबंदर के लिए प्रस्थान किया उनका प्रसिद्ध 'गंगा रियासत भी हाथ में भेजा गया। इसी प्रकार जयपुर औरगढ़ उदयपुर, बजवर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा के महाराजाओं ने भी हर समय सहमता देने का प्रस्ताव रखा। महाराजा बीकानेर ने वायुमार्ग के उन सैनिकों को पुरस्कार देने की घोषणा की जिन्हें युद्ध में शौर्यवान् सर्वोत्तम योगदान दिया था।

इस प्रकार जहाँ तक पोरबंदर राजस्थान की देशी रियासतों के राजाओं के हितों को हर समय सहमता की वही दूकरी पोरबंदर के विपक्ष सत्याग्रह आन्दोलन बनाए जाने की योजना थी। १९४० के आरम्भ में महात्मा गांधी की प्रेरणा पर राजस्थान की देशी रियासतों में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ। १९४२ के आरम्भ छोटा आन्दोलन में राजस्थान ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अखिल भारत में उत्तरवासी शासन में लोकप्रिय सरकार की स्थापना की मांग की जाने लगी। जनता का उत्साह प्रतीति का पोरबंदर में वृष्टभूमि में राजस्थान के राजाओं में उत्तरवासी शासन की स्थापना की मांग को लेकर चलाए गए आन्दोलन की विविध करने का प्रयत्न किया गया।

## अन्तर्गत

ब्रिटिश शासन होने के कारण राजस्थान की संप्रदाय राजनैतिक गति विधियों का केन्द्र अन्तर्गत बना। २६ जनवरी १९४० को नागरिकों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया, परन्तु विनाशपूर्ण ने सार्वजनिक सभा करने के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया। जनता के जोश की सीमा नहीं थी। अन्तर्गत के नागरिक और विचारियों ने ब्रिटिश विरोधी गति संगठित हुए विनाशपूर्ण के आदेश की अवहेलना की। परिणामस्वरूप अनेक विचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें से १२ विचारियों को प्रत्येक को ५०००००० रुपया दिए जाने का आदेश मिला। अनेक स्थानों पर पुलिस ने छापे मारे। फरवरी, १९४० में प्रांतीय कांग्रेस समिति अन्तर्गत पर छापा मारा गया तथा साथ ही साथ ५० जवाहरलाल नेहरू डॉ० जे एल मुन्शी पोरबंदर तथा मुंसिफ़ात के मंत्रियों की तलाशी भी गई क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि इनके नाम रिवाज और फारस दिए हुए हैं। देवी प्रसाद अन्तर्गत और स्वतंत्रतादिह आदि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार

किया गया। यद्यपि बाद में २ कार्य-कर्ताओं को रिहा कर दिया गया परन्तु अनेक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा गया। १० अप्रैल, १९४० को भारत सरकार अधिनियम, १९३२ के अन्तर्गत अमर प्रिटिंग प्रेस, अजमेर और उसके व्यवस्थापक भम्बालाल भाधुर के भक्तियों की तलाशी भी गई। इसका कारण केवल यह था कि पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रेस कार्यालय में 'उस पार रीतनी' नामक बन्धु की गई पुस्तक की प्रतियाँ रखी हुई हैं।

इस तनावपूर्ण वातावरण में ६ अप्रैल से १६ अप्रैल, १९४० तक अजमेर कांग्रेस ने राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का निश्चय किया। इन सप्ताह के दौरान लाठी की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। २० पीठ ऊँचे सभे पर कांग्रेस का ध्वज फहराया गया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी। साथ ही साथ विभिन्न आम सभाओं का भी आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली की एक राजनैतिक कार्यकर्ता श्रीमती प्रभाती झीरवानिया ने अपने भाषण में भारतीय नवयुवकों से आग्रह किया कि वे जविया वाले बाग के गद्दीदों से लिसा लें। जनता पर इस भाषण का बहुत प्रभाव पड़ा कि लोगों ने मरने प्यून ॥ हुस्ताशर करके प्रतिज्ञा की कि वे देश को आजाद कराके ही चैन लेंगे। ब्रिटिश सरकारवाही यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और अजमेर कमिशनर ने दण्ड संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि एक घंटे के अन्दर-अन्दर राष्ट्रीय झण्डा उतार दिया जाए और किले की ४०० गज की सीमा के अन्दर प्रवेश न किया जाए, परन्तु प्रदर्शनी के सचिव कृष्णगोपाल गर्ग ने आदेश मानने ॥ हुकार कर दिया तत्पश्चात् पुलिस ने कार्यवाही की और भड़े की जबरदस्ती हटा दिया। कृष्ण-गोपाल गर्ग को ४ मास का कठोर कारावास दिया गया। इन समस्त घटनाओं की सूचना महात्मागान्धी को भी भेजी गई। जिन्होंने अजमेर कमिशनर के आदेश की कटु-मानोचना करते हुए कांग्रेस कार्य-कर्ताओं को भी परामर्श दिया कि उन्हें 'कमिशनर के आदेश का पालन करना चाहिए।'

रेल्वे वर्कशाप में हड़ताल।

ब्रिटेन की दमनकारी नीति का परिणाम यह हुआ कि सामान्य जनता में भी ब्रिटिश विरोधी भावना बनने लगी और इसीलिए अपना विरोध प्रकट करने हेतु १५ अगस्त, १९४१ को अजमेर रेल्वे वर्कशाप के लगभग १०,०००



कर्मचारियों ने 'बैठे रहो' हड़ताल की। ब्रिटिश सरकार इस हड़ताल से इतनी घबरा उठी कि उसने सेना को भी बुला लिया। मई ३ सितम्बर, १९४१ को हड़ताल धारम ■ ली गई।

पंडित जवाहरलाल नेहरू की निरपेक्षता और उनका अजमेर के केन्द्रीय कारागृह से भागना

अजमेर रेलवे बर्कशान की हुई हड़ताल से जवाहरलाल ने भी सक्रिय योगदान दिया था। अजमेर भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत १९ अक्टूबर, १९४१ को उन्हें निरपेक्ष कर दिया गया। चीफ कमिशनर अजमेर ने भारत सरकार से यह भी प्रार्थना की कि अजमेर में जवाहरलाल की उपस्थिति स्थानीय आंदोलन को उग्र बना सकती है। अजमेर उन्हें मुख्य किसी दूसरे राज्य की जेल में भेज दिया जाए। परन्तु कोई भी दूसरी प्रांतीय सरकार जवाहरलाल को लेने की तैयारी नहीं की। अजमेर उन्हें रवाना नहीं किया जा सका। १२ नवम्बर, १९४१ को मर्चण्ट के कुछ ही समय बाद जवाहरलाल ने जेल से भागने का प्रयत्न किया। उन्होंने कमरे के एक रोशनदान में से जो केवल ६ १/२ इंच चौड़ा था निरन्तर घबरा रास्ता बनाया परन्तु जिस समय वे बाहर निकल रहे थे तो उनके पैर से बांस ने रखा हुआ लौटे का कजस्तार टकरा गया। परिणामस्वरूप आवाज सुनकर जेल का मुख्य गार्डर आ पहुँचा उसने देखा कि जवाहरलाल जेल पर लगे हैं और उनके हाथ में चाकु भी है। मुख्य गार्डर ने जवाहरलाल को वापस आने की समझाया। जवाहरलाल इस शर्त पर वापस आने के लिए तैयार हो गए कि गार्डर इस घटना का किसी में भी बिक नहीं करेगा और मामले को बर्ती देखा देगा। परन्तु उन पर मुख्यता बनाया गया और भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत उन्हें एक वर्ष लीन बर्तीने का कठोर कारावास तथा ५० रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना मंदा न करने पर ३ माह की सजा का प्रावधान था। मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध जवाहरलाल ने अपील की जिसके पक्षरक्षण १६ फरवरी, १९४२ को उनकी सजा रद्द कर दी गई, परन्तु २५ फरवरी, १९४२ को उनके विरुद्ध एक नया मुकदमा दायर किया गया और ६ माह के कठोर कारावास का दण्ड दिया।

२९ फरवरी, १९४४ को एक अन्य कड़ी रूपान्त सिद्ध के साथ जवाहरलाल ने एक बार फिर भागने का प्रयास किया। दोनों ही कंडी बरक नं०

■ में रहे गए थे। इन्होंने बानीवाल खेलने के आस और उसके संघों को लेकर छन पर पड़ने का सकल प्रयत्न किया और लगभग १० घंटियां अपनी कमर से लपेट कर खेल की छान पर से कूट पड़े। काफी खोजबीन के बादबूढ़ दोनों ही कंडियों को पकड़ने के प्रयास विफल रहे।

### सचिनय प्रवक्ता-प्रायोजन

दूसरी ओर "भारत छोड़ो आंदोलन" की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 'सचिनय प्रवक्ता-प्रायोजन' क्षेत्र होता जा रहा था। मार्च, १९४३ तक ६४ व्यक्तियों को विरतनार किया गया था जिनमें बालकृष्ण कौल, हरिभाऊ जगध्याय, रामनारायण चौधरी, मोकुल लाल प्रसाध, ज्योति दत्त महुता, मुकुटबिहारी लाल भार्गव, लालूराम जोशी श्रीमती श्रीमती देवी भार्गव, प्रवक्ता माधुर और मोक्षानान गुप्त भी सम्मिलित थे। बालकृष्ण कौल और मोकुल लाल प्रसाध को जेल अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करने ■ आरोप में ४ माह के बंदी कारावास की सजा सुनाई गई। इन बंद के विरोधस्वरूप बालकृष्ण कौल ने भूत हड़ताल आरंभ कर दी। ब्रिटिश सरकार ने श्रीमती कौल तक को बालकृष्ण से जेल में मिलने की अनुमति नहीं दी बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप पर श्रीमती कौल को अपने पति से मिलने की इजाजत मिली। तत्पश्चात् बालकृष्ण कौल ने भी भूत हड़ताल समाप्त कर दी।

१९४४ में शिवदा कांफ्रेंस आयोजित की गई। साथ ही १९४६ ■ भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान ढूँढ़ने के लिए वेबीनेट मिशन भारत आया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन ठण्डा हो गया और सचिनय प्रवक्ता प्रायोजन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

### जयपुर

भजमेर की घटनाओं का प्रभाव राजस्थान के अन्य राज्यों पर भी पड़ा तथा विभिन्न राज्यों में राजनीतिक आंदोलनों की मुख्य भाग "उत्तरवासी शासन की स्थापना" बनी। समूचे राजस्थान की देशी रियासतों में जयपुर सबसे अधिक प्रगतिशील राज्य था परन्तु अन्य राज्यों के समान जयपुर में भी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने दमन शक का सहारा लिया। १ जनवरी, १९४० को राज्य सरकार ने द्वारा एक आदेश जारी किया गया

जिसमें राज्य बर्नधारियों को यह आदेश दिया गया था कि वे राजनीतिक मामलों के प्रस्ताव में बिल्कुल विचार प्रकट न करें। परिणामतः जयपुर प्रजा-मण्डल ने राज्य की दमनकारी नीति का विरोध करते हुए जनवरी, १९४० में एक घोषित प्रस्तावित की जिसमें जयपुर राज्य में तुरन्त "उत्तरदायी सरकारें" स्थापना की मांग की गई। इस घटना ने राज्य के प्रभावमयी राजा ज्ञान नाथ को बहुत उत्तेजित कर दिया उन्होंने प्रजामण्डल को "गंभीर परिणाम" डुगतने की धमकी भी दी। फरवरी, १९४० के अन्तिम सप्ताह में पुलिस ने प्रजामण्डल के कार्यालय पर छापा मारा और बहुत से कामकाज घबरे साफ हो गई। ६ मार्च, १९४० को राज्य सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें प्रजामण्डल को रजिस्टर्ड कराने की कहा गया था। इस घटना ने राज्य में एक नई राजनीतिक स्थिति पैदा कर दिया। अप्रैल में ९ मई, १९४० को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया कि प्रजामण्डल की अधिभार है कि वह जनता के राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर सके और संबंधित साधनों के माध्यम से जनता की बहिष्कारों को राज्य सरकार के समुदाय प्रस्तुत कर सके, परन्तु इस स्वीकारोक्ति के बावजूद राज्य ने दमनकारी नीति का परि-त्याग नहीं किया और प्रजामण्डल की बैठकों के भाग लेने वाले व्यक्तियों को सदेह की निगाह से देखना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से इस समय प्रजामण्डल के सदस्यों और कार्यकर्ताओं में भावनात्मक मतभेद उठ खड़े हुए। विरजीलाल पटवाल के नेतृत्व में एक नए दल ने जिसे 'प्रजामण्डल प्रवर्धनीय दल' के नाम से पुकारा गया, जन्म लिया। परिणाम यह हुआ कि घायली कूट के परिणामस्वरूप जयपुर "भारत छोड़ो आंदोलन" में विशेष योगदान नहीं दे सका।

नवम्बर, १९४१ में लौकर में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें जयपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ने यह मांग की कि राज्य सरकार अपनी दमनकारी नीति का तुरन्त परित्याग कर दे और प्रजामण्डल की मांग को स्वीकार करत हुए राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। इसी समय एक अन्य दल ने भी जन्म दिया जिसे "माजाद मोर्चा" के नाम से जाना जाता है। इस मोर्चे के द्वारा राज्य के निरंकुश शासन के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन प्रारम्भ किया गया। इस आंदोलन में भाग लेने वालों में मास्टर रामारख जोशी, बी० एम्० देशपाण्डे, मोमदत्त शास्त्री, लादूराम जोशी और हंस डी० राय प्रमुख थे। यह आंदोलन

समयमग डेढ़ वर्ष तक चलता रहा । धांदोवन के दौरान विदेशी शराब और वस्त्रों की दुकानों पर घरने दिए गए और तोड़ फोड़ की कार्यवाही भी हुई ।

### सर्वधानिक सुधार

२६ अक्टूबर, १९४२ को जयपुर महाराजा ने सर्वधानिक सुधारों को लागू करने की दृष्टि से एक विशेष समिति की स्थापना की थी । समिति ने ११० परिच्छेदों ( पैरेग्राफ ) का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया परन्तु गैर सरकारी सदस्यों ने इस प्रतिवेदन का विरोध किया । परन्तु इसके फलस्वरूप १९४५ में जयपुर राज्य ने समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कुछ सुधार लागू किए । वास्तव में यह 'उत्तरदायी शासन' की स्थापना की ओर एक कदम था । द्विसदनात्मक विधान सभा की स्थापना की गई । प्रतिनिधि सभा में १२५ सदस्य होने थे जिनमें से ५ मनोनीत, २५ ठिकाने के सरदारों में निर्वाचित एवं २ स्थान व्यवसायिको रिजर्वों और सैनिकों के लिए सुरक्षित थे । इस प्रकार सामान्य स्थान केवल १८ थे । दूसरे सदन में कुल ५१ स्थान थे जिनमें से १४ सदस्यों का मनोनीयन करना था, ६ सदस्य ठिकाने सरदारों द्वारा निर्वाचित तथा ३ स्थान व्यवसायी रिजर्वों और सैनिकों के लिए तथा ४ स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे । इस प्रकार स्पष्ट था कि प्रस्तावित विधान सभा महाराजा की हा में हा मिलाते वालों की सत्ता थी परन्तु इस सब के बावजूद प्रजामण्डल ने चुनावों में भाग लिया तथा उसमें उसे आभासी सफलता मिली । प्रतिनिधि सभा में से ३१ स्थानों में से २७ स्थानों पर तथा ऊपरी सदन में ३ स्थानों पर प्रजामण्डल का कब्जा हो गया । यह तथ्य हम बात का प्रतीक था कि प्रजामण्डल को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था ।

### उदयपुर

फरवरी, १९४१ में उदयपुर राज्य सरकार ने मेवाड़ प्रजामण्डल से प्रतिबन्ध उठा लिया था । परिणामतः प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को राज्य में "उत्तरदायी सरकार" की स्थापना की मांग करने का पुन अवसर प्राप्त हुआ । इसी मांग पर चल देने के लिए नवंबर, १९४१ में मालिखयलाल वर्मा के सभा पतित्व में प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया । जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई । इस अवसर पर एक छादी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन श्रीमती

निम्नलिखित परिणामों ने किया। इन सब घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार ने यह अनुभव कर लिया कि जब अधिक समय तक जनता की भावनाओं को नहीं दबाया जा सकता। यही कारण है कि राज्य सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया कि प्रतिनिधित्व की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमूल होना। साथ ही 'बटवाली बर' कायम लेने की भी घोषणा की गई।

### सत्याग्रह-आन्दोलन

८ अगस्त, १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ब्रिटिश भारत में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन आरम्भ किया। इसके साथ ही राजस्थान के विभिन्न राज्यों में भी 'उत्तरदायी सरकार' की स्थापना की मांग को लेकर सत्याग्रह आरम्भ हुआ। उदयपुर भी घेरना न रह गया। १० अगस्त, १९४२ को सत्याग्रह करने हुए अखिल भोजपुरी प्रदेश आन्दोलन को विराम कर दिया गया और देश भेज दिया गया। २० अगस्त, १९४२ को मेवाड़ प्रजामण्डल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें राज्य में गुरुत्वात्मक शासन की स्थापना और ब्रिटिश सरकार से सभी सबब तोड़ लेने की मांग की गई थी। इसके प्रत्युत्तर में राज्य ने दमन-नीति का सहारा लिया और २१ अगस्त, १९४२ को माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल मुखारिया, बलवन्तसिंह मेहता सहित १५ सत्याग्रहियों को विराम कर दिया गया। इसके साथ ही समूचे राज्य में सार्वजनिक सभा करना प्रबन्ध आगुलाना या प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई और प्रजामण्डल को 'गैर कानूनी समूह' घोषित कर दिया गया शीघ्र ही विराम कर व्यक्तियों की संख्या ५० तक पहुँच गई। यद्यपि कानूनभंग को ठण्डा करने के लिए कुछ समय बाद अनेक सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया जिनमें माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल मुखारिया, बलवन्तसिंह मेहता और मोहनलाल तेशावत सम्मिलित थे। ६ अक्टूबर, १९४५ को प्रजामण्डल से भी प्रतिबन्ध उठा लिया गया। यद्यपि सार्वजनिक सभाओं पर तथा आपत्तियों पर प्रतिबन्ध बना रहा। सरकार की दमनकारी नीति का परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ने सरकार की नीति के विरुद्ध हड़ताल कर दी। पुलिस ने भाड़ी चार्ज किया और अनेक व्यक्ति विराम कर दिए गए। बाद में राज्य सरकार ने इस घोरता पर, कि जनता की कठिनाइयों को शीघ्र दूर किया जाएगा हड़ताल वापिस ले ली गई।

## नैसर्गिक मुषार

इन परिस्थितियों में मार्च, १९४७ में राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर राजकाचार्य ने राज्य में अनेक सर्वजनिक मुषारों को लागू करने की घोषणा की। वास्तव में इन मुषारों की कोई उपयोगिता नहीं थी। क्योंकि इन मुषारों के माध्यम से राज्य के निरक्षर भाग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता था। फिर भी मेवाड़ प्रजापण्टस ने विधान सभा के चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया और काफी सीढ़ी पर चढ़ा करते हुए सिद्ध कर दिया कि उसे जनता का भारी सम्बन्ध प्राप्त है।

## बीकानेर

राजस्थान के अन्य राज्यों के समान ही बीकानेर में भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की लेकर आन्दोलन चल रहा था। राज्य ने दमनचक्र का सहारा लिया और सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं एवं भाषणा पर रोक लगा दी परन्तु राज्य की इस दमन नीति के फलस्वरूप आन्दोलन और तेज हो उठा। नवम्बर, १९४१ में द्वितीय महापुद्द में भाग लेने जाते समय महाराजा गंगासिंह ने कुछ मुषारों को लागू करने की घोषणा की थी परन्तु व्यवहार में इनका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, घन. २६ जुलाई, १९४२ को रघुवरसिंह गोयन के समागमत्व में बीकानेर प्रजा-परिषद् ने राज्य में 'उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की लेकर सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू किया। राज्य ने दमन चक्र को तेजी से घुमाना शुरू किया और रघुवरदास गोयन सहित अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन्हें राज्य से निष्काशित कर दिया, परन्तु २६ अगस्त, १९४४ को रघुवरदास गोयन ने अपने प्रथम साक्षियों गंगाधर कोत्रिठ तथा दीनदयाल आचार्य के साथ निष्काशन आदेश की अवहेलना करने हुए राज्य में प्रवेश किया। राज्य सरकार ने इन्हें पुन गिरफ्तार कर राज्य से निष्कात दिया; परन्तु इन सबके बावजूद राज्य में आन्दोलन जारी रहा। राज्य की दमनकारी नीति पर मान विचार प्रकट करते हुए ३० जनवरी १९४६ को प्रतिभ भार-तीय देशी राज्य परिषद् में भाषण देने हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बीकानेर राज्य अपने निरक्षर शासन के लिए कुख्यात हो चुका है जहाँ राज-नैतिक केंद्रों की हानत दृश्य है। मार्च, १९४६ में बीकानेर प्रेस अधिनियम पारित हुआ जिसने अन्दर प्रत्येक समाचार पत्र के लिए यह आवश्यक था कि

यह सब से पूर्व राज्य को अमान्य है कि यह राज्य विशेषी अनिवार्यताओं से सम्बन्धित नहीं होगा। आदेश से यह भी कहा गया कि कोई भी और बीजानेरी व्यक्ति तथावार यह को सम्पादन नहीं बन सकेगा। इसी बीच राज्य सरकार के द्वारा आदेशकर विधेयक लागू किया गया जिसके अनुसार 'यदि कोई भी नागरिक बीजानेरी राज्य की भोजन है १२० दिन निवास करता है तो उसे बांध कर देना होता है।' इस धर्मनिरपेक्ष का सीधे विरोध किया गया। २२ मार्च, १९४६ को सफूचे राज्य में हुइगुन आयोजित की गई जिसने राज्य विधान सभा में बांधकर विधेयक पर विचार करना स्पष्ट कर दिया और हुइगुन की पारित से भी गई।

### विमान-आन्दोलन

मई, १९४६ में राज्य की दमनशीलता का विरोध करते हुए राज्य के किसानों ने अवैध प्रदर्शन किया। इस बार राज्य ने और भी बड़ी दमन-शक्त का सहारा लिया। कुमाराय चार्ज सहित अन्य विमान विमानार कर लिए गए। १० मई, १९४६ को पुलिस ने राजाई नामक गांव की घेरे किया और वहां के आन्निपूर्ण नागरिकों पर सभी प्रकार के भयंकर आवाचार किए। सरकार की इस दमन-नीति की न केवल बीजानेरी राज्य में बल्कि बन-कता, बम्बई और जयपुर तक में बढ़ आलोचना हुई। ३० जून और १ जुलाई, १९४६ को रायसिंह नगर में देशी राज्य परिषद् का अधिवेशन आयोजित हुआ, जहाँ १ जुलाई, १९४६ को जब परिषद् का एक कार्यकारी समिति में बैठने के लिए स्टेसन आ रहा था तो किता किमी कारण से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने आन्दोलन की उत्पत्ति बना दिया। पुलिस की इस दमनकारी नीति का जनता ने अवैध विरोध किया। जन-विरोध के बुझने के लिए राज्य में बढ़ने लाली चार्ज और बाद में पोली का सहारा लिया। यद्यपि कि सेवा भी बुना ली गई। परिणामतः औरतल सिंह (जो कि एक हरि जन कार्यकर्ता था) सहित ४ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए। १७ जुलाई, १९४६ को सफूचे राज्य में औरतल दिन मनाया गया और यह मौन की गई कि तमिल राजनीतिक कर्दियों को गिरा कर दिया जाए और 'रायसिंह नगर' होनी राज्य की आवाज बसाई जाए। अन्ततः ३१ अगस्त, १९४६ को महाराजा गार्डन मिड की इस घोषणा पर कि 'राज्य में बीजानेरी आन्दोलन की स्थिति की जांच' राज्य का तनावपूर्ण आवाज ली गया हो गया।

## भरतपुर

भरतपुर में आन्दोलन का आरम्भ सन् १९४० में उस समय हुआ जब राज्य के प्रधानमंत्री सर रिचर्ड टेटनहोड ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराना गैर कानूनी घोषित कर दिया। साथ राज्यों के समान ही भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रभाव भरतपुर पर भी पड़ा और वहाँ भी १० अगस्त, १९४२ को उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर आन्दोलन सीढ़ी हो उठा। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता जुगलकिशोर चतुर्वेदी मास्टर आदित्यदेव देवराज पंडित देवतीशरण ठाकुर श्रीवास्तव रमेश स्वामी राजबहादुर और मास्टर गोपीनाथ यादव थे। आन्दोलन के दौरान विदेशी शराब की दुकानों पर घना किया गया और विदेशी वस्त्रों की होनी जलाई गई। यहाँ तक कि अनेक स्थानों ने गोद में बच्चे लिए हुए अपने घरों की गिरफ्तारी के लिए पेश किया। आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए महाराजा भरतपुर ने १९४३ में कुछ जमा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की और उसी की परम्परा भरतपुर प्रजापण्डित ने उस समय तक किसी भी प्रकार का सहयोग देना बन्द कर दिया जबतक जनता की सच्ची प्रतिनिधि सभा की स्थापना नहीं की जाती। प्रभुत्तर में राज्य में दमनकारी नीति का सहारा लिया और आन्दोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। १ अगस्त १९४५ को आन्दोलन के प्रमुख नेता जुगलकिशोर चतुर्वेदी को एक वर्ष की कारावास और २२० रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। २४ सितम्बर १९४५ को एक सामाजिक सभा में भाषण देते हुए राजबहादुर ने महाराजा भरतपुर से अनुरोध किया कि उन्हें जनता की मांग स्वीकार कर वेनी चाहिए और उत्तरदायी शासन की तुरंत स्थापना करनी चाहिए। सन् १९४६ में बसंत दरबार के अवसर पर महाराजा भरतपुर ने लोकप्रिय मंत्रिमण्डल की पेशकश किए जाने की घोषणा की परन्तु प्रजापरिषद् राज्य की मुस्लिम शीख भाता और किसान सभा ने राज्य के साथ उस समय तक सहयोग से बन्द कर दिया जबतक कि राज्य में प्रत्यक्ष मत के आधार पर निर्वाचित उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं कर दी जाती। अपनी मांगों पर बल देने के लिए प्रजा परिषद् ने राजबहादुर वकील और देवतीशरण के नेतृत्व में ४ फरवरी १९४७ को राष्ट्रीय नारे लगाते हुए जाने भण्डों का प्रदर्शन किया।

अगस्त १९४७ में भरतपुर राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए



घोर १३ सितम्बर, १९४७ को महाराजा भरतपुर के आदेश के अन्तर्गत देवनी-शरण और जुगलकिशोर सहित सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया।

अन्तर्वर :

मार्च १९४० में अन्तर्वर राज्य के द्वारा अन्तर्वर प्रशासन को साम्यता प्रदान कर दो गई थी परन्तु भूमि के मामले को लेकर दोनों ही पक्षों में मतभेद उत्पन्न हो गए और २ जून, १९४१ को प्रजामण्डल के द्वारा 'जागीर माफी प्रजा परिषद्' का आयोजन किया गया जिसमें किसानों को भू-स्वामित्व दिए जाने की मांग की गई। साथ ही यह भी मांग की गई कि जागीरदारों के द्वारा ली जाने वाली बेमर समायोजन की जाए और जमीन का जोतने वाला ही जमीन का मालिक समझा जाए। अन्तर्वर पक्षों के अग्रजों में किसानों ने राज्य के अनेक स्थानों पर प्रदर्शन भी किया परन्तु राज्य की दमनकारी नीति के सम्मुख कुछ समय के लिए यह आन्दोलन स्थगित हो गया। परन्तु फरवरी १९४६ में प्रजामण्डल के द्वारा एक बार फिर 'उत्तरदायी शासन' की स्थापना की मांग को लेकर आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। गोभाराय, रामगोलाल, कुज-बिहारीलाल और हरिनारायण सहित अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर, १९४७ में रायपुर के अन्तर्वर पर महाराजा अन्तर्वर ने राज्य प्रशासनिक परिषद् में ३ निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित करने की घोषणा की परन्तु राज्य की अन्तर्वर इस नाममात्र के सुधार से संतुष्ट नहीं हो सकी। बाद में अन्तर्वर राज्य भारतीय मध्य में सम्मिलित हो गया और सभी राज-नीतिक बन्धियों को रिहा कर दिया गया।

कोटा :

अन्य राज्यों के समान कोटा में भी 'उत्तरदायी सरकार' की मांग की जाने लगी। २६ जनवरी, १९४१ को 'उत्तरदायी सरकार' दिवस मनाया गया जिसमें राज्य प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि वह जनता की मांग को तुरन्त स्वीकार करके संसदीय शासन की स्थापना करे। नवम्बर, १९४१ में बिगडती स्थिति को समाप्त करने के लिए महाराज कोटा ने कुछ सर्वजनिक सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों के अन्तर्गत एक सचिवालय का निर्माण किया जाना था और एक विधान परिषद् भी स्थापित की जानी थी। परन्तु राज्य प्रशासन ने इन सर्वजनिक सुधारों के साथ सहयोग करने से इस्तिफा

इन्कार कर दिया क्योंकि इनके माध्यम से नागरिकों को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया था।

अगस्त, १९४२ में "भारत छोड़ो आंदोलन" के दौरान ब्रिज-मण्डल ने भी उत्तरदायी शासन की मांग की लेकर सत्याग्रह प्रारंभ किया। समूचे राज्य में हड़ताल की गई और घरना दिया जाने लगा। राज्य की दमनकारी नीति के फलस्वरूप निरक्षर लोगों को सड़क हड़तों तक पहुँच गई। जन उमड़े-उमड़ा इनकी ध्वजक बड़ी कि नागरिकों ने शहर के दरवाजे बंद कर दिए और पुनिम कोनवाली में भूँडे फहराकर नागरिक शासन अपने हाथ में ले लिया। लगभग ३ दिन तक यही स्थिति रही। बाद में महाराज के इस आश्वासन पर कि वे जनता की मांगों पर विचार करेंगे और पुनिम दमनकारी नीति का सहाय नहीं लेगी, शहर के दरवाजे खोल दिए गए। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय भूँडे की पुनिम व सेना ने मिलकर सत्सामी की और सभी नागरिकों ने राज्य प्रशासन अधिकारियों को मीठा, परंतु शीघ्र ही राज्य ने अपने आशासनों का उल्लंघन किया और दमनकक धुमाना शुरू किया। क्यामनागदल सक्मेना सहित अनेक कार्यकर्ता पुनिम की दमनकारी नीति के शिकार बने। पुनिम जुलूम के विरोध में क्यामनारायण ने धूम हड़ताल प्रारंभ की। अतः महाराज के इस आश्वासन पर कि वे राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए शीघ्र ही बदल उठाएंगे, सत्याग्रह आरोपित कर दिया गया।

### जोधपुर

जोधपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की लेकर प्रारंभ होने वाला धारोवन जत्रारायण व्यास के नेतृत्व में १९४० में प्रारंभ हुआ था। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यह केवल शहर तक ही सीमित नहीं था बरिंतु ग्रामीण जनता ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। जोधपुर के गांवों में जागीरदारों के जुल्मों की बहानी ध्वजस्मरणीय है। वास्तविकता यह थी कि एक किसान को सैकड़ों तरह की धानबाग देनी पड़ती थी, जैसे कासासाग, लटाईलाग आदि। इस प्रकार एक सामान्य किसान ने लिए मुद्दे से शायद तक कार्य करने के पश्चात् भी अस्पष्ट भोजन करना मुश्किल हो गया था। मारवाड़ लोक परिषद् ने धारोवन जनता की इन कठिनाइयों की ओर राज्य सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित किया, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। अंत में जागीर-दारों के अत्याचार बढ़ते गए और उन्हें सरकार का समर्थन मिलता रहा।

इन परिस्थितियों में मारवाड लोक परिषद् ने जब मारवाड ब्याम और उनके सहयोगी कचनेयकरप्रसाद, पुष्पोत्तमप्रसाद, किंगोरीनान मेहता, प्रनमन जैन, गो० भार० चौधरीजीकता और गणेशनाथ ब्याम के नेतृत्व में मादोन शरद किया। इन कार्यकर्ताओं को भीड़ ही मारवाड पार्टी में एक्ट १९३२ के धर्मांत २६ मार्च, १९४० को विरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जोधपुर राज्य में सभी स्थानों पर पण्डित और उनकी शाखाओं को बंद काजूनी घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार ने मादोन को कुचलने की दृष्टि से समूचे राज्य में धारा १४४ लागू करके सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी परन्तु इन सबके बावजूद मादोन की कुचला नहीं जा सका। सब मादोन का नेतृत्व मयुरादास मायूर ने संभाला। १ अप्रैल, १९४० को जब मयुरादासों का जुलूम निकाला जा रहा था तो भीजाना रिषापुरीन, भाई परमानन्द, हुकमराज मेहता, वृद्धिबद जोशी को विरफ्तार कर लिया गया। ३ अप्रैल, १९४० को जब मयुरादास मायूर लगभग १००० नागरिकों के जुलूम का नेतृत्व कर रहे थे तब उन्हें भी विरफ्तार काके एक वर्ष के लिए परबतपुर में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज प्रतिदिन की कहानी बन गई। यही तक कि विद्यार्थी पण्डित के अध्यक्ष साराप्रसाद को भी विरफ्तार कर लिया गया; यद्यपि २६ अप्रैल, १९४० को विशेष न्यायमय ने उन्हें रिहा कर दिया। पुलिस जुलूम की जाच की हर घोर से माच की जाने लगी। जून, १९४० में देशी राज्य परिषद् के अध्यक्ष प० जवाहरलाल मेहता ने जोधपुर की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दारकानाथ कचर को जोधपुर भेजा। राज्य सरकार ने उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया। कचर ने अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि राज्य का राजनीतिक शासनबल दमघोड़ था और एक दारकानाथ तक का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। अतः जून, ४० में राज्य सरकार और मारवाड लोक परिषद् के मध्य एक समझौता हुआ जिसके धर्मांत राज्य ने परिषद् की मांगना प्रदान की और सभी विरफ्तार राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया।

६ करवरी, १९४२ को मारवाड लोक परिषद् का जुला अधिवेशन लाडनू में सम्पन्न हुआ। समापति पद से भावसु देते हुए एण्थोडदास गड्डानी ने सरकार से मांग की कि वह बेमार-शवा को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करे। परिषद् ने २८ मार्च, १९४२ को उत्तरदायी शासन-दिवस मनाने का भी निश्चय किया। परन्तु बंदाबन (मारवाड) के ठिकानेदारों ने

लोक परिषद् को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की अनुमति नहीं थी और राज्य पुलिस की सहायता से नागरिकों पर साठिया बरसाई गई। राज्य सरकार ने सत्याग्रहियों की सहायता करने के स्थान पर १८ अप्रैल, १९४२ को एक माह के लिए धारा १४४ लगाकर सभी सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी। इन परिस्थितियों में लोक परिषद् के समुख इसके प्रतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था कि वह सत्याग्रह का सहारा ले। परिषद् ने निश्चय किया कि जयनारायण व्यास जो अभी हाल में ही जेल से आए थे, के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रादोलन प्रारम्भ किया जाए। प्रादोलन प्रारम्भ करने से पूर्व जयनारायण व्यास ने जोधपुर महाराज से मेट करना चाहा परन्तु उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया। इसी बीच राज्य की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए "भारवाड में उत्तरदायी शासन" और "जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश" नामक दो पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। इन प्रकाशन ने जोधपुर महाराजा को उत्तेजित कर दिया और उन्होंने जयनारायण व्यास को बतावनी दी कि इसके गभीर परिणाम होंगे। प्रत्युत्तर में २६ मई को जयनारायण व्यास और उनके साथियों ने राज्य की दमनकारी नीति के विरोध में जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

### जोधपुर में दमन-चक्र

इसके साथ ही २७ मई, १९४२ को जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर तो गिरफ्तारियों का ताता ही लग गया। मयुरादास माधुद, प्रबलेश्वर प्रसाद शर्मा, छगनलाल चौगसनीवाला, गणेशलाल व्यास और अभयमल जैन को भी जेल ही गिरफ्तार कर लिया गया। स्थिति की गभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद् ने स्थायी समिति के सदस्य बम्हयालाल बीछ का स्थिति का अध्ययन करने के लिए जोधपुर भेजा परन्तु राज्य सरकार ने उन्हें तुरन्त राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया और एक वर्ष के लिए उनके राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी। राज्य की इस दमन-नीति की जवाहरलाल नेहरू, हरिभाऊ उपाय्याय, हीरालाल शास्त्री, मास्टर भोनानाथ, मोकुन भाई मट्ट, मुकुटबिहारीलाल भार्गव और सत्यदेव विशालवार ने कटु आलोचना की।

### बालमुकंद जिसस की मृत्यु

रखी ॥ ११ जून, १९४२ को बालमुकंद जिसस सहित लोक परिषद्

के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को निरपहार कर दिया गया। उनके साथ जेल में बहुत बुरा व्यवहार किया गया और दूसरे दिन मध्याह्न १॥ बजे तक भोजन भी नहीं दिया गया, इस दुर्व्यवहार के विरोध में सत्याग्रहियों ने भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी। सत्याग्रहियों की मांग थी कि उन्हें उनकी निरपहारी के कारण बठाए जाएं परन्तु राज्य सरकार न ४ दिन बाद यह सूचित किया कि वे अभियुक्तों से भी गए बीते हैं और उनके साथ बैसा ही (अभियुक्तों जैसा) व्यवहार होगा। १२ जून, १९४२ को जबरदस्ती से भीर भीषण गर्मी के कारण सत्याग्रहियों ने जेल अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें कुले में सोने की अनुमति दी जाए परन्तु उनके इस मावेदन को ठुकरा दिया गया और जब सत्याग्रहियों ने बेरक में जाने से इकार कर दिया तो जेल अधिकारियों ने कैदियों से उनकी पिटाई करवाई, तदुपरान्त पुलिस की सहायता से उन्हें गहरी नींद लाने के लिए बेरक में फेंक दिया। इस घटना में बालमुकद बीस्ता और रणछोहरदास गढ़ानी सहित प्रत्येक व्यक्तियों के गंभीर चोटें पड़ीं। बालमुकद बीस्ता को इतनी चोट लगी कि वह बीमार पड़ गया परन्तु उसकी भीर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब १६ जून को उसे १०३ डिग्री बुझार हो गया तो अधिकारियों ने उसे अस्पताल भेजने का विचार किया। बालमुकद को उनके बूढ़े माता-पिता और उनकी पत्नी तथा बच्चों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस गंभीर हालत में जब बालमुकद बीस्ता को बेहोशी की हालत में विष्टम अस्पताल भेजा गया तो बीड़ी देर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने समूचे शहर को उत्तेजित कर दिया। पुलिस ने रात रात पर प्रतिबन्ध लगा दिया और भीड़ को छिन्न-खिन्न करने के लिए लाठी चार्ज किया। महाराजा की दस बमनकारी नीति की समूचे शहर में प्रतीति हुई। महारजा शाही ने भी प्रार्थना व्यक्त की कि महाराजा घटना से सबक लेंगे और राज्य में शीघ्र ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। इस युग की महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि जोधपुर की राजनीति में पहली बार स्त्रियों ने केसरिया साड़ी पहन कर शहर में घटाघर के समीप सत्याग्रह किया। श्रीमती महिमादेवी किकर के नेतृत्व में १७ जुलाई, १९४२ को प्रदर्शन भी किया गया। २६ जुलाई को समूचे राज्यभर में 'मारवाड़ सत्याग्रह' दिवस मनाया गया और स्थान-स्थान पर सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गईं।

जब सत्याग्रह आन्दोलन जोधपुर के समीपस्थ जिने जैध फलोदी, सोमठ और नाबौर में भी फैलने लगा तथा बड़ी संख्या में व्यक्तियों को

गिरफ्तार किया गया। इसी बीच ४ अगस्त, १९४२ को जयनारायण व्यास को ६ वर्ष ६ महीने, मधुरादास भापुर को २ वर्ष ६ महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। समूच भारत में जोधपुर न्यायालय ने इन निर्णय की कटु-प्रालोचना हुई। अन्त में १९४४ में वातावरण को शांत करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने जयनारायण व्यास और उनके सहयोगियों को रिहा किया। १९४५ में राज्य सरकार ने कुछ सर्वेधानिक सुधारों को लागू करने की घोषणा की। एक प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की गई जिसमें ६९ सदस्य होने थे, जिनमें से अधिकांश जनता द्वारा निर्वाचित किए जाने थे। इस प्रकार इन सर्वेधानिक सुधारों की घोषणा के साथ ही साथ राज्य का राजनीतिक वातावरण कुछ शांत बना परन्तु जागीरदारों के जुलूम अभी भी अदम्य बल हुए थे, मग चक्रवर्त १९४६ में 'सारवाइ लोह परिषद्' में जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारम्भ किया। होशियार दिन में डादरा नामक स्थान पर १९४७ में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया परन्तु जागीरदारों ■ सहयोग से राज्य पुलिस ने अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें राधाशिवन, डागडादाम पुरोहित, मधुरादास भापुर सम्मिलित थे। इन व्यक्तियों पर राज्य विरोधी कार्यवाही करने का आरोप लगाया गया परन्तु जब कुछ समय बाद जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लोकप्रिय मन्त्रि मण्डल की स्थापना हुई तो सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हो गया और गिरफ्तार सत्याग्रहियों की रिहा करके उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमे वापिस ले लिए गए।

**जैसलमेर —**

राजस्थान की देशी रियासतों में जैसलमेर की वर्तमान निकोदार के नाम से पुकारा जाता था। कारण यह था कि यह राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी जहाँ पर राजनीतिक चेतना का आरम्भ काफी देर से हुआ। सागरमन गीरा और नारायणदास भाटिया पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य के तानाशाही शासन के विरुद्ध जन जागृति करने में योगदान दिया। जैसलमेर के इतिहास में पहली बार १६ नवम्बर, १९३० को जवाहर दिसल मनाया गया। सागरमन गीरा और सहयोगी इन्दन पुरोहित और रघुनाथ सिंह मेहता को भीष्म ही गिरफ्तार कर लिया गया, मन्त्रि प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण उन्हें ३६ घंटे बाद ही रिहा कर दिया गया। सत्याग्रह सागरमन गीरा भागपुर चले गए और वहीं से जैसलमेर के निरक्षर शासन के विरुद्ध

मेन लिखते हैं : १९३२ में रघुनाथसिंह मेहता ने महेष्वासी गुप्त गण्डप की स्थापना की जिससे कि जनता में राजनीतिक चेतना जागृत हो जा सके परन्तु रघुनाथसिंह मेहता की सीमा ही गिरणार करने २ वर्ष ६ माह के कारावास की सजा दी गई । राज्य की इस दमनकारी नीति ने समूचे राज्य में उत्तेजना पूर्ण आन्दोलन पैदा दिया । एक माह बाद रघुनाथसिंह मेहता को रिहा कर दिया गया और वे मद्रास में जाकर बस गए ।

जैसलमेर में प्रजा परिषद् की स्थापना

इस समय जैसलमेर के लिए राजनीतिक चेतना का कार्य नागपुर से सागरमल गोवा महाम में रघुनाथसिंह मेहता और जैसलमेर में शिवशंकर गोवा तथा तिनच में केशवदास व्यास और रामचन्द्र जेयसिंघा बन रहे थे । राज्य की दमन-नीति के बावजूद १९३६ में शिवशंकर गोवा ने राज्य में प्रजा परिषद् की स्थापना कर दी । परन्तु इसका परिणाम उन्हें सीमा ही भुगतना पड़ा, राज्य ने उन्हें निष्काशित कर दिया और वे भी अपनी भाई सागरमल गोवा के पास नागपुर चले गए ।

सागरमल गोवा की गिरफ्तारी

मार्च १९४१ में सागरमल गोवा के पिता की मृत्यु हो गई घत सागरमल गोवा ने ब्रिटिश रेजिडेंट से प्रार्थना की कि यह उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान करें । रेजिडेंट की इस सूचना पर कि उनके विरुद्ध में कोई मामला विचारणीय नहीं है २२ मई १९४१ को सागरमल गोवा जैसलमेर पहुँचे परन्तु जब वे निवृत्त होने के लिए बाहर जा रहे थे तभी पुलिस सब इन्स्पेक्टर गुमानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । सागरमल गोवा की कड़ीर माननाई दी गई और बाद में उन पर राज्य-विरोधी भाषण देने का आरोप लगाकर ९ वर्ष के कारावास का दण्ड दे दिया गया । इस अवधि में भी जेल में सागरमल गोवा के साथ अचञ्चलीय दुर्व्यवहार किया गया । सागरमल गोवा ने इस दुर्व्यवहार के प्रति जयनारायण व्यास और अखिल भारतीय देशी राजदूत परिषद् के उपाध्यक्ष जेम्स ब्रिड्जस को तथा सिन्धु से प्रकट कराया जिससे राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की । २ मई, १९४६ को सागरमल गोवा ने जिला जज के पास भी उन पर किए जा रहे पुलिस दलान-चारों के विरुद्ध प्रार्थनापत्र भेजा परन्तु पुलिस सब इन्स्पेक्टर गुमानसिंह ने रास्ते में ही उसे जम कर लिया और सागरमल गोवा को तभीर परिणाम भुगतने

की चेतावनी दी। दूसरे ही दिन यर्नान् ६ अप्रैल, १९४६ को यह समाचार मिला कि सागरमल गोपा ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उन्हें शीघ्र ही अस्पताल ले जाया गया जहाँ ४ अप्रैल, १९४६ को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने समूचे भारत में तहलका मचा दिया। जवाहरलाल नेहरू और 'नेतृनायक' जयनारायण व्यास ने सरकार की दमनकारी नीति की कटु आलोचना की और सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए एक कमीशन को नियुक्त करने की मांग की। २७ अगस्त १९४६ का श्रीगोपायस्वरूप पाठक (वर्तमान में भारत के उप राष्ट्रपति) को एक सम्स्थीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया जिन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि सागरमल गोपा ने पुनिम प्रस्थाचारों के डर से अपना पुनिम द्वारा दी गई यातनाओं से परेशान होकर आत्महत्या की है।

### प्रजामण्डल की गतिविधियाँ

इसी बीच १३ दिसम्बर १९४३ को बीठावाल स्थान ने सचप से बचने के लिए जोड़पुर में जैमनमेर प्रजामण्डल की स्थापना कर ली थी। सागरमल गोपा के इतिहास ने प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं में एक नए साहस का संचार किया। इसीलिए २६ मई १९४६ को बीठावाल व्यास जयनारायण व्यास और उनके साथियों ने जसमेर की राज्य-सीमा में प्रवेश किया। २७ मई १९४६ को जयनारायण व्यास ने जैमनमेर भूमि पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया जिसका जनता ने इत्साव जिन्दाबाद और 'प्रजामण्डल जिन्दाबाद' के नारों से स्वागत किया।

### राजस्थान में देशी रियासतों का विलोनीकरण

इन १९४७ में ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता सौंपने का निर्णय किया। तदनुसार १३ अगस्त १९४७ को भारत ने अपने स्वायत्त और इतिहास का पुरस्कार स्वाधीनता के रूप में प्राप्त किया। स्वतंत्र भारत की सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी गंभीर समस्या देशी राज्यों के एकीकरण की थी। भारत के तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा भारत सरकार के गृह सचिव श्री बी पी मेनन के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारत के अधिकांश देशी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निणय किया। जहाँ तक राजगुजाना के राज्यों के एकीकरण का संबंध है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण ५ चरणों में पूरा हुआ।



प्रथम चरण में बनारस, भरतपुर, धौलपुर और बगौली को मिलाकर २० जून १९४६ को मातृसूचिक का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में बागपडा, बूंदी, हृदयपुर, भासाबाद, किशनगढ़, बोट, प्रतापगढ़ नाटपुरा और टोंक को मिलाकर २५ मार्च, १९४८ को प्रथम राजस्थान सूचिक का निर्माण किया गया। तृतीय चरण में १ अप्रैल, १९४६ को प्रथम राजस्थान सूचिक में हृदयपुर सम्मिलित हुआ। चौथे चरण में बृहत् राजस्थान का निर्माण हुआ। जिसमें जयपुर, जोरपुर, बीकानेर और जैतपुर की रिमाइन्स सम्मिलित हुई। पांचवें और अंतिम चरण में ३० मार्च, १९४६ को मातृसूचिक का विभाग बृहत् राजस्थान में होकर सम्पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ।

इस प्रकार विभिन्न राज्यों में प्रजासङ्घ, प्रजा परिषद् और किसान समा हत्यादि की स्थापना ने नागरिकों में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान राजस्थान की जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बने और इस प्रकार देशी राज्यों की जनता का एक सम्मानपूर्ण समस्त एकता के साथ सम्बन्धित हुआ।

## उपसंहार

१२ वीं और १३ वीं शताब्दी में मध्ययुगीन—राजस्थान में मुस्लिम शासन का सूत्रपात हुआ, तत्पश्चात् मुगलों का शासन स्थापित हुआ था परन्तु १७०७ में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मराठा और पेशवियों ने जी भरकर राजस्थान को लूटा था। राजे और महाराजे असहाय दिखाई देते थे। इन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक शून्यता की स्थिति को भरने के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। १८०३ से १८१८ तक लगभग राजस्थान के सभी राज्यों ने ब्रिटेन के साथ संधिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इस तरह अब वे अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे थे।

परन्तु शीघ्र ही रीति रिवाज और परम्पराओं को लेकर राजाओं और उनके जागीरदारों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होने लगा जिसके परिणामस्वरूप राजा की शक्ति को चुनौती दी जाने लगी। इसी बीच १८५७ का विप्लव प्रारंभ हुआ। राजस्थान में यह विद्रोह सैनिक छावनियों-नबीराबाद नौमच और देवली तक सीमित था। यद्यपि भागते हुए विप्लवकारियों ने जयपुर, जोधपुर, टोंक, मारवाड़ और मेवाड़ की प्रादेशिक सीमाओं में प्रवेश किया और वहाँ के राजाओं पर जनता से सहयोग लेने की प्रसन्न चेष्टा की। परन्तु पक्षपात जनता उदासीन रही। राजा के अमलानुष्ठ ठाकुर ने अवश्य स्थिति में लाभ उठाने का प्रयत्न किया। कोठारिया और सनुम्बर के जागीरदारों का दृष्टिकोण भी सहानुभूतिपूर्ण था परन्तु ब्रिटिश दमन-चक्र के सम्मुख विप्लवकारियों को

समर्पण करना पड़ा। १८६१ से १८८५ तक देशी राज्यों में भी ब्रिटिश भारत के सुधार लागू किए गए जिसके परिणामस्वरूप देशी राज्यों की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति में आकाशीय प्रगति हुई। १६ वीं जगन्नी के उत्तरार्द्ध में अनेक धर्म सुधार-घान्दोलन हुए जिनमें भार्य समाज ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा स्वदेशी स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य की प्राप्ति पर सर्वाधिक बल दिया गया जिससे राजस्थान में नई राजनीतिक चेतना की जन्म दिया। इसी समय समाचार-पत्रों और विभिन्न मासिक के प्रकाशनों ने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जतवती की।

१८८५ में प्रचलित भारतीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में भारत को राष्ट्रवाद की एक नया रसमच प्राप्त हुआ। १८१९-२७ में लेफ्टीनेंट गेनर और आर्चबिशप की हत्या के साथ ही साथ भारतीय राजनीति में उस राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ, जो १९१६ तक भारतीय राजनीति में छाया रहा। १९०५ के बंगाल-विभाजन और इस युग की अनेक घातकवादी घटनाओं ने प्रभाव से राज-स्थान भी झटका न रह सका। व्यापारी कृष्ण वर्मा, धनंजयलाल सेठी, बैसरी-सिंह बरेल्ल, राव गोपालसिंह राणा और अन्य नालिकारियों ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए तन, मन, धन से योग दिया। इसी युग में विजोमिया, देहू, मुंदी और शिरोही में किसान आन्दोलन भड़क उठा। जागीरदारों के नृसम व्यवहार, बेगार और साम्राज्य के विरुद्ध राजस्थान के किसानों ने विजयसिंह 'पथिक' के नेतृत्व में सफलतापूर्वक टक्कर ली।

इस युग की एक महत्त्वपूर्ण घटना यह भी थी कि राजस्थान के भीलों ने ब्रिटेन के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। जनगणना और भू-राजस्व सम्बन्धी सुधारों ने भीलों की प्राचीन परम्पराओं का उत्पन्न किया जो अत के भी ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से घीनप्रोत थे। यही कारण था कि १८८१-८२ में और बाद में १९२४ में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन किया। निषेध राज्य की दमनकारी नीति व मोतीलाल तेजावत की निरफ्तारी के परिणामस्वरूप भील आन्दोलन कुचल दिया गया परन्तु इस आन्दोलन ने भीलों के हृदय में जो स्वतन्त्रता की वयोति अगाई और उन्हें अधिवार व वसंधों का ज्ञान कराया वह कभी नहीं मिटाया जा सका।

१९१४ में प्रथम महायुद्ध आनू हुआ। राजा व महाराजाओं ने अपने

निराश्रित आगमन की जाए रखने की दृष्टि में ब्रिटेन की दूर मध्य महागंगा की घोर ब्रिटेन की विजय की घाती विजय समझी। १९१६ के पश्चात् भारत की सर्वजनिक समस्या का समाधान निकालने के लिए मण्टेग्यू बेन्टिन्सों मुबार लायू किया गया परन्तु अब इसका कोई मकान परिणाम नहीं निकला तो १९२१-२२ में महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन का श्रीगणेश किया। राजस्थान में भी अपना भरपूर योगदान दिया। महात्मा गांधी के आन्दोलन में प्रभावित होकर बूंदी, दिग्विजया, वेणू भरतपुर, सिरोही और धारपुर में अनेक आन्दोलन हुए तथा अनेक स्थानीय समस्याओं का जन्म हुआ जिसमें मारवाड़ हितवागिणी सभा, राजस्थान मेवक संघ और देवी राज्य परिषद् प्रमुख थे। इन समस्याओं ने नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों के लिए जनक आन्दोलन किए।

१९३० में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन में राजस्थान में भी सहभागिता ली गई। अजमेर, जोधपुर, जयपुर बीकानेर उदयपुर और भरतपुर राज्य के नागरिकों ने उत्तरदायी भावना की पुष्टि कर दी। परिणामस्वरूप राजस्थान के विभिन्न राज्यों में प्रजासङ्घन की स्थापना हुई। प्रत्युत्तर में राज्य सरकारों ने दमनक का सहारा लिये परन्तु अब जनता में आहूत जागृता हो चुका था। यहाँ तक कि बीकानेर महागंगा के किछड़ लुके पत्र विनश्वित किए गए। भरतपुर में यदि बात महात्मा का आन्दोलन शुरू हुआ तो येवाड़ में दिग्विजया आन्दोलन और जयपुर बीकानेर मनभेदों ने आलावरण को अत्यन्त गर्म बना दिया। सभी राज्य सरकारों ने प्रजासङ्घनों की सर्वेध घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप आन्दोलन और तीव्र हुआ। इन समय राजस्थान में २ दल कार्य कर रहे थे जिनमें से एक का नेतृत्व विजयसिंह पटेल, धनुंनवान सेठी और बाबा गृन्निह-राम कर रहे थे तो दूसरा दल जयनारायण बजाज हरिभाऊ तगाध्याय और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में कार्यरत था परन्तु दुर्भाग्य से इनके प्राथमिक मन-भेदों के परिणामस्वरूप ये दोनों दल भिन्नकर कार्य नहीं कर सके। कुछ समय पश्चात् जब इन दोनों के प्राथमिक भेद दूर हुए तो जयनारायण व्यास, मालिक्यलाल वर्मा जयनारायण बजाज हीरालाल शास्त्री, पण्डित भोजनाराय, सुगतकिशोर चतुर्वेदी, स्वामी गोपालदास और गुजराम मर्गाक इत्यादि ने मिलकर राजस्थान के सभी राज्यों में उत्तरदायी भावना की स्थापना कर दिया गया आन्दोलन का नेतृत्व किया। १९३१-३२ में जब उत्तर भारत में

एक बार घातक की लहर पुनः उमड़ी तो राजस्थान भी इसकी चपेट में आया । इन बार १० ज्वालाप्रसाद शर्मा के नेतृत्व में धनमेरु घातकवादी गतिविधियों का नेत्र बना । बाद में ज्वालाप्रसाद की गिरफ्तारी के पश्चात् यह आन्दोलन शिथिल पड़ गया ।

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ । इस बार भी देशी राजाओं ने तन-मन पन से ब्रिटेन की सहायता की परन्तु १९४० में जयनारायण व्यास और मधुरादास माधुर के नेतृत्व में जब मारवाड़ लोक परिषद् ने उत्तरदायी शासन की मांग की लेकर बीकानेर में आन्दोलन आरम्भ किया तो राज्य के अन्य भागों में भी उसकी पंथीर प्रतिक्रिया हुई यथा जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, तिरौटी, कोटा और झुनपुर राज्यों में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग में जोर पड़ा । जयपुर में जयनारायण व्यास बीकानेर में जयनारायण व्यास और उदयपुर में माणिक्यमान वर्मा की गिरफ्तारी ने समूचे भारत का ध्यान आकर्षित किया और राज्यों में व्याप्त किरहुज शासन की सभी जगह चरसंग हुई । यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में स्वतन्त्रतावादी गुप्तार भागू किए गए । इस मर्म में जैसलमेर में सागरमल गोपा के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता । जैसलमेर में राजस्थान की यह पिछड़ी रियासत भी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का आठवाँ आश्चर्य कहा था, सागरमल गोपा के बलिदान ने इस पिछड़ी रियासत की जनता में भी राजनीतिक चेतना का संचार किया ।

८ अगस्त, १९४२ को 'भारत छोड़ो' आन्दोलन आरम्भ हुआ । राजस्थान में भी जन्य से कठ्ठा विभाकर घपना मोमदान दिया । राज्य सरकारों के द्वारा आन्दोलनों को कुचलने के लिए हर समय प्रयत्न किए गए परन्तु अन्त में जनता की जीत हुई । १५ अगस्त, १९४७ को जब उषा की लाली ने भारत के झाल पर स्वाधीनता का तिलक किया तो राजस्थान की रियासतों ने भी भारतीय सभ के साथ ही घपना आशी जीवन सम्मिलित कर दिया । इस प्रकार एक सम्ये समय, स्थान और बलिदान के पश्चात् राजस्थान की जन-आकांक्षाओं की पूर्ति हुई और भारत के अन्य राज्यों के समान ही राजस्थान में भी लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल पदार्थ हुआ ।